सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

NSO INDIA
Data for Development

वार्षिक रिपोर्ट

2023-24

www.mospi.gov.in @GoIStats

विषयसूची

क्रम सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1	प्रस्तावना	01
2	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी)	06
3	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय	07
4	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)	33
5	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	45
6	अवसंरचना एवं परियोजना निगरानी	49
7	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	52
8	प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण	63
9	संगणक केंद्र	67
10	नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग (पीआईएमडी)	71
11	संयुक्त राष्ट्र में भारत	73
12	सांख्यिकीय सेवाएं	75
13	सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण उप-योजना के लिए समर्थन	78
14	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	81
15	अन्य कार्यकलाप	84
	अनुबंध	
IA	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	89
IB	राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का संगठनात्मक चार्ट	90
IC	प्रयुक्त संक्षिप्तियां	91
II	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आवंटित कार्य	93
III A	बजट अनुमान विवरण (एसबीई) – 2023 - 24	95
III B	पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु 2022 - 23 (बीई तथा आरई) के लिए कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	96
III C	पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2023 - 24 (बीई एवं आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	97
IV	मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी प्रकाशन	98
V	वर्ष 2022 - 23 के लिए की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति	102
VI(A)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण	103
VI B	सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला वार्षिक विवरण	104

अध्याय - 1

प्रस्तावना

1.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (मॉस्पी) 15 अक्टूबर 1999 को एक स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आया था, इसकी स्थापना सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के द्वारा की गई थी। मंत्रालय देश में सांख्यिकीय प्रणाली के नियोजित और संगठित विकास और भारत सरकार, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न हितधारकों के बीच सांख्यिकीय गतिविधियों के समन्वय के साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नोडल एजेंसी है।

1.2 मंत्रालय के दो स्कंध हैं, सांख्यिकी स्कंध और कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध। एक स्वायत्त निकाय भी है जो एक भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के रूप में जाना जाता है, जिसे संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम 1959, द्वारा राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था, यह देश में सांख्यिकी के क्षेत्र में एक प्रसिद्ध और प्रमुख संस्थान है। इसके अलावा, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) भी है, जिसे 12 जुलाई 2006 को भारत सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से सांख्यिकीय मामलों में नीतियां, प्राथमिकताएं और मानक विकसित करने के लिए बनाया गया था। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक Iक और Iख पर दिया गया है।

1.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सभी सांख्यिकीय मामलों के लिए भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है और देश में जारी की जाने वाली सांख्यिकी के कवरेज और गुणवत्ता पहलुओं को काफी महत्व देता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है। मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़े प्रशासनिक स्रोतों, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए सर्वेक्षणों, जनगणनाओं और गैर-आधिकारिक स्रोतों और अध्ययनों पर आधारित होते हैं। मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले सर्वेक्षण वैज्ञानिक नमूनाकरण विधियों पर आधारित होते हैं और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा उनकी निगरानी की जाती है। डेटा समर्पित फील्ड स्टाफ के माध्यम से एकत्र किया जाता है, जिन्हें नियमित रूप से मदों की अवधारणाओं और परिभाषाओं और सर्वेक्षण के दायरे के बारे में प्रशिक्षित किया जाता है। मंत्रालय द्वारा जारी किए जाने वाले आंकड़ों की गुणवत्ता पर जोर देने के साथ-साथ, राष्ट्रीय खातों के संकलन से संबंधित पद्धतिगत मुद्दों की देखरेख राष्ट्रीय खातों पर सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति और मूल्य और जीवन-यापन सूचकांकों की देखरेख मूल्य और जीवन-यापन लागत के सांख्यिकी पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी ऑन एसपीसीएल) द्वारा की जाती है। मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों और व्यापक जांच और पर्यवेक्षण को लागू करने के बाद वर्तमान डेटा के आधार पर डेटा सेट संकलित करता है।

1.4 सांख्यिकी स्कंध, जिसे राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) कहा जाता है, देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों को विकसित करने और निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष डेटा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) का अनुपालक है और वर्तमान में इन मानकों को पूरा कर रहा है। मंत्रालय एसडीडीएस के अंतर्गत आने वाली डेटा श्रेणियों के लिए एक 'अग्रिम रिलीज कैलेंडर' रखता है, जिसे मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ आईएमएफ के प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) पर प्रसारित किया जाता है। मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले डेटासेट को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से एक साथ जारी करता है। भारत में आधिकारिक सांख्यिकी की एक मजबूत प्रणाली है और आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी देशों में से एक है। मंत्रालय के अधिकारी विशेष रूप से राष्ट्रीय खातों, अनौपचारिक क्षेत्र की सांख्यिकी, बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण, जनगणना के संचालन, सेवा क्षेत्र की सांख्यिकी, गैर-पर्यवेक्षित अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र की सांख्यिकी, पर्यावरण सांख्यिकी और वर्गीकरण, सांख्यिकीय संकलन और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के क्षेत्रों में कार्यप्रणाली के विकास पर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़े रहे हैं। इन विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की अत्यधिक सराहना की गई है।

1.5 हाल ही में, यह निर्णय लिया गया है कि:

(i) डेटा गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग (डीक्यूएडी) और डेटा सूचना विज्ञान नवाचार प्रभाग (डीआईआईडी) का नामकरण क्रमशः डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग (डीपीडी) और कंप्यूटर सेंटर में उनकी मूल भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ वापस कर दिया गया है।

(ii) पहले की स्थिति के अनुसार, कंप्यूटर सेंटर और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) अपनी मूल भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ मंत्रालय के संबद्ध कार्यालयों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

(iii) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और इसके घटक अर्थात् सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एससीडी), डेटा प्रोसेसिंग प्रभाग (डीपीडी), सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी) और फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (एफओडी) अपनी मूल भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे।

1.6 कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध में दो प्रभाग हैं, अर्थात् (i) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना और (ii) अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी)। एमपीलैड योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है, इसकी घोषणा 23 दिसंबर 1993 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री ने संसद में की थी। माननीय सांसदों को कुछ शर्तों के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में 5 करोड़ रुपये का वार्षिक प्राधिकरण आवंटित किया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सांसद को लोगों की स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। बुनियादी ढांचा परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की निगरानी करता है ।

1.7 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के अधीन आने वाला **राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)** राष्ट्रीय खातों की तैयारी के लिए जिम्मेदार है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण और बचत के अनुमानों के साथ-साथ संस्थागत क्षेत्रों के लेनदेन का विवरण शामिल है। एनएडी सालाना 'राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी' शीर्षक से एक प्रकाशन निकालता है, जिसमें ये आंकड़े शामिल होते हैं। एनएडी अग्रिम रिलीज कैलेंडर में दिए गए पूर्व-निर्दिष्ट कार्यक्रम के अनुसार समय-समय पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के वार्षिक और त्रैमासिक अनुमान जारी करता है। 29 फरवरी, 2024 को जारी वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार 2023-24 के दौरान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि 2022-23 में 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर की तुलना में 7.6 प्रतिशत अनुमानित था। मूल मूल्यों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) 2023-24 में ₹158.28 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2022-23 में यह ₹148.05 लाख करोड़ थी, जो 6.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

1.8 **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)** उन चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ आने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है जिनको लोग घरेलू उपभोग के उद्देश्य से खरीदते हैं। सीपीआई के आंकड़ों का व्यापक रूप से मुद्रास्फीति के व्यापक आर्थिक संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है, और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा मुद्रास्फीति को लक्षित करने और मूल्य स्थिरता की निगरानी के लिए एक उपकरण के रूप में भी उपयोग किया जाता है। सीपीआई का उपयोग राष्ट्रीय खातों में अपस्फीतिकारक के रूप में भी किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी सीपीआई का उपयोग अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा के लिए मुद्रास्फीति के उपाय के रूप में करता है। मंत्रालय ने मार्च, 2024 माह के लिए अखिल भारतीय ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए आधार वर्ष 2012 = 100 पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जारी किया, जो 187.8, 183.6 और 185.8 थे; मार्च, 2024 माह के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीपीआई) क्रमशः 187.8, 193.4 और 189.8 थे।

ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्र के लिए मार्च, 2024 माह के लिए सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः 8.55%, 8.41% और 8.52% थी। एनएसओ, सांख्यिकी मंत्रालय हर महीने की 12 तारीख को मुद्रास्फीति और सीपीआई पर डेटा जारी करता है (12 तारीख को छुट्टी होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर)। इसलिए, इस डेटा को जारी करने में समय अंतराल केवल 12 दिन है। इस रिलीज में विभिन्न हितधारकों के उपयोग के लिए राज्यवार व्यापक मुद्रास्फीति के आंकड़े शामिल हैं।

1.9 **अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी)** संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी) के तत्वावधान में दुनिया की सबसे बड़ी सांख्यिकीय पहल है। विश्व बैंक इस कार्यक्रम को वैश्विक स्तर पर लागू कर रहा है और एशियाई विकास बैंक (एडीबी) एशिया और प्रशांत क्षेत्र में इसकी नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। आईसीपी का मुख्य उद्देश्य क्रय शक्ति समता (पीपीपी) और मूल्य स्तर सूचकांक तैयार करना और पीपीपी का उपयोग करके सकल घरेलू उत्पाद के आयतन और प्रति व्यक्ति माप को सामान्य मुद्राओं में परिवर्तित करना है। भारत 1970 से आईसीपी में भाग ले रहा है और सांख्यिकी मंत्रालय इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली नोडल कार्यान्वयन एजेंसी है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी मंत्रालय का **मूल्य सांख्यिकी प्रभाग (पीएसडी)** अंतर-देशीय सत्यापन और पीपीपी आदि के संकलन के लिए एडीबी को डेटा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। आईसीपी के लिए डेटा मंत्रालय के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (एफओडी), प्रशासनिक डेटा, सर्वेक्षण और विभिन्न मंत्रालयों के पास उपलब्ध अन्य स्रोतों सहित विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया जाता है। वर्तमान में, आईसीपी 2021 दौर चल रहा है और इसके परिणाम जल्द ही घोषित किए जाने वाले हैं।

1.10 आधार वर्ष 2011-12 के साथ **औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)** को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के **आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी)** द्वारा हर महीने की 12 तारीख (या यदि 12 तारीख को छुट्टी हो तो पिछले कार्य दिवस) को संकलित और प्रकाशित किया जाता है, जिसमें संदर्भ महीने से छह सप्ताह का समय अंतराल होता है। आईआईपी में खनन, विनिर्माण और बिजली जैसे तीन क्षेत्र शामिल हैं। 2023-24 के लिए आईआईपी 146.7 है, जो 2022-23 के 5.2 प्रतिशत के मुकाबले 5.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है।

1.11 **आर्थिक गणना (ईसी)** सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र की उप-योजना के रूप में क्षमता विकास योजना के अंतर्गत संचालित की जा रही है। आर्थिक गणना से औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्रों में गैर-कृषि उद्यमों की कुल संख्या और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की संख्या के साथ-साथ भूगोल के निम्नतम स्तर पर अन्य क्रॉस-सेक्शनल पैरामीटर का पता चलता है ।

1.12 मंत्रालय को भारत में **सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी)** के लिए संकेतक ढांचे के विकास का काम सौंपा गया है ताकि एसडीजी की निगरानी की सुविधा मिल सके। एनएसओ के **सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)** ने राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी की सुविधा के लिए पहचाने गए डेटा स्रोतों और आवधिकता के साथ एसडीजी के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक ढांचा (एनआईएफ) विकसित किया। यह ढांचा प्रकृति में गतिशील है और हर साल इसकी समीक्षा और परिशोधन किया जाता है। वर्तमान में, एसडीजी एनआईएफ 2023 में, पहचाने गए डेटा स्रोतों और आवधिकता के साथ 284 राष्ट्रीय संकेतक शामिल हैं। प्रभाग संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन ढांचे की प्रणाली (यूएन एसईईए फ्रेमवर्क) का उपयोग करके पर्यावरण खाता भी संकलित करता है। 2023 में जारी किए गए खातों के सेट में नए क्षेत्र शामिल थे जैसे कि सामग्री प्रवाह खाते और वन द्वारा मृदा क्षरण रोकथाम सेवाओं पर खाते और साथ ही ठोस अपशिष्ट खाते और मछली प्रावधान सेवाएं। 2023-24 के दौरान प्रभाग द्वारा निम्न प्रकाशन लाए गए - सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2023, सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2023 पर डेटा स्नैपशॉट, सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क 2023, एनवीस्टेट्स इंडिया 2023 खंड (I) : पर्यावरण सांख्यिकी, फसल भूमि द्वारा प्रदान की गई मृदा क्षरण रोकथाम सेवाओं पर एनवीस्टेट्स इंडिया व्याख्याता श्रृंखला, एनवीस्टेट्स इंडिया 2023 खंड (II) : पर्यावरण खाते और भारत में महिलाएं और पुरुष, 2022।

1.13 **राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)** अखिल भारतीय आधार पर विविध क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नमूना सर्वेक्षण करने के लिए जिम्मेदार है।

प्राथमिक डेटा नियमित रूप से विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी घरेलू सर्वेक्षणों, सांख्यिकी संग्रह अधिनियम के तहत उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई) और आर्थिक जनगणना के अनुवर्ती के रूप में उद्यम सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्र किया जाता है। इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण और शहरी कीमतों पर डेटा एकत्र करता है और राज्य एजेंसियों के क्षेत्र गणना और फसल अनुमान सर्वेक्षणों की देखरेख के माध्यम से फसल सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह शहरी क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए नमूने तैयार करने के लिए शहरी क्षेत्र इकाइयों का एक ढांचा भी बनाए रखता है

1.14 **सांख्यिकी दिवस :** आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में (दिवंगत) प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने हर साल 29 जून को उनकी जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिवसों की श्रेणी में सांख्यिकी दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों, विशेषकर युवा पीढ़ी के बीच सामाजिक-आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी की भूमिका के बारे में (दिवंगत) प्रोफेसर महालनोबिस से प्रेरणा लेने के लिए जन जागरूकता पैदा करना है।

1.15 मॉस्पी ने 29 जून, 2023 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में 17वां सांख्यिकी दिवस मनाया। "सांख्यिकी दिवस" 2023 का विषय "सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के साथ राज्य संकेतक ढांचे का संरेखण" था। इस कार्यक्रम को मंत्रालय के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सीधा प्रसारण भी किया गया।

1.16 1967 में स्थापित कंप्यूटर सेंटर निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार है: (i) मंत्रालय की वेबसाइट, डेटा कैटलॉग और सीपीआई वेब पोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव; (ii) अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) ढांचे और एसडीएमएक्स (सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज) दिशानिर्देशों सहित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार मंत्रालय द्वारा उत्पादित रिपोर्टों और आंकड़ों का प्रसार; और (iii) मंत्रालय के अनुप्रयोगों / पोर्टलों की होस्टिंग और रखरखाव के लिए एनआईसी क्लाउड सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

1.17 मंत्रालय की वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in) को नवीनतम तकनीक का उपयोग करके डिजाइन किया गया है और यह उपयोगकर्ताओं को एक एकीकृत डिजिटल अनुभव प्रदान करता है। मंत्रालय की भूमिका, गतिविधियों, संपर्कों आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा, वेबसाइट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें मंत्रालय के सभी सांख्यिकीय प्रकाशन/रिपोर्ट, डेटा और डैशबोर्ड शामिल हैं। सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को शामिल करने के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम के रूप में, मंत्रालय की वेबसाइट में कुछ संवर्द्धन किए गए हैं, जैसे:

- किसी भी उद्योग समूह के राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण के अनुसार उपयुक्त कोड को कुछ प्रमुख शब्दों की सहायता से आसानी से खोजने के लिए एनआईसी कोड खोजक को शामिल करना।
- भारत में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए एक एफओडी कार्यालय लोकेटर भी विकसित किया गया है और उसे वेबसाइट पर रखा गया है।
- अपने होमपेज पर प्रमुख केपीआई (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) का प्रदर्शन,
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सर्वाधिक व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए डेटा उत्पादों से संबंधित डेटा विजुअलाइजेशन अनुभाग को शामिल करना, आदि।
- विजुअलाइजेशन अनुभाग जिसमें 1400 से अधिक डेटा विजुअलाइजेशन शामिल हैं।

वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है और मार्च 2023 माह से शुरू होकर पिछले एक वर्ष में इसमें 200 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।

1.18 मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस), केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (सीएसओएलएस), केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा (सीएससीएस) और मंत्रालय में तैनात मंत्री के कर्मचारियों के प्रशासनिक/स्थापना और सेवा संबंधी मामलों को देखता है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग मंत्रालय में तैनात केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अधिकारियों के सेवा मामलों को भी देखता है।

यह भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) और अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्गों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के अधिकारियों के कैडर नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करता है, जिसमें उनके प्रशिक्षण, करियर प्रगति और जनशक्ति नियोजन से संबंधित मामले शामिल हैं।

1.19 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है और भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959[1] के प्रावधानों के अनुसार इसके कामकाज को सुनिश्चित करता है। यह सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008[2] का प्रशासन भी करता है।

1.20 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को कार्य का आवंटन **अनुलग्नक II** पर दिया गया है। मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.mospi.gov) है और इसे मंत्रालय के एनएसओ के कंप्यूटर सेंटर द्वारा डिजाइन, निर्मित और रखरखाव किया जा रहा है। विभिन्न हितधारकों की पहुँच/उपयोग के लिए मंत्रालय की बड़ी संख्या में रिपोर्ट वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। रिपोर्ट डाउनलोड करने/देखने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की एक प्रणाली भी शुरू की गई है।

1.21 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान चरण में मंत्रालय का कुल बजट आवंटन ₹ 5,443.40 करोड़ (योजना और गैर-योजना) है, जिसमें से ₹ 4558.50 करोड़ योजना के लिए और ₹ 884.90 करोड़ गैर-योजना के लिए है। इस मंत्रालय द्वारा बजटीय आवंटन करते समय इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाता है।

[1] 1959 का अधिनियम संख्या 57

[2] 2008 का अधिनियम संख्या 7

अध्याय - 2

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी)

2.1 रंगराजन आयोग की सिफारिश को स्वीकार करने के मंत्रिमंडल के निर्णय के बाद, जिसने 2001 में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली की समीक्षा की थी, भारत सरकार ने 1 जून 2005 के एक प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) स्थापित करने का निर्णय लिया और सांख्यिकीय मामलों पर नीतियां, प्राथमिकताएं और मानक विकसित करने के अधिदेश के साथ 12 जुलाई 2006 को एनएससी का गठन किया गया। प्रस्ताव में कई संशोधन हुए हैं, जिन्हें 5 नवंबर 2019 के प्रस्ताव में संक्षेपित किया गया है। एनएससी में एक अंशकालिक अध्यक्ष और चार अंशकालिक सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक के पास निर्दिष्ट सांख्यिकीय और संबद्ध क्षेत्रों में विशेषज्ञता और अनुभव होता है। इसके अलावा, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनएससी के पदेन सदस्य होते हैं। अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है। भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् एनएससी के सचिव होते हैं।

2.2 31 मार्च 2024 तक एनएससी के अंशकालिक अध्यक्ष और अंशकालिक सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

क्र.सं.	नाम और पदनाम	कार्यकाल अधिकतम
1	प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर, अध्यक्ष	8 दिसंबर 2022 - 7 दिसंबर 2025
2	प्रो. मुकेश मोहनिया, सदस्य	1 दिसंबर 2022 - 30 नवंबर 2025
3	श्री असित कुमार साधु, सदस्य	5 दिसंबर 2022 - 4 दिसंबर 2025
4	प्रो. ए. गणेश कुमार, सदस्य	18 मार्च 2024 - 17 मार्च 2027
5	प्रो. देबाशीष कुंडू, सदस्य	19 मार्च 2024 - 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक

2.3 एनएससी के कार्यों को भारत सरकार के 5 नवंबर 2019 के संकल्प में निर्धारित किया गया है। संकल्प में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एनएससी द्वारा अपनी गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने और उसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ इसे संसद के दोनों सदनों या संबंधित राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

अध्याय - 3

राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय

3.1 राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) देश में सांख्यिकीय गतिविधियों का समन्वय करता है और सांख्यिकीय मानकों का विकास करने और निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी है। इसकी गतिविधियों में, अन्य बातों के साथ-साथ, जेंडर सांख्यिकी और आर्थिक गणना तथा सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करने सहित राष्ट्रीय लेखों का संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मानव विकास सांख्यिकी शामिल है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण गतिविधियां मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय नामतः क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) के माध्यम से संचालित की जाती हैं। एनएसओ राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में सहायता करता है तथा ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक और पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है और राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है।

3.2 एनएसओ की जेंडर, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा आदि जैसे बहु-डोमेन आंकड़ों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका है और यह सरकार की विभिन्न एजेंसियों के बीच सहयोग स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ताकि इनमें से प्रत्येक एजेंसी के प्रयासों को समय पर कुशलतापूर्वक आंकड़े तैयार करने के लिए संचित किया जा सके जो देश में इन आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक घटनाओं के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करते हैं। एनएसओ द्वारा निभाई जाने वाली भूमिकाओं में से एक इन बहु-डोमेन आंकड़ों की जानकारी के एकत्रीकरण की है, ताकि नीति निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं को एक ही स्थान पर सभी आवश्यक जानकारी उपलब्ध हो। इस समेकित डेटासेट का कार्य सभी स्तरों पर निर्णय लेने, मूल्यांकन और आकलन के लिए बुनियादी जानकारी प्रदान करना है। इस संबंध में, सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, एनएसओ की ओर से, कुछ वार्षिक प्रकाशनों के साथ-साथ विषय-विशिष्ट तदर्थ प्रकाशन भी तैयार करता है जो कुछ उपयोक्ता मांगों का परिणाम है ।

3.3 यह प्रभाग केंद्र और राज्य स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में गठित कई विशेषज्ञ/तकनीकी समूहों और समितियों में एनएसओ का प्रतिनिधित्व करता है और न केवल देश के भीतर विभिन्न सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बल्कि सभी स्तरों पर सांख्यिकीय प्रणालियों की स्थिरता और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए मानकीकृत अवधारणाओं, वर्गीकरण और विधियों के उपयोग पर बल देता है। एनएसओ में विभिन्न प्रभाग विभिन्न एजेंसियों में क्षमता विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ताकि बहु-डोमेन सांख्यिकी के संबंध में मौजूदा संकेतक-सेट की मजबूती और कवरेज में सुधार हो सके।

राष्ट्रीय लेखा

3.4 केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है, जिसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्रों के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। एनएडी इन अनुमानों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है। एनएडी समय-समय पर आपूर्ति-उपयोग तालिकाएं (एसयूटी) तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं (आईओटीटी) तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है। एनएडी राष्ट्रीय आय के आकलन से संबंधित मामलों पर अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ संपर्क बनाए रखता है।

3.5 एनएडी राज्य के घरेलू उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य की आय और संबंधित समुच्चयों के अनुमानों के समेकन पर राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा बड़े-क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) और सकल नियत पूंजी सृजन (जीएफसीएफ) के राज्य स्तरीय अनुमान प्रस्तुत किए जाते हैं ।

3.6 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, एनएडी अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद (जीएसडीपी/एनएसडीपी) के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है।

3.7 अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। वर्ष 2023-24 में एनएडी द्वारा विभिन्न अनुमानों को जारी करने की अनुसूची नीचे दी गई है:

जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर

वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसम्बर)	29 फरवरी 2024
वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च)	31 मई 2024
वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून)	30 अगस्त 2024
वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितम्बर)	29 नवंबर 2024

जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर

वर्ष 2023-24 के प्रथम अग्रिम अनुमान	05 जनवरी 2024
वर्ष 2022-23 के प्रथम संशोधित अनुमान	29 फरवरी 2024
वर्ष 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान	29 फरवरी 2024
वर्ष 2023-24 के अनंतिम अनुमान	31 मई 2024

3.8 मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 से आगे के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के तीसरे संशोधित अनुमान (टीआरई) को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए, 2020-21 का टीआरई और 2021-22 का दूसरा संशोधित अनुमान (एसआरई) संबंधित वर्षों के लिए अंतिम अनुमान हैं।

3.9 29 फरवरी, 2024 को जारी 2023-24 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) के अनुसार व्यय पक्ष अनुमानों के साथ-साथ वर्तमान और स्थिर दोनों मूल्यों पर जीवीए के उद्योग वार अनुमान निम्नलिखित विवरणों और ग्राफ में दिए गए हैं:

विवरण 1: सकल घरेलू उत्पाद के राष्ट्रीय आय और व्यय घटकों का दूसरा अग्रिम अनुमान, 2023-24 (2011-12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	2021-22 (दूसरी आरई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन 2022-23	2023-24
	घरेलू उत्पाद					
1	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	13,876,840	14,804,901	15,827,708	6.7	6.9
2	उत्पादों पर निवल कर	1,145,006	1,266,528	1,462,573	10.6	15.5
3	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)@	15,021,846	16,071,429	17,290,281	7.0	7.6
4	निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी)	13,066,058	13,986,798	15,061,632	7.0	7.7

क्रम सं.	मद	2021-22 (दूसरी आारई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन 2022-23	2023-24
	व्यय घटक[#]					
5	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	8,732,573	9,323,825	9,605,526		
6	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	1,480,394	1,613,726	1,662,078		
7	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीई)	5,014,263	5,346,423	5,893,155		
8	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	160,203	183,464	192,587		
9	बहुमूल्य वस्तुएं	283,099	229,167	260,747		
10	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	3,393,107	3,847,742	3,906,346		
11	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	3,543,745	3,919,021	4,346,728		
12	विसंगतियां	-498,048	-553,897	116,571		
13	जीडीपी	15,021,846	16,071,429	17,290,281		
	जीडीपी में शेयर (%)					
14	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	58.1	58.0	55.6		
15	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	9.9	10.0	9.6		
16	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	33.4	33.3	34.1		
17	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	1.1	1.1	1.1		
18	बहुमूल्य वस्तुएं	1.9	1.4	1.5		
19	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	22.6	23.9	22.6		
20	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	23.6	24.4	25.1		
21	विसंगतियां	-3.3	-3.4	0.7		
22	जीडीपी	100.0	100.0	100.0		
	राष्ट्रीय उत्पाद					
23	सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई)	14,827,920	15,831,133	17,034,386	6.8	7.6
24	निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई)	12,872,132	13,746,502	14,805,736	6.8	7.7

क्रम सं.	मद	2021-22 (दूसरी आारई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन 2022-23	2023-24
	प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम रूप से खपत					
25	जनसंख्या (लाखों में)	1369	1383	1395		
26	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	109,762	116,216	123,945	5.9	6.7
27	प्रति व्यक्ति जीएनआई (₹)	108,345	114,478	122,110	5.7	6.7
28	प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹)	94,054	99,404	106,134	5.7	6.8
29	प्रति व्यक्ति पीएफसीई (₹)	63,807	67,423	68,857	5.7	2.1

आरई: संशोधित अनुमान; एसएई : दूसरा अग्रिम अनुमान

@जीडीपी (उत्पादन/आय दृष्टिकोण) = बुनियादी मूल्य पर जीवीए उत्पादों पर शुद्ध कर

#व्यय दृष्टिकोण के अनुसार, जीडीपी = पीएफसीइ + जीएफसीई + जीएफसीएफ + सीआईएस + मूल्यवान वस्तुएँ + निर्यात - आयात। विसंगति जीडीपी (उत्पादन/आय दृष्टिकोण) और जीडीपी (व्यय दृष्टिकोण) के बीच अंतर को संदर्भित करती है।

*मध्य वित्तीय वर्ष से संबंधित

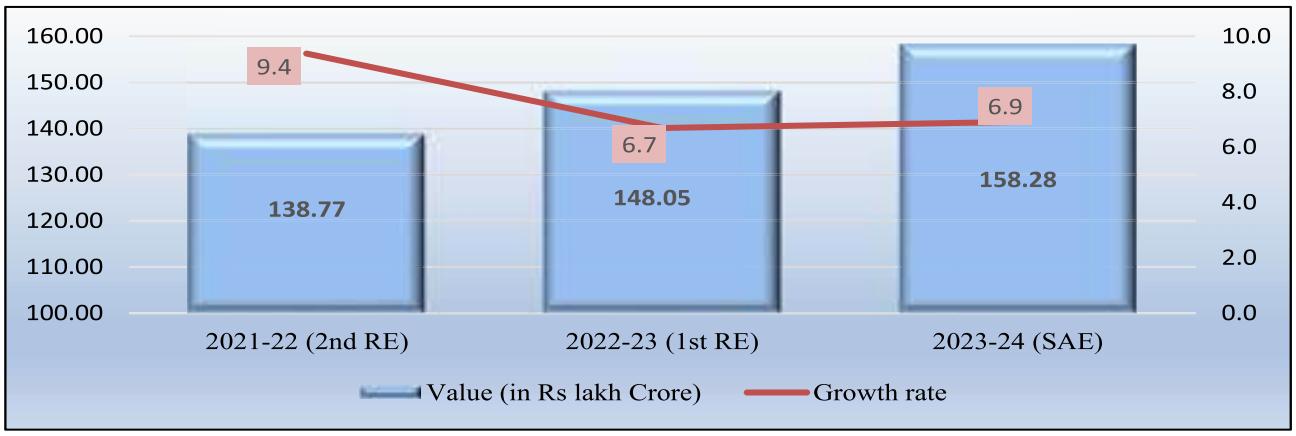

विगत तीन वर्षों के लिए बुनियादी मूल्यों पर जीवीए के वार्षिक अनुमान और वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

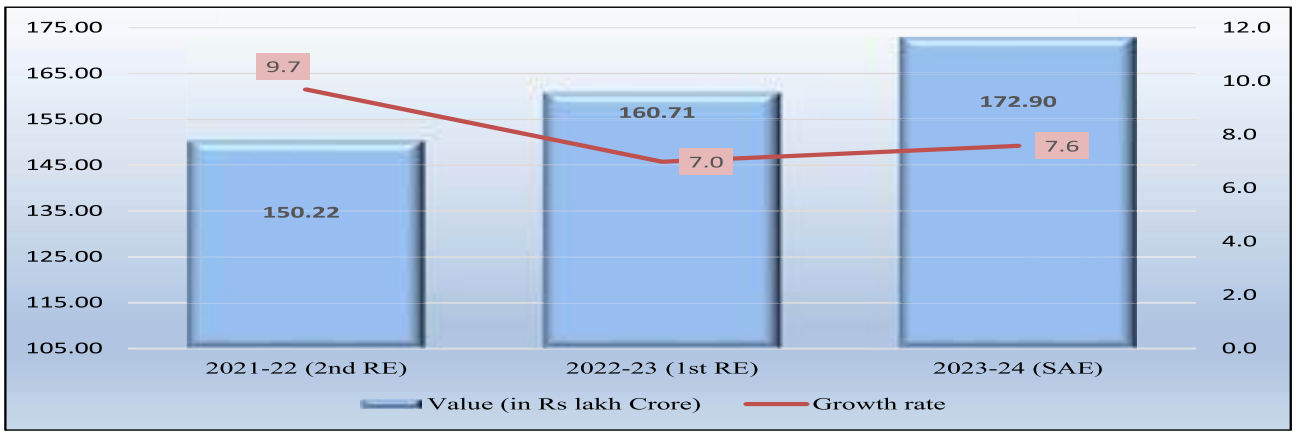

विगत तीन वर्षों के लिए जीडीपी के वार्षिक अनुमान और वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (स्थिर मूल्यों पर)

विवरण 2: सकल घरेलू उत्पाद के राष्ट्रीय आय और व्यय घटकों का दूसरा अग्रिम अनुमान, 2023-24 (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	मद	2021-22 (दूसरी आरई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन 2022-23	2023-24
	घरेलू उत्पाद					
1	बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	21,635,584	24,659,041	26,677,679	14.0	8.2
2	उत्पादों पर निवल कर					
3	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)[@]	1,961,815	2,290,605	2,712,007	16.8	18.4
4	निवल घरेलू उत्पाद (एनडीपी)	23,597,399	26,949,646	29,389,686	14.2	9.1
		20,930,595	23,809,748	25,992,750	13.8	9.2
	व्यय घटक[#]					
5	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	14,382,704	16,422,535	17,734,041		
6	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	2,472,153	2,883,649	3,085,666		
7	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीई)	6,979,647	8,286,979	9,207,604		
8	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	213,837	277,120	292,655		
9	बहुमूल्य वस्तुएं	385,015	335,730	414,375		
10	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	5,049,645	6,252,449	6,433,885		
11	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	5,669,023	7,213,027	7,042,440		
12	विसंगतियां	-216,578	-295,789	-736,100		
13	जीडीपी	23,597,399	26,949,646	29,389,686		
	जीडीपी में शेयर (%)					
14	निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई)	61.0	60.9	60.3		
15	सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई)	10.5	10.7	10.5		
16	सकल नियत पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ)	29.6	30.7	31.3		

क्रम सं.	मद	2021-22 (दूसरी आारई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन 2022-23	2023-24
17	स्टाकों में बदलाव (सीआईएस)	0.9	1.0	1.0		
18	बहुमूल्य वस्तुएं	1.6	1.2	1.4		
19	वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात	21.4	23.2	21.9		
20	वस्तुओं और सेवाओं का आयात	24.0	26.8	24.0		
21	विसंगतियां	-0.9	-1.1	-2.5		
22	जीडीपी	100.0	100.0	100.0		
	राष्ट्रीय उत्पाद					
23	सकल राष्ट्रीय आय (जीएनआई)	23,319,590	26,579,339	28,958,373	14.0	9.0
24	निवल राष्ट्रीय आय (एनएनआई)	20,652,786	23,439,442	25,561,438	13.5	9.1
25	सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (जीएनडीआई)	23,925,034	27,398,551	29,839,727	14.5	8.9
26	निवल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय (एनएनडीआई)	21,258,230	24,258,653	26,442,791	14.1	9.0
	प्रति व्यक्ति आय, उत्पाद और अंतिम रूप से खपत					
27	प्रति व्यक्ति जीडीपी (₹)	172,422	194,879	210,679	13.0	8.1
28	प्रति व्यक्ति जीएनआई (₹)	170,392	192,201	207,587	12.8	8.0
29	प्रति व्यक्ति एनएनआई (₹)	150,906	169,496	183,236	12.3	8.1
30	प्रति व्यक्ति जीएनडीआई (₹)	174,816	198,125	213,905	13.3	8.0
31	प्रति व्यक्ति पीएफसीई (₹)	105,092	118,755	127,126	13.0	7.0

आरईः संशोधित अनुमान; एसएई; दूसरा अग्रिम अनुमान

@जीडीपी (उत्पादन/आय दृष्टिकोण) = बुनियादी मूल्य पर जीवीए + उत्पादों पर शुद्ध कर

#व्यय दृष्टिकोण के अनुसार, जीडीपी = पीएफसीई + जीएफसीई + जीएफसीएफ + सीआईएस + मूल्यवान वस्तुएँ + निर्यात - आयात। विसंगति जीडीपी (उत्पादन/आय दृष्टिकोण) और जीडीपी (व्यय दृष्टिकोण) के बीच अंतर को संदर्भित करती है।

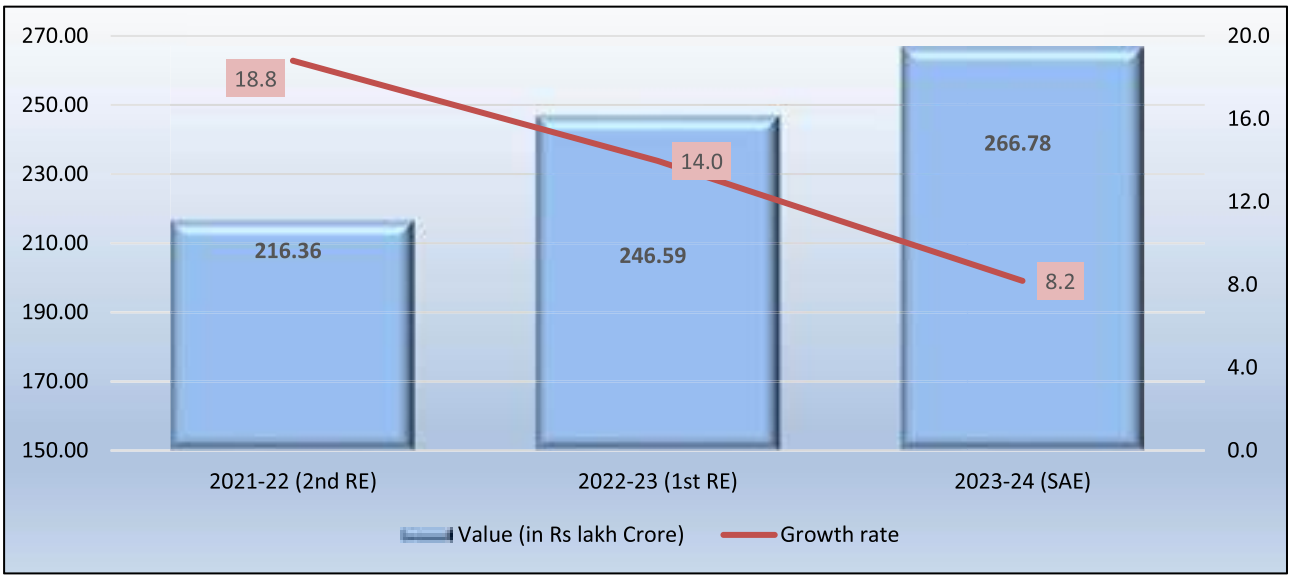

विगत तीन वर्षों के लिए बुनियादी मूल्यों पर जीवीए के वार्षिक अनुमान और वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

विगत तीन वर्षों के लिए जीडीपी के वार्षिक अनुमान और वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर (वर्तमान मूल्यों पर)

विवरण 3 : आर्थिक गतिविधि के आधार पर बुनियादी मूल्यों पर जीवीए का दूसरा अग्रिम अनुमान (2011-12 मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

उद्योग	2021-22 (दूसरी आरई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
				2022-23	2023-24
1. कृषि,पशुधन,वानिकी और मत्स्य पालन	2,170,106	2,272,250	2,287,329	4.7	0.7
2. खनन एवं उत्खनन	309,276	315,256	340,821	1.9	8.1
3. विनिर्माण	2,561,033	2,504,663	2,717,235	-2.2	8.5
4. विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	317,966	347,973	374,125	9.4	7.5
5. निर्माण	1,193,532	1,306,256	1,445,603	9.4	10.7
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	2,480,380	2,777,723	2,957,058	12.0	6.5
7. वित्तीय, रिएल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	3,122,847	3,405,474	3,684,959	9.1	8.2
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं*	1,721,699	1,875,304	2,020,579	8.9	7.7
बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	**13,876,840**	**14,804,901**	**15,827,708**	**6.7**	**6.9**

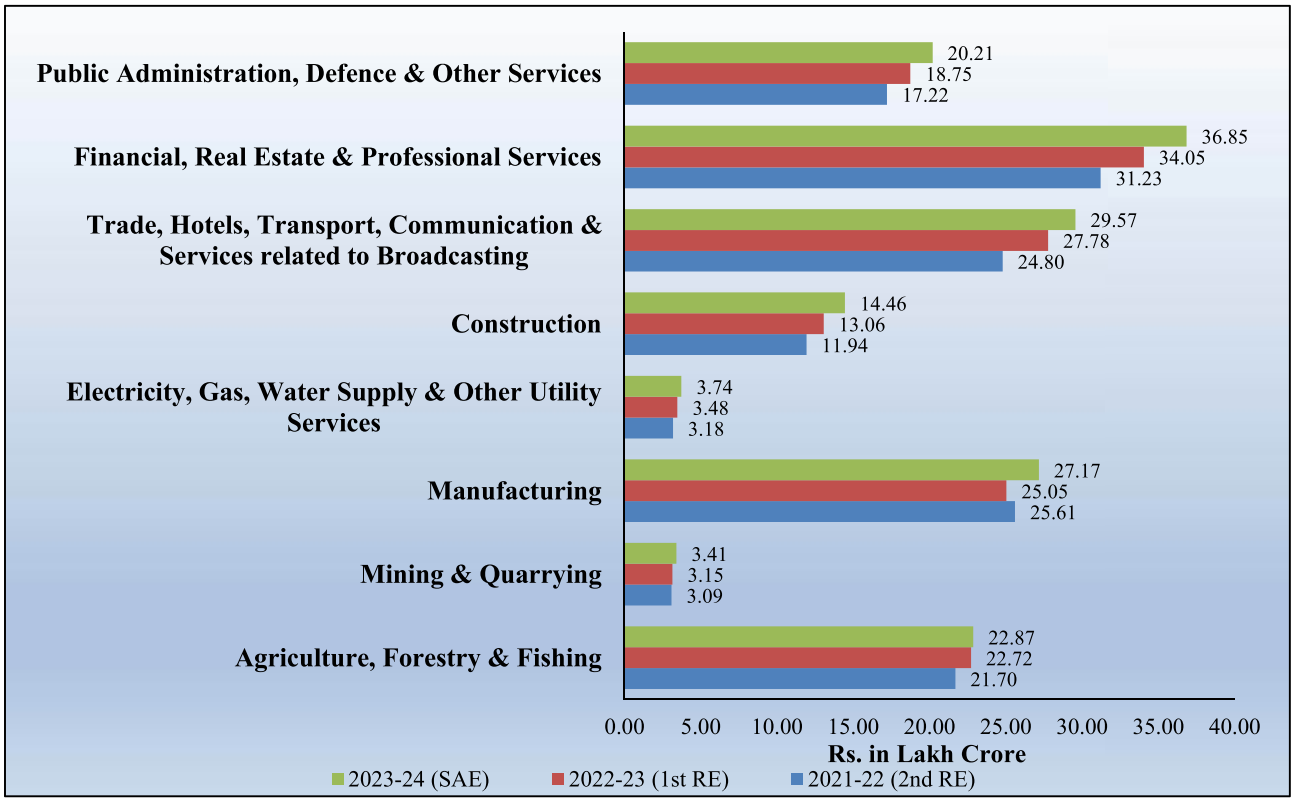

बुनियादी मूल्यों पर आर्थिक गतिविधि-वार वास्तविक जीवीए अनुमान

विवरण 4 : आर्थिक गतिविधि के आधार पर बुनियादी मूल्यों पर जीवीए का दूसरा अग्रिम अनुमान (वर्तमान मूल्यों पर)

(₹ करोड़ में)

उद्योग	2021-22 (दूसरी आरई)	2022-23 (प्रथम आरई)	2023-24 (एसएई)	पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत में परिवर्तन	
				2022-23	2023-24
1. कृषि,पशुधन,वानिकी और मत्स्य पालन	4,099,473	4,484,268	4,692,360	9.4	4.6
2. खनन एवं उत्खनन	439,339	494,602	527,064	12.6	6.6
3. विनिर्माण	3,392,605	3,536,461	3,773,280	4.2	6.7
4. विद्युत, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं	577,793	604,209	651,838	4.6	7.9
5. निर्माण	1,835,674	2,178,693	2,397,798	18.7	10.1
6. व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं	3,674,918	4,410,148	4,688,447	20.0	6.3
7. वित्तीय, रिएल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं	4,645,873	5,520,163	6,052,948	18.8	9.7
8. लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं*	2,969,909	3,430,497	3,893,944	15.5	13.5
बुनियादी मूल्यों पर जीवीए	**21,635,584**	**24,659,041**	**26,677,679**	**14.0**	**8.2**

आरईः संशोधित अनुमान; एसएईः दूसरा अग्रिम अनुमान

*लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवा श्रेणी में अन्य सेवा क्षेत्र अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और अन्य व्यक्तिगत सेवाएं शामिल हैं

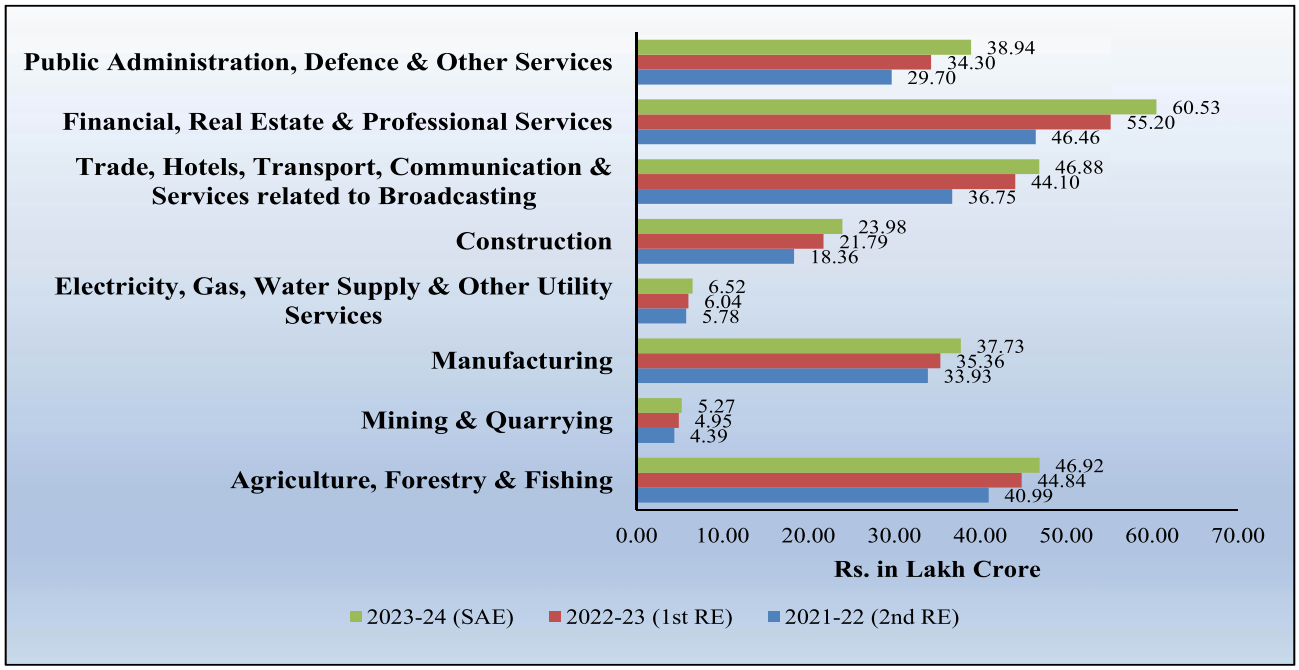

बुनियादी मूल्यों पर आर्थिक गतिविधि-वार सांकेतिक जीवीए अनुमान

3.10 वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एनएडी द्वारा जारी किए गए प्रकाशन, डाटा विज्ञप्तियां और रिपोर्टें, जो सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:

क्र.सं.	प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण	जारी करने की तिथि	जारी करने का तरीका
1.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – 2023	अप्रैल, 2023	ई-प्रकाशन
2.	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से उत्पादन का राज्य-वार और मद-वार मूल्य (2011&12 से 2020-21)	अप्रैल, 2023	प्रेस नोट
3.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-फरवरी, 2023	25 अप्रैल 2023	प्रेस नोट
4.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-मार्च, 2023	25 मई, 2023	प्रेस नोट
5.	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान और 2022-23 की चौथी तिमाही (क्यू4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	31 मई 2023	प्रेस नोट
6.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-अप्रैल, 2023	23 जून, 2023	प्रेस नोट
7.	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-मई, 2023	25 जुलाई, 2023	प्रेस नोट
8	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-जून, 2023	25 जुलाई, 2023	प्रेस नोट
9	2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेल उत्पाद का अनुमान	25 अगस्त, 2023	प्रेस नोट
10	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-जुलाई, 2023	23 सितंबर, 2023	प्रेस नोट
11	आपूर्ति और उपयोग तालिका (एसयूटी) 2019-20	25 सितंबर, 2023	ई-प्रकाशन
12	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-अगस्त, 2023	25 अक्टूबर, 2023	प्रेस नोट
13	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-सितंबर, 2023	24 नवंबर, 2023	प्रेस नोट
14	2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान	30 नवंबर 2023	प्रेस नोट
15	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-अक्टूबर, 2023	22 दिसंबर, 2023	प्रेस नोट
16	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान (एफएई)	5 जनवरी, 2024	प्रेस नोट
17	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-नवंबर, 2023	25 जनवरी, 2024	प्रेस नोट
18	भारत में पेरोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य*-दिसंबर, 2023	23 फरवरी, 2024	प्रेस नोट
19	राष्ट्रीय आय, 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) य 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (क्यू3) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान के साथ इसके व्यय घटक तथा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान	29 फरवरी, 2024	प्रेस नोट

*प्रत्येक माह की 25वीं तारीख को जारी और यदि 25वीं तारीख को अवकाश है तो उससे पहले कार्य दिवस को जारी।

3.11 वर्ष 2023-2024 के दौरान विभिन्न बैठकें/सम्मेलन/कार्यशालाएं आयोजित की गईं:

3.12 वर्ष 2020-21 और 2021-22, आधार वर्ष 2011-12 के लिए एसडीपी के तुलनीय अनुमानों पर राज्यों के डीईएस और एनएडी अधिकारियों/पदाधिकारियों के बीच वार्षिक चर्चा 17 अप्रैल - 10 मई, 2023 के दौरान आयोजित की गई।

3.13 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्यां. मं.) द्वारा 07 जुलाई, 2023 को आईजीआईडीआर, मुंबई में राष्ट्रीय लेखा डेटा उपयोगकर्ता सेमिनार का आयोजन किया गया।

3.14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकीय कार्मिकों के लिए राज्य घरेलू उत्पाद और अन्य संबंधित समुच्चयों के संकलन पर पहली क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं 7 से 11 अगस्त, 2023 के दौरान गुवाहाटी, असम में आयोजित की गईं, जिसमें 9 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल शामिल थे।

3.15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकीय कार्मिकों के लिए राज्य घरेलू उत्पाद और अन्य संबंधित समुच्चयों के संकलन पर दूसरी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं 11 से 15 सितंबर, 2023 के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की गईं, जिसमें 11 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अर्थात् आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, राजस्थान, दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव, पुडुचेरी और तेलंगाना शामिल थे।

3.16 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकीय कार्मिकों के लिए राज्य घरेलू उत्पाद और अन्य संबंधित समुच्चयों के संकलन पर तीसरी क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला 07 से 11 अक्टूबर 2023 के दौरान पंचकूला, हरियाणा में आयोजित की गई, जिसमें 12 राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र, अर्थात् छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख शामिल थे ।

3.17 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग ने 11 से 15 मार्च, 2024 के दौरान राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी और कार्यप्रणाली के संकलन पर नेपाल के अधिकारियों के अध्ययन दौरे की मेजबानी की।

मूल्य सांख्यिकी

3.18 केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ), सां. और कार्य.कार्या.मंत्रा., ने जनवरी 2011 से अखिल भारत तथा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010=100) के साथ मासिक आधार पर ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्र हेतु पृथक रूप से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करना आरंभ किया। अंतरराष्ट्रीय पद्धतियों के सामंजस्य से कार्यप्रणाली में बहुत से सुधारों को समाहित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से 2012=100 में संशोधित किया है। संशोधित श्रृंखला के लिए मदों तथा अधिमान रेखाचित्रों की बास्केट को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 68वें दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) 2011-12 के मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) दस उप-समूहों नामतः 'अनाज तथा उत्पाद; 'मांस तथा मछली; 'अंडा'; 'दूध तथा उत्पाद'; 'तेल एवं वसा'; 'फल'; 'वनस्पति'; 'दलहन तथा उत्पाद'; 'चीनी एवं मिष्ठान' 'तथा 'मसाले' के अधिमान औसत सूचकांकों के रूप में भी जारी किए जा रहे हैं। सीएफपीआई में 'गैर-एल्कोहलिक पेय' तथा 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां आदि' शामिल नहीं हैं।

सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति में रुझान

3.19 संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह की तुलना में वर्तमान माह की सीपीआई के प्रतिशत बदलाव) दिसम्बर, 2022 से मार्च, 2024 की अवधि के दौरान 4 प्रतिशत से अधिक थी। उक्त दर जुलाई, 2023 में 7.44 प्रतिशत पर सबसे अधिक हो गई थी। उपर्युक्त अवधि के दौरान मई 2023 में न्यूनतम दर 4.31 प्रतिशत दर्ज की गई थी।

3.20 संयुक्त क्षेत्र के लिए सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%) दर्शाती हैं कि दिसम्बर, 2022 से मार्च, 2024 के दौरान खाद्य मदों की औसत मुद्रास्फीति दर 6.92 % थी । सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने जुलाई 2023 में 11.51 प्रतिशत के उच्चतम स्तर को और मई 2023 में 2.96 प्रतिशत के न्यूनतम स्तर को छुआ है ।

माह और वर्ष	सीपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)	सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)
दिसंबर-22	5.72	4.19
जनवरी-23	6.52	6.00
फरवरी-23	6.44	5.95
मार्च-23	5.66	4.79
अप्रैल-23	4.70	3.84
मई-23	4.31	2.96
जून-23	4.87	4.55
जुलाई-23	7.44	11.51
अगस्त-23	6.83	9.94
सितंबर-23	5.02	6.62
अक्टूबर-23	4.87	6.61
नवंबर-23	5.55	8.70
दिसंबर-23	5.69	9.53
जनवरी-24	5.10	8.30
फरवरी-24	5.09	8.66
मार्च-24	4.85	8.52

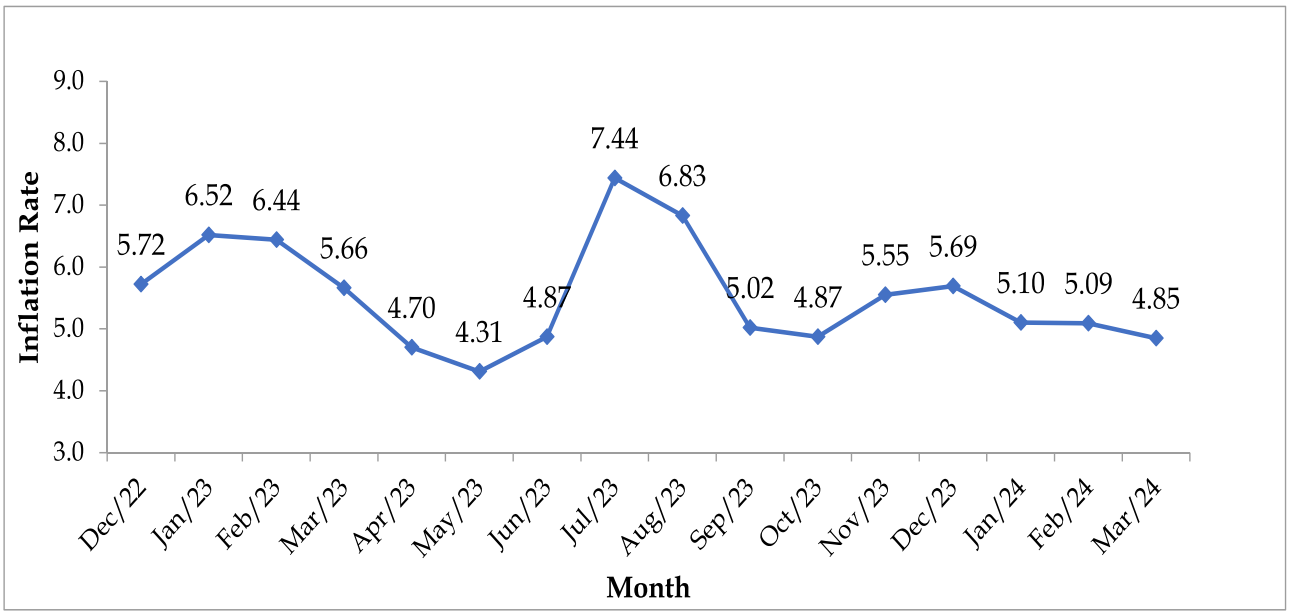

सीपीआई के आधार पर अखिल भारतीय वर्ष दर वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

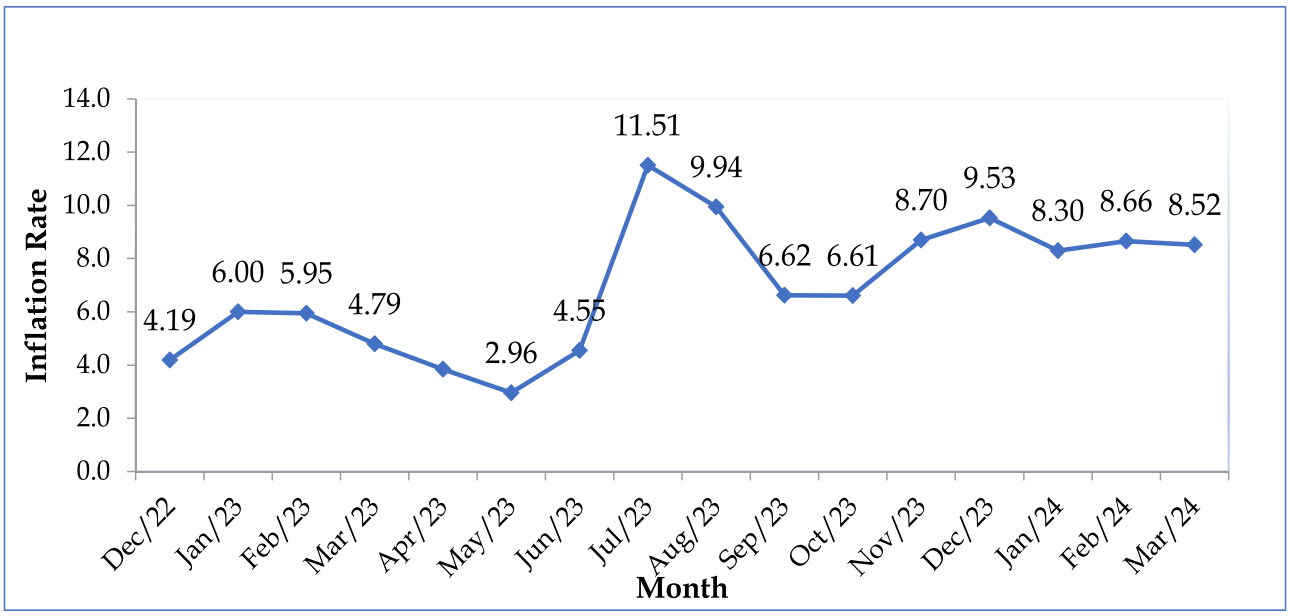

सीएफपीआई के आधार पर अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (%)

3.21 एनएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। उल्लेखनीय है कि यह परिपूर्ण रूप में 'खाद्य और पेय पदार्थ' का 45.86 प्रतिशत शेयर है जिसमें संयुक्त क्षेत्र के सीपीआई बॉस्केट में सीएफपीआई का 39.05 प्रतिशत शेयर शामिल है। अतः आमतौर पर खाद्य मदें सीपीआई पर आधारित समग्र मुद्रास्फीति दर की प्रमुख संचालक होती हैं। उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दरें और उनके संबंधित शेयर (अधिभार के संबंध में) को दिसम्बर, 2022 से मार्च, 2024 तक प्रत्येक माह के दौरान समग्र मुद्रास्फीति दर में उनका योगदान जानने के लिए एक साथ जोड़ा गया है। ये योगदान निम्नलिखित सारणी में दिए गए हैं ।

सारणी - 3

संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई पर आधारित समूह/उपसमूह-वार मुद्रास्फीति दरों में समग्र मुद्रास्फीति का विवरण

क्र. सं.	समूह/उप समूह का नाम	अधिमान	दिस.-22	जन.-23	फर.-23	मार्च-23	अप्रै.-23	मई-23	जून-23	जुला.-23	अग.-23	सित.-23	अक्टू-23	नव.-23	दिस.-23	जन.-24	फर.-24	मार्च-24
1	अनाज और उत्पाद	9.67	1.19	1.43	1.47	1.33	1.17	1.11	1.12	1.14	1.06	0.99	0.97	0.94	0.92	0.74	0.73	0.80
2	मांस व मछली	3.61	0.22	0.26	0.15	-0.06	-0.05	-0.06	0.07	0.10	0.16	0.18	0.14	0.09	0.05	0.05	0.22	0.27
3	अंडा	0.43	0.03	0.04	0.02	0.02	0.01	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.04	0.03	0.02	0.03	0.05	0.04
4	दूध और उत्पाद	6.61	0.54	0.57	0.62	0.59	0.55	0.57	0.55	0.53	0.50	0.44	0.41	0.37	0.33	0.30	0.25	0.22
5	तेल और वसा	3.56	0.02	0.05	-0.02	-0.33	-0.51	-0.68	-0.76	-0.67	-0.60	-0.54	-0.51	-0.57	-0.57	-0.56	-0.52	-0.42
6	फल	2.89	0.05	0.08	0.17	0.20	0.06	0.02	0.04	0.09	0.11	0.20	0.25	0.29	0.29	0.22	0.13	0.08
7	सब्जियां	6.04	-1.03	-0.75	-0.72	-0.51	-0.38	-0.49	-0.04	2.37	1.70	0.23	0.19	1.11	1.51	1.41	1.55	1.48
8	दालें और उत्पाद	2.38	0.09	0.10	0.10	0.10	0.12	0.15	0.24	0.30	0.30	0.38	0.43	0.47	0.48	0.45	0.43	0.41
9	चीनी और मिष्ठान	1.36	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
10	मसाले	2.5	0.52	0.55	0.53	0.48	0.46	0.48	0.52	0.59	0.65	0.65	0.64	0.62	0.57	0.48	0.40	0.34
11	गैर- अल्कोहलिक पेय पदार्थ	1.26	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03
12	तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाईयां आदि	5.55	0.46	0.47	0.48	0.45	0.40	0.38	0.35	0.32	0.32	0.29	0.28	0.25	0.24	0.24	0.23	0.22
13	**खाद्य और पेय पदार्थ**	**45.86**	**2.16**	**2.87**	**2.86**	**2.34**	**1.91**	**1.59**	**2.19**	**4.86**	**4.28**	**2.93**	**2.92**	**3.70**	**3.94**	**3.46**	**3.58**	**3.55**
14	**पान, तंबाकू, और मादक पदार्थ**	**2.38**	**0.07**	**0.09**	**0.09**	**0.08**	**0.09**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.11**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**0.09**	**0.08**	**0.08**
15	कपड़े	5.58	0.52	0.51	0.50	0.46	0.42	0.38	0.35	0.32	0.30	0.27	0.25	0.23	0.22	0.20	0.19	0.18
16	जूते-चप्पल	0.95	0.10	0.10	0.09	0.08	0.07	0.06	0.06	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
17	**कपड़े और जूते-चप्पल**	**6.53**	**0.62**	**0.61**	**0.59**	**0.54**	**0.49**	**0.45**	**0.41**	**0.38**	**0.35**	**0.31**	**0.29**	**0.26**	**0.25**	**0.23**	**0.21**	**0.21**

18	**हाउसिंग**	**10.07**	**0.44**	**0.47**	**0.49**	**0.49**	**0.48**	**0.48**	**0.45**	**0.44**	**0.43**	**0.39**	**0.37**	**0.35**	**0.35**	**0.31**	**0.28**	**0.27**
19	**ईंधन और प्रकाश**	**6.84**	**0.74**	**0.74**	**0.68**	**0.60**	**0.38**	**0.33**	**0.28**	**0.26**	**0.30**	**-0.01**	**-0.03**	**-0.05**	**-0.07**	**-0.04**	**-0.05**	**-0.24**
20	परिवार वस्तुएं और सेवाएं	3.8	0.27	0.27	0.27	0.26	0.23	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10
21	स्वास्थ्य	5.89	0.37	0.39	0.40	0.40	0.38	0.38	0.37	0.37	0.37	0.35	0.35	0.33	0.31	0.29	0.28	0.26
22	परिवहन और संचार	8.59	0.40	0.37	0.37	0.32	0.09	0.09	0.20	0.20	0.20	0.18	0.15	0.17	0.16	0.15	0.15	0.12
23	मनोरंजन और मनोविनोद	1.68	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04	0.04
24	शिक्षा	4.46	0.26	0.25	0.26	0.26	0.25	0.24	0.25	0.24	0.26	0.24	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21
25	व्यक्तिगत देखभाल और सामान	3.89	0.27	0.27	0.31	0.37	0.36	0.32	0.34	0.38	0.35	0.34	0.30	0.30	0.28	0.23	0.21	0.24
26	**विविध**	**28.32**	**1.62**	**1.65**	**1.69**	**1.75**	**1.74**	**1.61**	**1.35**	**1.37**	**1.45**	**1.40**	**1.22**	**1.19**	**1.13**	**1.05**	**0.99**	**0.98**
27	**सभी समूह**	**100**	**6.77**	**5.88**	**5.72**	**6.52**	**6.44**	**5.66**	**4.70**	**4.31**	**4.87**	**7.44**	**4.87**	**5.55**	**5.69**	**5.10**	**5.09**	**4.85**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

3.22 अखिल भारतीय औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक अल्पकालिक समग्र संकेतक है जो आधार अवधि के संबंध में औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी) विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक डेटा का उपयोग करके आईआईपी संकलित करता है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) प्रमुख स्रोत एजेंसी है।

3.23 आईएमएफ का विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) मानदंडों के अनुसार 6 सप्ताह के समय-अंतराल के साथ हर महीने त्वरित अनुमान के रूप में आईआईपी जारी करता है। खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए सूचकांक के ब्रेक-अप के अतिरिक्त, एनआईसी 2-अंकीय श्रेणियों और उपयोग-आधारित वर्गीकरण (यूबीसी) अर्थात, प्राथमिक सामान, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती सामान, अवसंरचना/निर्माण सामग्री, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता गैर- टिकाऊ के अनुसार अनुमान एक ही समय जारी किए जा रहे हैं। क्षेत्रीय, एनआईसी 2-अंकीय स्तर और यूबीसी श्रेणियों पर प्रेस विज्ञप्ति, सूचकांक और विकास दर, मद समूह स्तर पर सूचकांक और उत्पादन, आधार वर्ष 2011-12 के साथ अखिल भारतीय आईआईपी की कार्यप्रणाली का मेटाडेटा और विवरण सार्वजनिक पहुंच के लिए वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in/iip.2011.12.series) पर उपलब्ध कराया गया है ।

3.24 वर्ष 2012-13 से वर्ष 2023-24 तक औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र-वार वार्षिक सूचकांक और इसकी वृद्धि दर तथा जनवरी 2023 से मार्च 2024 तक और मासिक सूचकांक और वृद्धि दर नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाए गए हैं:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वार्षिक) : 2012-13 से 2023-24: क्षेत्र-वार
चित्र-3

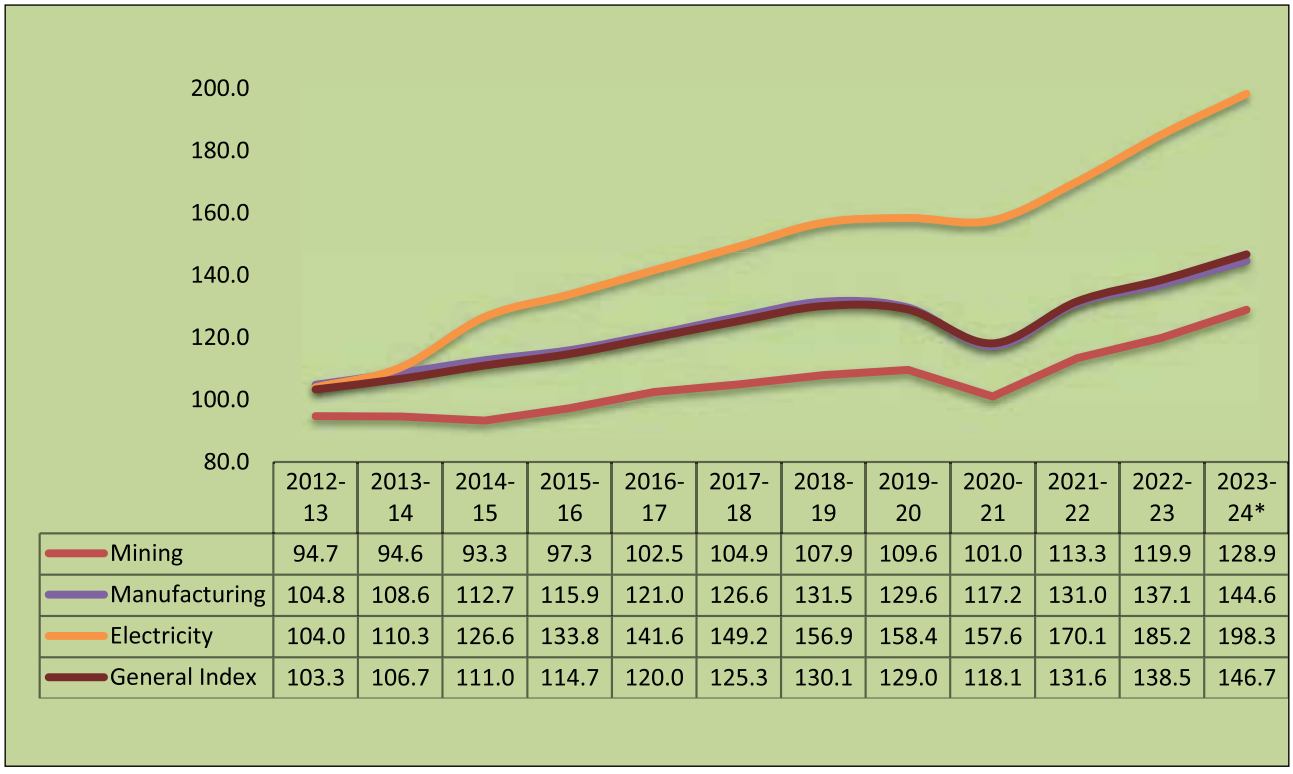

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
Mining	94.7	94.6	93.3	97.3	102.5	104.9	107.9	109.6	101.0	113.3	119.9	128.9
Manufacturing	104.8	108.6	112.7	115.9	121.0	126.6	131.5	129.6	117.2	131.0	137.1	144.6
Electricity	104.0	110.3	126.6	133.8	141.6	149.2	156.9	158.4	157.6	170.1	185.2	198.3
General Index	103.3	106.7	111.0	114.7	120.0	125.3	130.1	129.0	118.1	131.6	138.5	146.7

*अनंतिम

आईआईपी की क्षेत्र-वार वार्षिक वृद्धि दरों (पिछले वर्ष के संबंध में) की तुलना : 2012-13 से 2023-24

चित्र-4

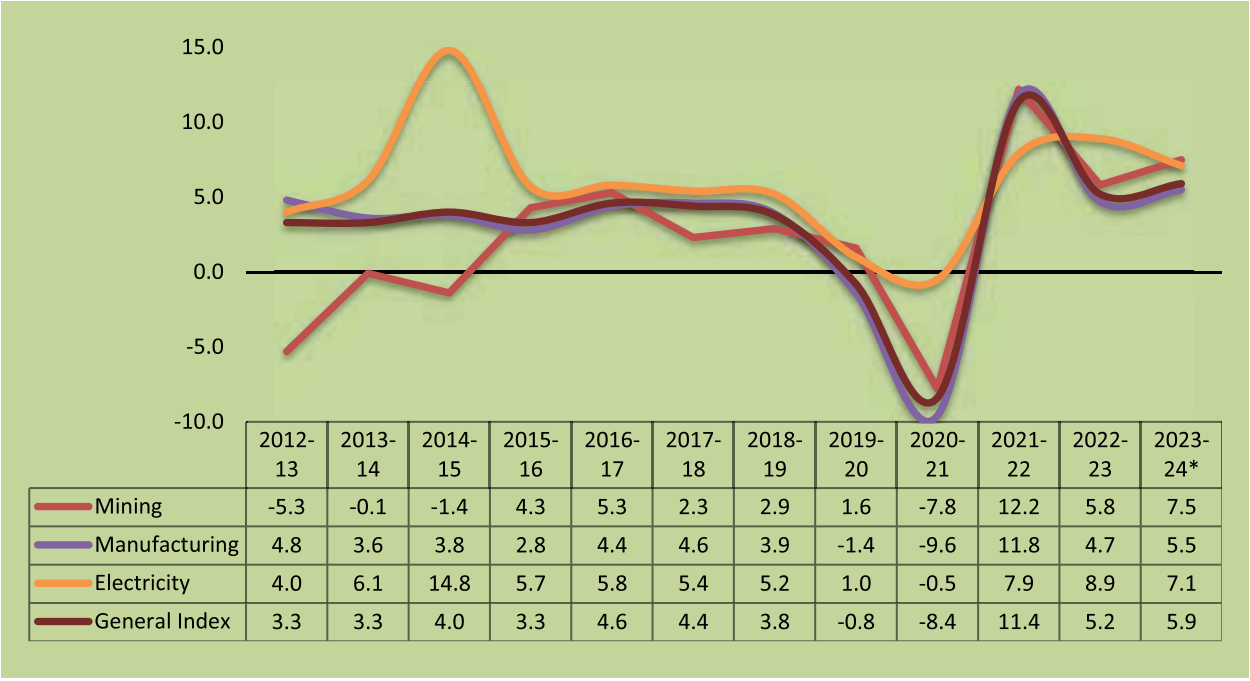

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24*
Mining	-5.3	-0.1	-1.4	4.3	5.3	2.3	2.9	1.6	-7.8	12.2	5.8	7.5
Manufacturing	4.8	3.6	3.8	2.8	4.4	4.6	3.9	-1.4	-9.6	11.8	4.7	5.5
Electricity	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.4	5.2	1.0	-0.5	7.9	8.9	7.1
General Index	3.3	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4	3.8	-0.8	-8.4	11.4	5.2	5.9

*अनंतिम

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मासिक): जनवरी 2023 से मार्च 2024-क्षेत्रीय सूचकांक

चित्र-5

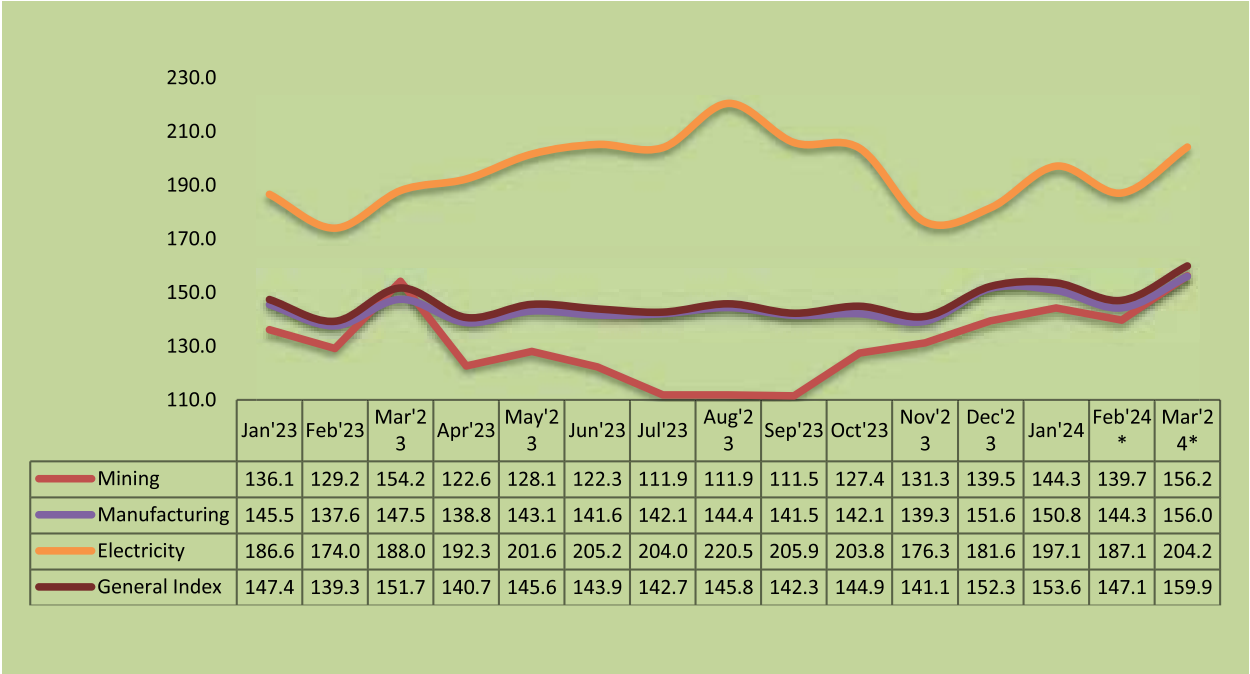

	Jan'23	Feb'23	Mar'23	Apr'23	May'23	Jun'23	Jul'23	Aug'23	Sep'23	Oct'23	Nov'23	Dec'23	Jan'24	Feb'24*	Mar'24*
Mining	136.1	129.2	154.2	122.6	128.1	122.3	111.9	111.9	111.5	127.4	131.3	139.5	144.3	139.7	156.2
Manufacturing	145.5	137.6	147.5	138.8	143.1	141.6	142.1	144.4	141.5	142.1	139.3	151.6	150.8	144.3	156.0
Electricity	186.6	174.0	188.0	192.3	201.6	205.2	204.0	220.5	205.9	203.8	176.3	181.6	197.1	187.1	204.2
General Index	147.4	139.3	151.7	140.7	145.6	143.9	142.7	145.8	142.3	144.9	141.1	152.3	153.6	147.1	159.9

*अनंतिम

क्षेत्र-वार आईआईपी वृद्धि दर (पिछले वर्ष के संबंध में): जनवरी 2023 से मार्च 2024

चित्र-6

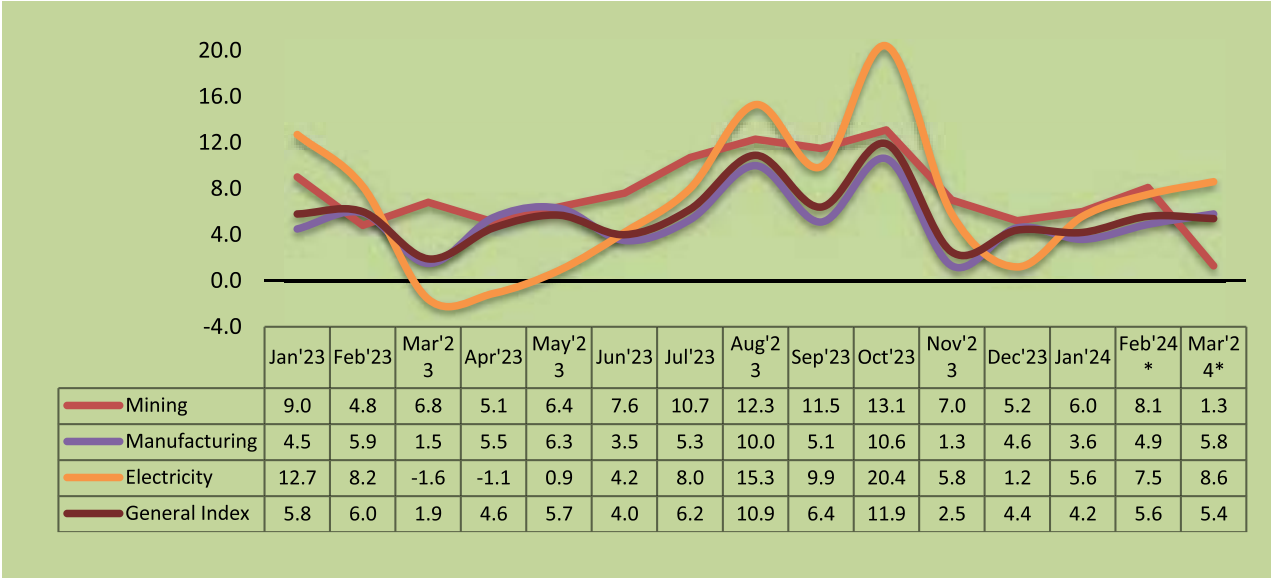

	Jan'23	Feb'23	Mar'23	Apr'23	May'23	Jun'23	Jul'23	Aug'23	Sep'23	Oct'23	Nov'23	Dec'23	Jan'24	Feb'24*	Mar'24*
Mining	9.0	4.8	6.8	5.1	6.4	7.6	10.7	12.3	11.5	13.1	7.0	5.2	6.0	8.1	1.3
Manufacturing	4.5	5.9	1.5	5.5	6.3	3.5	5.3	10.0	5.1	10.6	1.3	4.6	3.6	4.9	5.8
Electricity	12.7	8.2	-1.6	-1.1	0.9	4.2	8.0	15.3	9.9	20.4	5.8	1.2	5.6	7.5	8.6
General Index	5.8	6.0	1.9	4.6	5.7	4.0	6.2	10.9	6.4	11.9	2.5	4.4	4.2	5.6	5.4

*अनंतिम

ऊर्जा सांख्यिकी

3.25 एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया नामक प्रकाशन एनएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग (ईएसडी) द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है। "एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2024" (31वां संस्करण) इस श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है और एक एकीकृत डेटासेट है जिसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की सभी ऊर्जा वस्तुओं (जैसे कोयला, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, आदि) के भंडार, क्षमता, उत्पादन, खपत और आयात/निर्यात के संबंध में विविध महत्वपूर्ण जानकारी शामिल है।

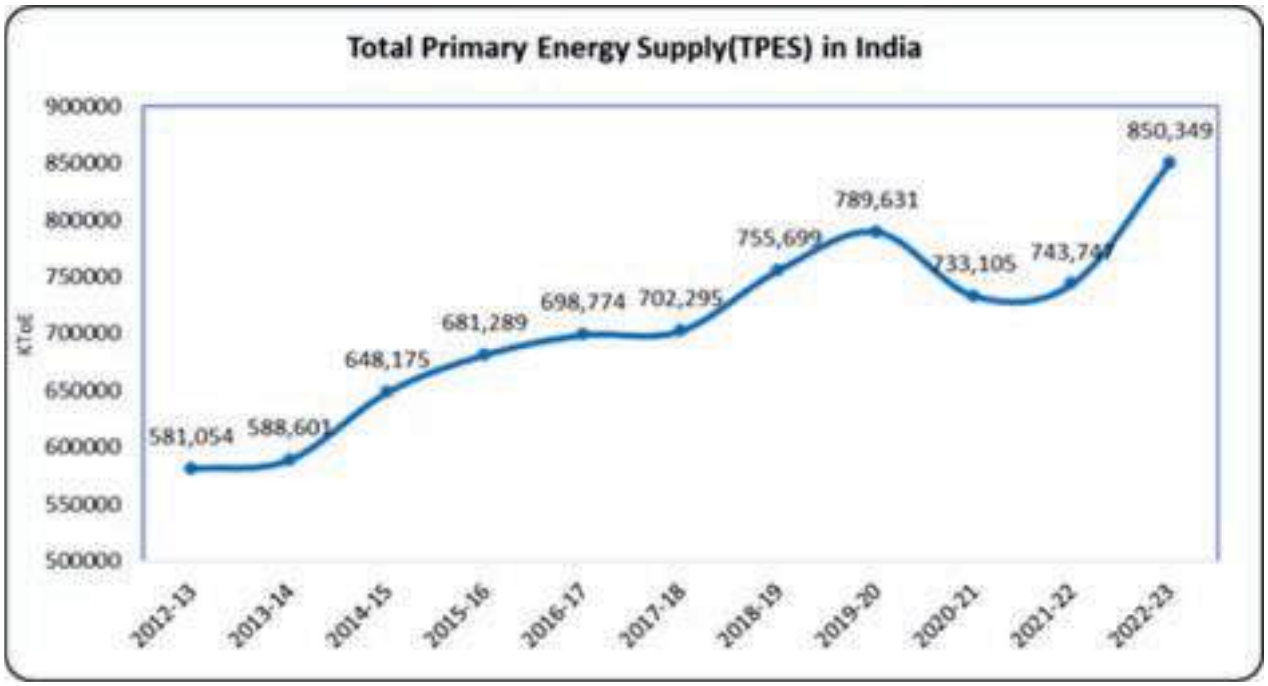

3.26 यह प्रकाशन ऊर्जा डेटा को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराकर योजनाकारों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। इस प्रकाशन में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विभिन्न तालिकाएँ (जैसे ऊर्जा संतुलन), ग्राफ (जैसे सैंकी आरेख) और संधारणीय ऊर्जा संकेतक भी शामिल हैं, जिनका विभिन्न उपयोगकर्ताओं द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा है।

3.27 कोविड-19 के प्रभाव को दरकिनार करते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान उज्ज्वल रूप से चमकती रही, क्योंकि अर्थव्यवस्था की कुल प्राथमिक ऊर्जा आपूर्ति (टीपीईएस) में पिछले वर्ष की तुलना में 14% से अधिक वृद्धि हुई है ।

3.28 वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो 16,999 मेगा जूल/व्यक्ति रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है।

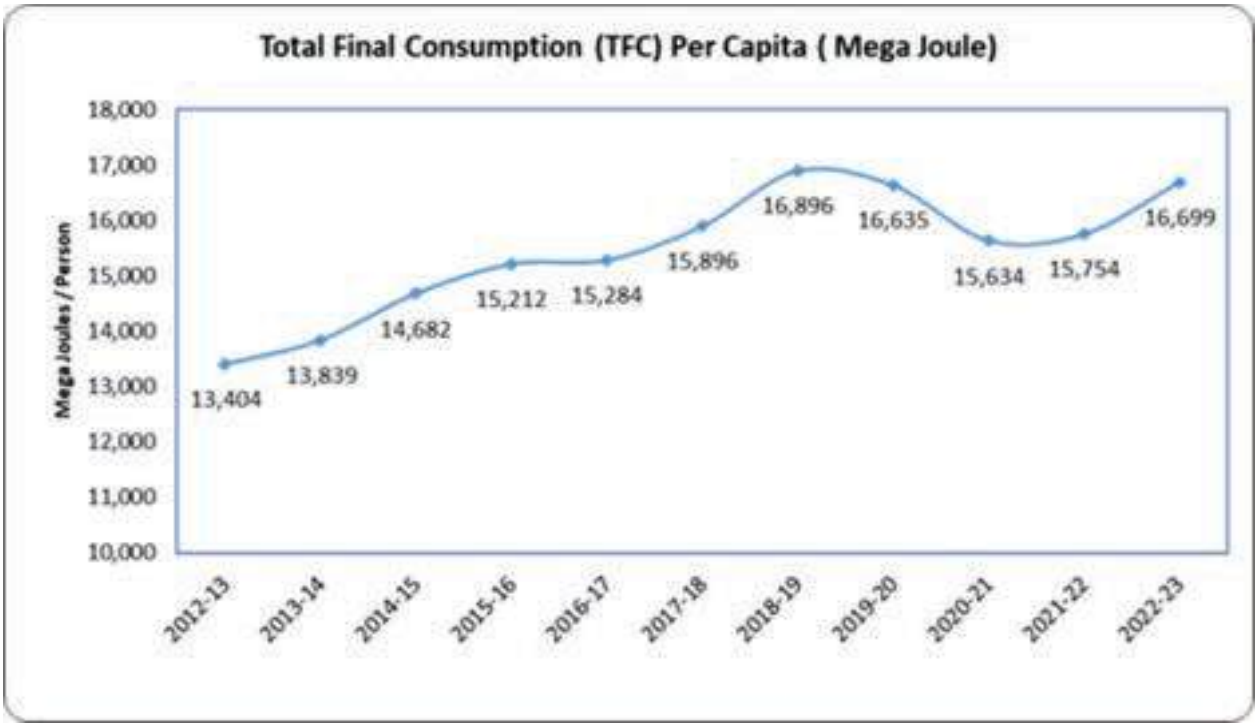

सामाजिक सांख्यिकी

3.29 एनएसओ का सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी) सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु-डोमेन सांख्यिकी के विकास के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, मानव विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय शामिल है जबकि बहु-डोमेन सांख्यिकी में, जेंडर, दिव्यांगजन, और सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) संबंधी संकेतक शामिल हैं।

3.30 प्रभाग समाज, पर्यावरण और ऊपर उल्लिखित मल्टी-डोमेन सांख्यिकी संबंधी विविध विषयों पर वार्षिक और तदर्थ प्रकाशन जारी करता है। प्रभाग राष्ट्रीय सर्वेक्षणों, गणनाओं, प्रशासनिक आंकड़ों, आर्थिक आंकड़ों, रिमोट सेंसिंग एजेंसियों, पर्यावरणीय निगरानी प्रणालियों से प्राप्त सूचनाओं की तुलना करते हुए उन्हें समेकित करता है। इन डेटासेटों को तब इन आंकड़ों के लिए विहित मानक रूपरेखा में सम्मिलित कर दिया जाता है, इस प्रकार समय और स्थान में तुलनीय समय-श्रृंखलाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

3.31 यह प्रभाग ब्रिक्स से संबंधित सांख्यिकीय गतिविधियों के संबंध में भारत के लिए सांख्यिकीय समन्वय के लिए भी उत्तरदायी है और ब्रिक्स सदस्य देशों के बारे में कई सामाजिक और आर्थिक आंकड़ों के प्रसार में सहायता करता है।

3.32 वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभाग द्वारा संचालित विशेष गतिविधियां निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्शायी गई हैं।

सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की दिशा में प्रगति को आगे बढ़ाना और उसकी निगरानी करना

3.33 संयुक्त राष्ट्र ने सितंबर, 2015 में सतत विकास को वर्ष 2030 तक प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने हेतु 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबद्ध लक्ष्यों को अंगीकार किया। एसडीजी के पांच महत्वपूर्ण आयाम हैं- व्यक्ति, समृद्धि, ग्रह, साझेदारी और शांति, इनमें से प्रत्येक को सतत विकास के तीन पहलूओं अर्थात आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय विकास को शामिल करते हुए वैश्विक स्तर पर लागू सतत विकास लक्ष्यों और ध्येयों का उपयोग करके 2030 कार्यसूची में चर्चा की गई ।

वैश्विक स्तर पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने के लिए, वर्ष 2017 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्तमान में 248 संकेतकों (231 विशिष्ट संकेतकों) को शामिल करते हुए एक वैश्विक संकेतक रूपरेखा को अंगीकृत किया गया।

3.34 भारत सरकार "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास" सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें "कोई पीछे न छूट जाए" एसडीजी लक्ष्य के अनुरूप है इस प्रयास में, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. को जीआईएफ के साथ, एसडीजी के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा के विकास को जिम्मेदारी के साथ सौंप दिया गया, जिसका देश में एसडीजी की प्रगति की निगरानी के लिए उपयोग किया जा सकता है।

3.35 सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. ने आरंभ में राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, डेटा स्रोत और आवधिकता के साथ 306 संकेतकों को शामिल करते हुए, सतत विकास लक्ष्यों के लिए एक राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा (एनआईएफ) तैयार की है। राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा मंत्रालयों/सरकारी विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया के आधार पर तैयार की गई है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, एनआईएफ की आवधिक समीक्षा करने और उसमें सुधार लाने के लिए भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् (सीएसआई) और सचिव, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. की अध्यक्षता में नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों के साथ सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. द्वारा एसडीजी पर एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) का गठन किया गया। एचएलएससी के क्षेत्र के अंतर्गत, एचएलएससी को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के लिए महानिदेशक (सांख्यिकी), सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. की अध्यक्षता में मार्च 2020 में सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. द्वारा एसडीजी पर एक तकनीकी सहायता समिति (टीएसी) का गठन किया गया। एनआईएफ में प्रस्तावित किसी संशोधन या एसडीजी से संबंधित किसी नए प्रस्ताव की टीएसी में जांच-पड़ताल की जाती है और टीएसी की संस्तुतियों पर विचार करने के लिए एचएलएससी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। एचएलएससी समय-समय पर एनआईएफ में सुधार करता रहा है। वर्तमान में, एसडीजी-एनआईएफ 2023 में, एसडीजी की प्रगति की निगरानी करने के लिए चिन्हित डेटा स्रोत और आवधिकता (29 जून, 2023 के अनुसार) के साथ 284 राष्ट्रीय संकेतक हैं।

3.36 नवीनतम सतत विकास लक्ष्यों - राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा के आधार पर, सांख्यिकी दिवस (29 जून 2023 को मनाया गया) के अवसर पर निम्नलिखित रिपोर्टें जारी की गईं।

(i) सतत विकास लक्ष्य / राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2023

(ii) सतत विकास लक्ष्य पर डेटा स्नैपशॉट / राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2023

(iii) सतत विकास लक्ष्य / राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा 2023

3.37 एसडीजी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट उद्देश्यों और लक्ष्यों के संबंध में देश द्वारा की गई प्रगति की सांख्यिकीय निगरानी के लिए अभिरक्षक एजेंसियों, केंद्र में नोडल मंत्रालयों, अनुसंधान संस्थानों, राज्य सरकारों और जनता सहित सभी हितधारकों का सक्रिय सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। एसएसडी ने इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कई प्रयास किए और निम्नानुसार विभिन्न कार्यशाला/बैठकें आयोजित कीः

3.38 वर्ष 2023 के दौरान एसडीजी संकेतकों, डाटा संकलन तथा संभव डेटा संकलन की समीक्षा के लिए कई अंतरमंत्रालयी परामर्शों/बैठकों का आयोजन किया गया। विभिन्न राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समितियों और तकनीकी समूहों में प्रभाग की सक्रिय भागीदारी भी रही है।

3.39 यह प्रभाग एक व्यापक और समावेशी एसडीजी निगरानी रूपरेखा तैयार करने में राज्यों को तकनीकी सहयोग प्रदान करता है। इस संदर्भ में , प्रभाग ने जुलाई, 2019 में संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक राज्य स्तरीय निगरानी रूपरेखा तैयार करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने और सहयोग देने हेतु राज्य संकेतक रूपरेखा (एसआईएफ) के विकास के लिए दिशानिर्देश तैयार और परिचालित किए हैं जिन्हें मार्च 2022 में बाद में अद्यतित किया गया था। इस मुद्दे पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

3.40 11-12 दिसंबर, 2023 को गोवा में 'सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और जेंडर सांख्यिकी' पर दो दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के योजना विभाग/अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारी, नीति आयोग के एसडीजी वर्टिकल के अधिकारी, यूएनडीपी के प्रतिनिधि और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारी शामिल हुए।

3.41 निर्धारित किए गए कई लक्ष्यों के लिए लोगों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है, जिसके लिए जागरूकता पैदा करना महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्रचारित करने के लिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2023 के लिए सांख्यिकी दिवस की थीम को "सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा के साथ राज्य संकेतक रूपरेखा का संरेखण" के रूप में घोषित किया।

3.42 सभी स्तरों पर एसडीजी की प्रगति की निगरानी में डेटा के महत्त्व पर विचार करते हुए, एसडीजी पर डेटा अंतराल को पूरा करने हेतु सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। सा. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के कुछ मौजूदा सर्वेक्षणों को एसडीजी डेटा की आवश्यकतानुसार संरेखित किया जा रहा है।

3.43 प्रभाग ने 22 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में "एसडीजी राष्ट्रीय संकेतकों के लिए मील का पत्थर स्थापित करने और अप्राप्त एसडीजी लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय संकेतकों की पहचान पर परामर्श" का आयोजन किया, जिसमें संबंधित डेटा स्रोत एजेंसियों/संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

3.44 सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. ने 3 फरवरी, 2023 से पांच वर्ष की अवधि के लिए "भारत में सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी हेतु डेटा, संकेतक और सांख्यिकी के लिए समर्थन" पर यूएन रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर कार्यालय (यूएनआरसीओ) और नीति आयोग के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन के तहत, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के महानिदेशक (सांख्यिकी) और यूएनआरसीओ की सह-अध्यक्षता में "एसडीजी पर विकास समन्वय मंच के लिए डेटा" की तीसरी बैठक 30 जनवरी, 2024 को नई दिल्ली में आयोजित की गई।

3.45 भारत (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के माध्यम से) 2023-2025 की अवधि के लिए एसडीजी संकेतकों (आईएईजी-एसडीजी) पर अंतर-एजेंसी और विशेषज्ञ समूह में दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आईएईजी-एसडीजी सदस्य देशों और पर्यवेक्षकों के रूप में क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से बना है। आईएईजी- एसडीजी को 2030 एजेंडा के उद्देश्यों और लक्ष्यों के लिए वैश्विक संकेतक रूपरेखा तैयार करने और लागू करने का काम सौंपा गया है।

3.46 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.) के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राव इंद्रजीत सिंह ने अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में दिनांक 15 मार्च, 2023 को "भारत में महिलाएं और पुरुष 2022" शीर्षक से प्रकाशन के 24वें अंक का विमोचन किया, जिसके बाद "नीति निर्माण में जेंडर सांख्यिकी की भूमिका" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया।

पर्यावरण की निगरानी

3.47 भारत में पर्यावरण संबंधी सरकारी सांख्यिकी के संबंध में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के कार्यकलापों को दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जा सकता है-पर्यावरण सांख्यिकी और पर्यावरण लेखा। वर्ष 2023-24 के दौरान प्रभाग द्वारा पर्यावरण सांख्यिकी और लेखा से संबंधित कुछ गतिविधियों पर निम्नलिखित पैराग्राफों में प्रकाश डाला गया है।

पर्यावरण सांख्यिकी

3.48 पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सांख्यिकी सूचना का मिलान करने तथा जारी करने के अपने प्रयासों की निरंतरता में मार्च 2023 में प्रकाशन "एनवीस्टेटस-इंडिया, 2023; वाल्यूम-I-पर्यावरण सांख्यिकी" को जारी किया गया। यह प्रकाशन पर्यावरण सांख्यिकी के संकलनार्थ यूएनएसडी द्वारा विहित पर्यावरण सांख्यिकी के विकास संबंधी ढांचा (एफडीईएस 2013) पर आधारित है तथा छह मौलिक घटकों नामतः (i) पर्यावरण स्थितियां और गुणवत्ता; (ii) पर्यावरण संसाधन और उनका उपयोग; (iii) अवशिष्टों; (iv)चरम घटनाओं और आपदाओं; (v) मानव अवस्थापन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य; और (vi) पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और संलग्नता पर सूचना उपलब्ध कराता है। यह प्रकाशन श्रृंखला में छठा है। नवीनतम प्रकाशन को रूपरेखा के 177 संकेतकों पर प्रदान की गयी सूचना के साथ, एफडीईएस द्वारा विहित संकेतकों की कवरेज को बेहतर बनाया गया है।

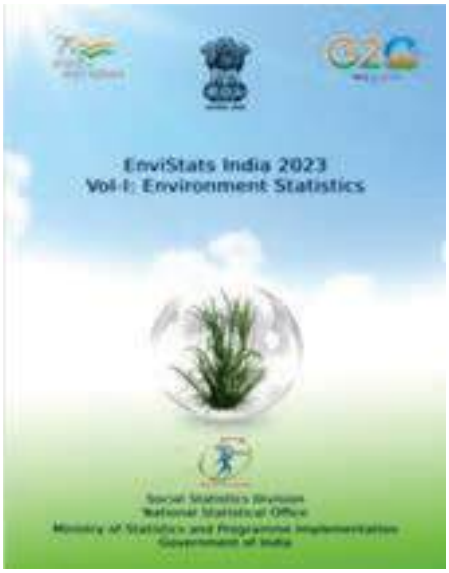

पर्यावरण लेखा

3.49 अपने अधिदेश के अनुपालन के साथ और पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने के लिए, प्रभाग ने पर्यावरण-आर्थिक लेखा रूपरेखा (एसईईए) की प्रणाली का अनुसरण करते हुए सितंबर 2023 में "एनविस्टेट्स इंडिया 2023 वॉल्यूम II: पर्यावरण लेखा" शीर्षक से पर्यावरण लेखाओं पर वार्षिक प्रकाशन का लगातार छठा अंक जारी किया है। वर्तमान प्रकाशन में कई नए विषय शामिल हैं जैसे सामग्री प्रवाह लेखा और वनों द्वारा मृदा कटाव रोकथाम सेवाओं संबंधी लेखा के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट लेखा और मछली प्रावधान सेवाओं संबंधी अद्यतन। इसके अलावा, प्रभाग ने मई, 2023 में क्रॉपलैंड द्वारा प्रदान की जाने वाली मृदा कटाव रोकथाम सेवाओं पर व्याख्याता श्रृंखला भी जारी की।

3.50 दस्तावेज विशेष रूप से वास्तविक रूप में क्रॉपलैंड द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (नियामक) के बारे में विस्तार से बताता है। प्रभाग ने 'एनवीस्टेट्स इंडिया-शब्दावली' (मार्च 2024) के अद्यतित संस्करण भी प्रकाशित किए, जिसमें पर्यावरण लेखांकन में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की परिभाषा शामिल है और 'एनवीस्टेट्स इंडिया-अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न' (जनवरी 2024) में पर्यावरण लेखांकन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य एनवीस्टेट्स इंडिया के उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं की बेहतर समझ प्रदान करना और इसके लिए जागरूकता पैदा करने में सहायता करना है।

3.51 प्रभाग ने भारत में पर्यावरण लेखों के महत्व को उजागर करने के उद्देश्य से कई सेमिनार और कार्यशालाएँ भी आयोजित कीं। 1-15 जुलाई 2023 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा 2023 के उत्सव के तहत, 3 जुलाई, 2023 को भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र (आईआईसी), लोधी रोड, नई दिल्ली में 'अवशिष्ट लेखा और सतत विकास लक्ष्यों के साथ इसके संबंध' पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया।

3.52 इसके अलावा, पर्यावरण-आर्थिक लेखा रूपरेखा (एसईईए) की प्रणाली का उपयोग करके पर्यावरण लेखाओं के संकलन के महत्व के विषय में राज्य स्तर पर अधिकारियों को जागरूक करने के लिए, एसएसडी, एनएसओ के तकनीकी सहयोग से डीईएस, छत्तीसगढ़ द्वारा मार्च, 2023 के दौरान अखिल भारतीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ओडिशा सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लिए दो दिवसीय क्षमता विकास कार्यशाला 30-31 अक्टूबर, 2023 को भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की गई और लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित दक्षिणी राज्यों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशाला 19-20 फरवरी, 2024 के दौरान ममल्लापुरम, तमिलनाडु में आयोजित की गई।

3.53 भारत जेंडर सांख्यिकी पर अंतर-एजेंसी और विशेषज्ञ समूह (आईएईजी-जीएस) का सदस्य है। सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इसके विकास को समझने और भारत के दृष्टिकोण को सामने रखने के लिए आईएईजी-जीएस की बैठकों और जेंडर सांख्यिकी संबंधी अन्य सम्मेलनों/मंचों में भाग लेता है। आईएईजी-जीएस की 17वीं बैठक 28 अगस्त, 2023 को जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई, जिसमें सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.ने विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में भाग लिया।

3.54 भारत दिव्यांगता सांख्यिकी पर वाशिंगटन समूह का सदस्य भी है जो गणना और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के लिए उपयुक्त दिव्यांगता उपायों के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य सांख्यिकी के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है और समन्वय करता है। वाशिंगटन समूह का प्रमुख उद्देश्य दिव्यांगता के बारे में ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो विश्व भर में तुलनीय हो। भारत समूह की सभी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।

3.55 इन आंकड़ों के प्रसार और क्षमता विकास में प्रभाग द्वारा 2023-24 के दौरान संचालित की गई कुछ गतिविधियाँ आगामी पैराग्राफ में विस्तारपूर्वक दी गई हैं ।

3.56 वार्षिक प्रकाशन "भारत में महिलाएं तथा पुरूष 2022" के नाम से मार्च 2023 में प्रकाशित किया गया था। यह प्रकाशन स्वास्थ्य, साक्षरता और शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णयन तथा सशक्तिकरण में बाधाएं सहित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलूओं के संबंध में जेंडर के आधार पर अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध कराता है। प्रकाशन में जेंडर संकेतकों के न्यूनतम सेट के अंतर्गत आईएईजी-जीएस द्वारा निर्धारण के अनुसार, कई परिमाणात्मक संकेतकों से संबंधित सूचना को शामिल किया जाता है। चालू वर्ष के प्रकाशन में सतत् विकास लक्ष्य और जेंडर पर एक नया अध्याय जोड़ा गया है।

3.57 ब्रिक्स देशों की सांख्यिकी डेटा श्रृंखला, जो एक वार्षिक संयुक्त सांख्यिकीय प्रकाशन (जेएसपी) के रूप में जारी की गई, वर्ष 2010 से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रीय सांख्यिकीय अधिकारियों के वार्षिक संयुक्त प्रयास का परिणाम है। यह प्रकाशन (जेएसपी) पांच देशों के मुख्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों का व्यापक सांख्यिकीय डाटा प्रदान करता है। सांख्यिकी दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन (जेएसपी) 2023 के संबंध में निम्नलिखित बैठकें आयोजित की गईं।

3.58 ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) की 15वीं तकनीकी बैठक 17 से 19 अप्रैल, 2023 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई।

3.59 ब्रिक्स देशों के एनएसओ के प्रमुखों की 15वीं बैठक 11-13 अक्टूबर, 2023 के दौरान दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई।

अंतर, अंतरा और अंतरराष्ट्रीय समन्वय इकाई (आईआईआईसीयू)

3.60 अंतर अंतरा अंतरराष्ट्रीय समन्वय इकाई (आईआईआईसीयू) केंद्रीय सरकार मंत्रालयों/विभागों और साथ ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) के विभिन्न प्रभागों के समन्वय संबंधित कार्य कर रही है । यह सांख्यिकी संग्रहण (सीओएस) अधिनियम, 2008 और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) अधिनियम, 1959 को लागू करता है तथा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करता है। यह क्षमता विकास (सीडी) योजना, मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसओ के प्रभागों में) के लिए समन्वय इकाई के रूप में भी कार्य करता है। जिसका उद्देश्य नीति-निर्माताओं और बड़े पैमाने पर जनता के लिए विश्वसनीय और सामयिक आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचनात्मक, तकनीकी और जनशक्ति संसाधनों में वृद्धि करना है।

3.61 नियमित समन्वय गतिविधियों के अलावा, वर्ष 2023 (मार्च 2024 तक) के दौरान इकाई द्वारा संचालित मुख्य गतिविधियां आगामी पैराग्राफ में इंगित हैं।

सांख्यिकी दिवस

3.62 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.) ने 29 जून, 2023 को स्कोप कन्वेंशन सेंटर, स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में 17वां सांख्यिकी दिवस मनाया। "सांख्यिकी दिवस" 2023 का विषय "सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा के साथ राज्य संकेतक रूपरेखा का संरेखण" था।

3.63 कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा.), योजना मंत्रालय और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राव इंद्रजीत सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के अध्यक्ष प्रो. राजीव लक्ष्मण करंदीकर और भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के सचिव डॉ. जी. पी. सामंता ने भी प्रतिभागियों को संबोधित किया। सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. के वरिष्ठ अधिकारी, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के प्रतिनिधि, संयुक्त राष्ट्र संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम को मंत्रालय के सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान 'ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता, 2023' के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया।

3.64 सांख्यिकी दिवस, 2023 की थीम पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उप महानिदेशक डॉ. आशुतोष ओझा ने संक्षिप्त प्रस्तुति दी। भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर श्री शोम्बी शार्प, नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. योगेश सूरी और नीति आयोग के निदेशक श्री राजेश गुप्ता ने भी प्रतिभागियों को सांख्यिकी दिवस, 2023 की थीम पर संबोधित किया।

(बाएं से दाएं) श्री ए.के. बिस्वास, (महानिदेशक), प्रो. आर.एल. करंदीकर (अध्यक्ष, एनएससी), राव इंद्रजीत सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना और राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, डॉ. जी.पी. सामंता (सीएसआई और सचिव) और श्री घन श्याम, (एडीजी)

राव इंद्रजीत सिंह, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना और राज्य मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय।

3.65 कार्यक्रम के दौरान सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा, प्रगति रिपोर्ट, 2023 जारी की गई। रिपोर्ट के साथ-साथ, सतत विकास लक्ष्य-राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा, 2023 पर डेटा स्नैपशॉट भी जारी किया गया। रिपोर्ट में लक्ष्य-वार डेटा को एक्सेल फाइल में सां. और कार्य. कार्या. मंत्रा. की वेबसाइट से डाउनलोड करने का प्रावधान है।

3.66 भारत को लगभग दो दशकों के अंतराल के बाद वर्ष 2024-27 की चार वर्ष की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया ।

अध्याय - 4

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)

4.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय आधार पर व्यापक स्तर के प्रतिदर्श सर्वेक्षण संचालित करने के लिए जिम्मेदार है। एनएसएसओ अपने सर्वेक्षणों के आधार पर डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और परिणामों/डेटा के प्रकाशन/प्रसार से संबंधित मामलों में अपेक्षित स्वायत्तता के साथ कार्य करता है। महानिदेशक (एनएसएस) एनएसएसओ की सभी गतिविधियों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है, जिन्हें चार अपर महानिदेशकों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, प्रत्येक एक अलग प्रभाग का प्रभारी होता है जो बड़े पैमाने पर सर्वेक्षणों के विभिन्न पहलुओं जैसे अभिकल्प और नियोजन, क्षेत्रीय कार्य/आंकड़ा संग्रहण, आंकड़ा प्रसंस्करण और एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों के बीच समन्वय के लिए उत्तरदायी होता है।

एनएनएसओ के प्रभागः

4.2 दिल्ली में मुख्यालय वाला सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग (एससीडी) एनएसएस के विभिन्न प्रभागों नामतःसर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसन्धान प्रभाग (एसडीआरडी), क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग (एफओडी) और समंक विधायन प्रभाग (डीपीडी) की सभी गतिविधियों का समन्वय करता है। यह महानिदेशक (एनएसएसओ) के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। इसके अलावा, एससीडी एनएसएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सेमीनार के आयोजन के लिए भी जिम्मेदार है। यह एनएसएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षण' भी प्रकाशित करता है जिसमें एनएसएसओ के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों पर शोध पत्र शामिल हैं।

4.3 सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी) कोलकाता में स्थित है। इस प्रभाग पर सर्वेक्षण के लिए तकनीकी योजना बनाने, प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को तैयार करने, सारणीयन योजना तैयार करने तथा परिणामों का विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार करने का दायित्व है।

4.4 क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) का मुख्यालय फरीदाबाद में कृषि संबंधी सांख्यिकीय विंग के साथ दिल्ली में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 53 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 116 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए गए सर्वेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है।

4.5 समंक विधायन प्रभाग (डीपीडी) का मुख्यालय कोलकाता में है। अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, गिरीडीह तथा नागपुर में इसके छह समंक विधायन केन्द्र हैं। यह प्रतिदर्श चयन, सॉफ्टवेयर विकास,सर्वेक्षणों के आंकड़ों की गुणवत्ता की ऑनलाइन जांच और उनका संसाधानिकरण तथा सर्वेक्षणों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के संसाधन एवं सारणीयन के लिए उत्तरदायी है। यह राज्यों को सभी समंक विधायन संबंधी गतिविधियों में आईटी समाधान द्वारा तथा आवधिक प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा अन्य परस्पर संवादात्मक तरीके से भी सहायता करता है। औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध भी इस प्रभाग के अधीन कार्य करता है। औद्योगिक सांखियिकी स्कंध का मुख्य कार्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के संबंध में प्रतिदर्श, अभिकल्प, डाटा मान्यकरण, डाटा संसधानिकरण और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के परिणामों को अंतिम रूप देना है, जो भारत में औद्योगिक सांख्यिकी का एक प्रमुख स्रोत है। समर्पित एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उनका रख-रखाव किया जाता है, जिसके कारण समय बचने के साथ-साथ सही आंकड़ों का पता चलता है। यह पोर्टल वार्षिक आंकड़ों को बिना किसी वास्तविक छेड़छाड़ के समय पर, पारदर्शी रूप से तथा कार्यक्रम में विश्वसनीय तरीके से सुरक्षित वातावरण में प्रस्तुत करने में सहायता करता है।

एनएसएस के नए दौर के लिए कार्य समूह

4.6 श्री प्रवीण श्रीवास्तव, पूर्व सीएसआई-सह-सचिव, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय की अध्यक्षता में 26 मार्च 2021 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनएसएसओ 79वें दौर के कार्य समूह (डब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। कार्यकारी समूह ने एनएसएस 79वें दौर के सर्वेक्षणों के विभिन्न पहलूओं पर विचार विमर्श करने के लिए अनेक बैठकों का आयोजन किया है। डब्ल्यूजी का उदेश्य एनएसएस 79वें दौर के सर्वेक्षणों के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर गतिविधियों के संपूर्ण पहलुओं जैसे प्रतिदर्श डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति आदि निर्धारित करना पर विचार करना,उनका विकास करना और तैयार करना है।

4.7 सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय ने दिनांक 10 फरवरी 2020 को श्री प्रणव सेन, कार्यक्रम निदेशक, अंतरराष्ट्रीय वृद्धि केंद्र, नई दिल्ली की अध्यक्षता में घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) के लिए कार्यकारी समूह का गठन किया था। डब्ल्यूजी ने सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए कई बैठकें कीं है। डब्ल्यूजी का उदेश्य सर्वेक्षण के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर गतिविधियों के संपूर्ण पहलुओं जैसे प्रतिदर्श डिजाइन, सर्वेक्षण पद्धति आदि निर्धारित करना पर विचार करना,उनका विकास करना और तैयार करना है।

सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति (एससीओएस)

4.8 सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीओएस) का गठन 13 जुलाई 2023 को आर्थिक सांख्यिकी पर स्थायी समिति (एससीईएस) का नाम बदलकर और इसके संदर्भ की शर्तों (टीओआर) को बढ़ाकर किया गया ताकि अधिक कवरेज सुनिश्चित किया जा सके। समिति की स्थापना डॉ. प्रणव सेन, पूर्व कार्यक्रम निदेशक, भारत टीम शोधकर्ता, अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र, नई दिल्ली की अध्यक्षता में की गई है। समिति मौजूदा ढांचे की समीक्षा करेगी और समय-समय पर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एससीओएस के समक्ष लाए गए सभी सर्वेक्षणों से संबंधित विषयों/परिणामों/पद्धति आदि पर उठाए गए मुद्दों का समाधान करेगी।

एनएसएसओ के द्वारा संचालित सर्वेक्षण

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण

4.9 एनएसएस का 78वां दौर (जनवरी-दिसम्बर 2020) (i) घरेलू पर्यटन व्यय और (ii) बहु संकेतक सर्वेक्षण के विषयों को समर्पित था। 'घरेलू पर्यटन पर सर्वेक्षण' पर्यटन मंत्रालय द्वारा किए गए अनुरोधों के कारण दिनांक 1 जुलाई, 2020 से स्थगित था। बहु संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) का उदेश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), 2030 के कुछ महत्वपूर्ण संकेतकों से संबंधित अनुमान उपलब्ध करवाना था। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्षों को एक रिपोर्ट के रूप में शामिल किया गया है जिसका शीर्षक है: 'मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, 2020-21 पर रिपोर्ट' (एनएसएस रिपोर्ट संख्या 589) मार्च 2023 में जारी की जाएगी। यह रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट (http://mospi.gov.in) पर उपलब्ध है।

4.10 एनएसएस का 79वां दौर (जुलाई 2022-जून 2023) (i) व्यापक वार्षिक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएएमएस) और (ii) आयूष पर सर्वेक्षण के विषयों को समर्पित है। सीएएमएस का उद्देश्य कुछ एसडीजी संकेतक और वैश्विक सूचकांकों के उप-संकेतक बनाने के उद्देश्य से आवश्यक जानकारी एकत्र करना है। केंद्रीय नमूने के लिए डेटा का संग्रह ई सिग्मा प्लेटफॉर्म पर कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) पद्धति के माध्यम से किया गया है। फील्ड वर्क जून 2023 में पूरा हो गया था।

उप महानिदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय पटना द्वारा सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के 79वें दौर का क्षेत्र निरीक्षण

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के लिए राज्य सहायता

4.11 राज्य भी एनएसएसओ के सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं। डीपीडी ने राज्यों को जानकारी साझा करने और अपने प्रत्यनों की ओर तकनीकी सहायता की सुविधा प्रदान करने में अपनी विशेषज्ञता का हमेशा लाभ उठाया है। डीपीडी डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रूमेंट (प्रतिदर्श सूची, डाटा प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर, मान्यकरण तथा सारणीकरण सहित) उपलब्ध करवाकर राज्यों को सभी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन मुहैया कराती है और इस प्रकार से सारणीयन और पूलिंग कार्यशालाओ का आयोजन करके राज्यीय सैंपल आंकड़ों को संसाधित करने के साथ-साथ केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श आंकड़ों को पूलिंग में सहायता प्रदान करता हैं।

4.12 डीपीडी द्वारा 19 से 21 मार्च 2024 के दौरान आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय के 27 पदाधिकारियों के लिए एनएसएसओ के 78 वें दौर के केन्द्रीय तथा राज्यीय प्रतिदर्श डाटा पर एक सारणीयन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यशाला में सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जब कभी भी राज्यीय डीईएस द्वारा अनुरोध किया गया, डीपीडी द्वारा राज्यों के लिए विशेषीकृत आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं ।

4.13 घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस), 2023-24 की डेटा प्रोसेसिंग कार्यशाला 21-22 फरवरी 2024 के दौरान डेटा प्रोसेसिंग (डीपीडी) मुख्यालय, कोलकाता में आयोजित की गई। एचसीईएस डेटा के प्रसंस्करण में शामिल डेटा प्रोसेसिंग सेंटर (डीपीसी) नागपुर और डीपीसी दिल्ली ने कार्यशाला में भाग लिया।

4.14 एनएसएस के 71वें से 76वें दौर के लिए राज्य कार्यशाला मई 2023 के महीने में डीईएस नागालैंड, डीईएस त्रिपुरा के लिए आयोजित की गई थी।

4.15 एनएसएस के 76वें से 77वें दौर के लिए राज्य कार्यशाला अक्टूबर 2023 के महीने में डीईएस अरुणाचल प्रदेश, डीईएस छत्तीसगढ़ और डीईएस सिक्किम के लिए आयोजित की गई थी।

घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) 2022-24:

4.16 एचसीईएस (अगस्त 2022 - जुलाई 2023) परिवारों के उपभोग व्यय के विषय के लिए समर्पित है। एचसीईएस का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी भारत के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के संकलन के लिए कुल उपभोग में विभिन्न वस्तु समूहों के बजट शेयरों के निर्धारण के माध्यम से भार आरेख तैयार करना है। एचसीईएस का सर्वेक्षण कार्य 1 अगस्त 2022 को शुरू किया गया था। फील्ड वर्क जुलाई, 2023 में पूरा हो गया और एचसीईएस 2022-23 के लिए फैक्टशीट फरवरी 2024 में जारी की गई। एचसीईएस 2023-24 का सर्वेक्षण कार्य अगस्त 2023 से सीएपीआई मोड का उपयोग करके शुरू हो गया है।

असंगठित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसइ)

4.17 एएसयूएसइ 2023-24 को अक्टूबर 2023 से सिग्मा प्लेटफॉर्म पर सीएपीआई पद्धति का उपयोग करके लॉन्च किया गया है, जिसमें भारत के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवाओं से संबंधित असंगठित गैर कृषि क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को शामिल किया गया है। 1 अक्टूबर 2022 से शुरू किए गए एएसयूएसइ 2022-23 का फील्डवर्क सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है।

समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस):

4.18 समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) जनसंख्या द्वारा विभिन्न गतिविधियों पर समय व्यय को मापने के लिए बनाया गया है। यह सर्वेक्षण घरेलू सदस्यों द्वारा अवैतनिक देखभाल गतिविधियों, अवैतनिक स्वयंसेवी कार्य, अवैतनिक घरेलू सेवा उत्पादन गतिविधियों में बिताए गए समय की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने जनवरी-दिसंबर 2019 के दौरान पहला समय उपयोग सर्वेक्षण किया। दूसरे समय उपयोग सर्वेक्षण (जनवरी-दिसंबर 2024) का क्षेत्र कार्य पहले ही 1 जनवरी 2024 से ई सिग्मा के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शुरू हो चुका है जैसा कि पहले दौर में किया गया था और हैंड-हेल्ड डिवाइस टैबलेट के माध्यम से कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) मोड में प्रचार किया गया।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस)

4.19 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) अप्रैल 2017 से राष्ट्रव्यापी रूप से आरंभ किया गया। पीएलएफएस के मुख्यतः दोहरे उद्देश्य हैं (i) वर्तमान साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यूएस) में केवल शहरी क्षेत्रों के लिए तीन महीनों के थोड़े समय के अंतराल में श्रमबल संकेतकों को मापना (ii) ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए और शहरी क्षेत्रों हेतु तीन महीनों के लिए सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति. सहायक स्थिति) और सीडब्ल्यूएस वार्षिक दोनों तरह से सभी महत्वपूर्ण श्रम शक्ति मापदंडों का अनुमान लगाना।

4.20 शहरी क्षेत्रों में पीएलएफएस के लिए घूर्णी पैनल प्रतिदर्श डिजाइन का उपयोग किया जा रहा है। दो साल की अवधि की घूर्णी योजना में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए प्रतिदर्श फ्रेम अपरिवर्तित रहता है। जो पैनल दो साल से उपयोग में था, उसे जुलाई, 2021 से एक अपडेटेड पैनल से बदल दिया गया है। अद्यतित पैनल जुलाई 2023 तक अपरिवर्तित रहेगा।

4.21 पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट, 2021-2022 फरवरी, 2023 में जारी की गई और पीएलएफएस की वार्षिक रिपोर्ट, 2022-23 अक्टूबर, 2023 में जारी की गई। इनके अलावा, पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 की अतिरिक्त तालिकाएं जनवरी, 2024 में जारी की गई हैं और जनवरी-दिसंबर, 2023 के लिए प्रमुख रोजगार-बेरोजगारी संकेतक मार्च, 2024 में जारी किए गए हैं।त्रैमासिक बुलेटिन जारी करने में लगने वाला समय क्षेत्र कार्य पूरा होने से दो महीने से भी कम रह गया है। 2023-24 के दौरान पीएलएफएस के निम्नलिखित त्रैमासिक बुलेटिन जारी किए गए हैं।

क्र.सं.	तिमाही बुलेटिन(क्यू बी)	जारी करने का माह
1.	पीएलएफएस क्यूबी अक्टूबर-दिसम्बर, 2023	फरवरी 2023
2.	पीएलएफएस क्यूबी जनवरी-मार्च, 2023	मई 2023
3.	पीएलएफएस क्यूबी अप्रैल-जून, 2023	अक्टूबर 2023
4.	पीएलएफएस क्यूबी जुलाई-सितम्बर, 2023	नवम्बर 2023
5.	पीएलएफएस क्यूबी अक्टूबर-दिसम्बर, 2023	फरवरी 2024

उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसआई)

4.22 भारत में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है। यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र के गठन और संरचना, वृद्धि संबंधी परिवर्तन और यथार्थ रूप से निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, बिजली का पारेषण आदि, गैस एवं जल आपूर्ति तथा कोल्डस्टोरेज से जुड़े कार्यकलाप शामिल हैं। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक है।

4.23 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पूरे भारत में किया जाता है। सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) तथा 2 एम (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कारखाने शामिल हैं।

सर्वेक्षण में बीड़ी एवं सिगार कामगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीड़ी एवं सिगार निर्माणकारी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जाता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे सभी बिजली उपक्रम, उनके रोजगार का आकार चाहे कुछ भी हो, वर्ष 1997-98 तक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे। कोल्डस्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा घड़ी आदि जैसी उपभोग की अन्य टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत जैसी कुछ सेवाओं और कार्यकलापों को सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है। रक्षा प्रतिष्ठानों, तेल भंडारण तथा वितरण डिपो, जलपान-गृहों, होटलों, कैफे और कम्प्यूटर सेवाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को भी सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत बिजली उपक्रमों को वर्ष 1998-99 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है तथापि, वे कैप्टिव इकाईयां जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल होना जारी रखेंगी।

4.24 उक्त के अलावा, अब एएसआई की कवरेज का एएसआई के प्रतिचयन डिजाइन संबंधी उप-समूह द्वारा संस्तुति के अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) के अनुसार बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के दायरे से परे विस्तार किया गया है। इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों के लिए तैयार किए गए प्रतिष्ठान कार्य रजिस्टर (बीआरई) तथा छठी आर्थिक गणना आधारित प्रतिष्ठान निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग किया जाएगा।

4.25 जहां तक संवर्धित ढ़ांचे के कार्यान्वयन की बात है 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कारखाना अधिनियम, जिसे 1948 की धारा 2 एम (i) तथा 2 एम (ii) के तहत पंजीकृत नहीं किया गया परंतु संबंधित राज्यों के बीआरई में शामिल इकाइयों को एएसआई फ्रेम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए, आंध्र प्रदेश के बीआरई को एएसआई 2014-15 के लिए आंध्र प्रदेश के फ्रेम में शामिल किया गया तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान के बीआरई को एएसआई 2015-16 के लिए संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया और एफओडी द्वारा ऐसी इकाईयों का सत्यापन करने के पश्चात गुजरात, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की बीआरई को एएसआई 2017-18 हेतु संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया। यह पिछली पद्धति से महत्वपूर्ण प्रस्थान है तथा पंजीकृत विनिर्माण सेक्टर की कवरेज में सुधार लाता है।

4.26 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े पूंजी, रोजगार तथा परिलब्धियों, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स की खपत, कच्चा माल एवं अन्य लागत/उत्पादन, मूल्यवर्धन, श्रम टर्नओवर और कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से सम्बद्ध है। केंद्रीय प्रतिदर्श के लिए फील्डवर्क के क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है। आईएस विंग आंकड़ों को संसाधित करता है और परिणाम प्रकाशित करता है। एएसआई 2022-23 का क्षेत्रीय कार्य दिसम्बर 2023 से आरम्भ हो चुका है।

4.27 एएसआई 2020-21 और एएसआई 2021-22 (फैक्ट्री सेक्टर के लिए खंड I और सारांश परिणाम) के अंतिम परिणाम फरवरी, 2024 में मंत्रालय की वेबसाइट पर जारी किए गए हैं। एएसआई प्रकाशन (फैक्ट्री सेक्टर के लिए खंड I और सारांश परिणाम) और इकाई स्तर के आंकड़े मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) पर उपलब्ध हैं। ये प्रकाशन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उपयोगकर्ताओं के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं और मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में राज्यों की भागीदारी

4.28 राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को एएसआई में भागीदारी के प्रयोजनों से आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है। अन्य इच्छुक राज्यों के साथ प्रतिभागी राज्यों को एएसआई सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिदर्श सूची मुहैय्या कराई गयी है। डीपीडी के आईएस विंग राज्यों को सभी सर्वेक्षण और आंकड़ा विधायन साधन (प्रतिदर्श सूची, शेड्यूल, अनुदेश पुस्तिका, आंकड़ा प्रविष्टि पैकेज (ई-शेड्यूल), वैधीकरण नियम, वैधीकरण सॉफ्टवेर, पूलिंग कार्यप्रणाली आदि) उपलब्ध कराता है। संबंधित राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिदर्श यूनिट स्तरीय आंकड़े भी राज्य डीईएस के साथ साझा किए गए थे ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रतिदर्शों को उन्नत करके जिला/माइक्रों स्तरीय अनुमानों को तैयार करने में उन्हें सशक्त किया जा सके।

4.29 हाल के दिनों में एएसआई डेटा संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार में सुधार के लिए कई बदलाव किए गए हैं पिछले कुछ दशकों में, पंजीकृत कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई और इसके परिणामस्वरूप उन इकाइयों की संख्या में वृद्धि हुई जहाँ से आंकड़ों का प्रत्येक वर्ष संग्रह और विश्लेषण किया जाने हैस एफओडी, एनएसएसओ की परिचालन बाधाओं को ध्यान में रखते हुए एएसआई में नमूना आकार क्रमशः एएसआई 2017-18, एएसआई 2018-19, एएसआई 2019-20, एएसआई 2020-21 और 2021-22 के दौरान 76, 613, 77, 919, 77, 737, 79, 589 और 80, 764 इकाइयां रखी गईं। एएसआई 2022-23 में, 62, 746 जनगणना इकाइयों और 19, 956 नमूना इकाइयों वाली 82, 702 इकाइयों को सर्वेक्षण के लिए चुना गया है। एएसआई 2012-13 से शुरू होकर, सर्वेक्षण एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

सचिव एवं भारत के मुख्य सांख्यिकीविद, सां. और कार्य. कार्या. मंत्रालय द्वारा दिनांक 11 मई 2023 को कोलकता में औद्योगिक सांख्यिकी पर 11 वे राष्ट्रीय सेमीनार में संबोधन

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणामों की झलक

4.30 एएसआई 2020-21 और एएसआई 2021-22 (फैक्टरी क्षेत्र के लिए खंड-I, खंड-सस, और सारांश परिणाम) के अंतिम परिणाम फरवरी, 2024 में जारी किए गए। एएसआई 2020-21 और एएसआई 2021-22 में पूरे देश को शामिल किया गया। एएसआई 2021-22 के लिए क्षेत्रीय कार्य मार्च 2023 से सितंबर, 2023 की अवधि के दौरान पूरे देश में किया गया था, जिसमें संदर्भ अवधि वित्तीय वर्ष 2021-22 के साथ मेल खाती थी। एएसआई 2020-21 के परिणामों के प्रमुख बिन्दु नीचे दिए गए हैं:

(क) 2021-22 के दौरान, कारखानों की अनुमानित संख्या 2,49,987 थी।

(ख) इन फैक्ट्रियों में 172 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया था।

(ग) सभी कारखानों में कुल मिलाकर ₹55,44,932 करोड़ की निवेशित पूंजी थी।

(घ) कारखानों द्वारा जोड़ा गया कुल शुद्ध मूल्य ₹17,48,325 करोड़ था।

4.31 एएसआई के अंतर्गत यथाशामिल उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

विशेषताएं	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
कारखाने	संख्या	237684	242395	246504	250454	249987
नियत पूंजी	₹लाख	328588927	346606975	364135165	369438562	372635444
उत्पादक पूंजी	₹लाख	393000817	427473434	452465244	480347637	507944093
निवेशित पूंजी	₹लाख	446094480	477726474	497362352	519114310	554493175
कामगार	संख्या	12224422	12798588	13058156	12594563	13609931
कार्मिक	संख्या	15546199	16212214	16568527	16025118	17151172
श्रमिकों को मजदूरी	₹लाख	19280066	21576035	22890520	22261548	26455930

विशेषताएं	इकाई	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
परिलब्धियां	₹लाख	41835716	46207983	49172897	48389031	56082801
कुलनिवेश	₹लाख	660520215	774377980	749755617	719206541	987917996
आउटपुट	₹लाख	807217258	928179908	898330129	880921387	1192715147
अवमूल्यन	₹लाख	23729624	26155291	27309742	28135986	29964685
निवल मूल्य संवर्धन	₹लाख	122967418	127646637	121264771	133578860	174832466
निवल नियत पूंजी निर्माण	₹लाख	7539180	8310576	14361795	3225819	3042540
निवल आय	₹लाख	105078789	107790378	102243476	115747714	157994016
दिया गया किराया	₹लाख	2147363	512545	471423	481328	506211
दिया गया ब्याज	₹लाख	18768379	19343714	18549872	17349819	16332239
लाभ	₹लाख	57624246	55652258	46947269	61405752	95071368

एएसआई वेब-पोर्टल

4.32 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वेब-पोर्टल को औद्योगिक सांख्यिकी विंग, कोलकाता द्वारा एएसआई अनुसूचियों के संग्रह और संकलन के लिए एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया था। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य बिल्ट-इन वेलिडेशन की सुविधा के साथ स्रोत पर ही एएसआई आंकड़े एकत्र करना है जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी। इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सुरक्षित वातावरण में 24X7 उपलब्ध रहेगा ।

जनवरी, 2024 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा व्यापारिक संघें के साथ एएसआई सम्मेलन का आयोजन

इसका उद्देश्य है कि इससे अनुसूचियों को भौतिक रूप से परिवर्तित किए बगैर सुरक्षित वातावरण में एएसआई आंकड़े समय से, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान किए जा सकेंगे। एएसआई वेब-पोर्टल को एएसआई 2012-13 से एएसआई 2018-19 तक फ्रेम अपडेशन, नमूना चयन और एएसआई अनुसूची के ई-संकलन के लिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। एएसआई 2019-20 से, एएसआई वेब-पोर्टल को एनएसएस की ईएसआईजीएमए परियोजना के हिस्से के रूप में विकसित किया गया था और तब से इसका उपयोग किया जा रहा है।

कृषि सांख्यिकी

4.33 एनएसएसओ (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) की कृषि सांख्यिकी स्कंध "फसल सांख्यिकी सुधार योजना (आईसीएस)" को क्रियान्वित करती है तथा राज्य सरकारों को विभिन्न फसलों के क्षेत्र डेटा और उपज दर अनुमानों के संग्रह की उनकी प्रणाली में कमियों की पहचान करने में सहायता करती है। आईसीएस योजना के अंतर्गत राज्य प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए क्षेत्र गणना कार्य की नमूना जांच तथा उपज दर का अनुमान लगाने के लिए प्राथमिक कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोगों का नमूना पर्यवेक्षण किया जाता है, ताकि प्रणाली में कमियों की पहचान की जा सके। आईसीएस योजना की स्थिति रिपोर्ट राज्य सरकारों को प्रस्तुत की जाती है।

4.34 इस योजना के अंतर्गत, एक कृषि वर्ष में 13887 (खरीफ सीजन के लिए 6209 और रबी सीजन के लिए 7678) नमूना गांवों में क्षेत्र गणना से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र कार्य पर नमूना जांच और प्रत्येक कृषि वर्ष में 31324 (केंद्रीय और राज्य नमूना प्रत्येक के लिए 15662) फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण किया जाता है।राज्य सरकारों के राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसए) भी अनुसूची एएस 1-1 में क्षेत्रीय सांख्यिकी पर डेटा को मजबूत करने के लिए राज्य के नमूने के 5349 गांवों के क्षेत्र एकत्रीकरण पर नमूना जांच करते हैं। कटाई के चरण में फसल कटाई प्रयोगों के पर्यवेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग आईसीएस योजना के तहत निर्दिष्ट फसलों की उपज दर के 223 अनुमानों की गणना करने के लिए भी किया जाता है।अग्रिम अनुमान तैयार करने में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, डीईएस द्वारा अन्य स्रोतों के अलावा अनुमानों का भी उपयोग किया जाता है।

4.35 वर्तमान में, एनएसएसओ (एफओडी) ने फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) पर नमूना जांच पर डेटा संग्रह के लिए कागज-आधारित अनुसूची की प्रणाली से ई-शेड्यूल में परिवर्तन किया है (अनुसूची एएस 2.0) शुरुआत में, एनएसएसओ में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एएस 2.0 के लिए एक इन-हाउस डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है, जिसे अप्रैल 2018 से शुरू किया गया था।इसी प्रकार, क्षेत्र गणना कार्य (एएस 1-0) पर नमूना जांच को डिजिटल मोड में लाने के लिए इन-हाउस विशेषज्ञता का उपयोग करके एक एंड्रॉइड आधारित सॉफ्टवेयर 'एग्रीसॉफ्ट' विकसित किया गया है।यह क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सुधार की प्रक्रिया में है और अगले कृषि वर्ष (2024-25) से शुरू होने की उम्मीद है। पीएमएफबीवाई फसल की विफलता के खिलाफ एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करता है जिससे किसानों की आय को स्थिर करने में मदद मिलती है एनएसएसओ (एफओडी) का एएस

ऊपर से नीचेः कृषि वर्ष 2023-24, खरीफ सीजन के दौरान आरओ क डपपा और आओ चेन्नई के विभिन्न स्थानों पर किए जा रहे फसल कटाई प्रयोगों (एएस 20.) का पर्यवेक्षण

मुख्यालय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के प्रमुख कार्यक्रम के तहत सीसीई से संबंधित कार्यप्रणाली और प्रक्रियात्मक मुद्दों पर प्रतिक्रिया और सलाह प्रदान करता है।डीडीजी (एएस) राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह (टीएजी) का सदस्य है, जिसकी अध्यक्षता सीईओ-पीएमएफबीवाई करते हैं।एनएसएसओ का एएस मुख्यालय (एफओडी) महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी) को रिमोट सेंसिंग, मौसम सूचकांक, कृषि-मौसम संबंधी मापदंडों और ग्राउंड ट्रूथिंग की मदद से प्रत्यक्ष उपज अनुमान के लिए एमएनसीएफसी द्वारा संचालित स्मार्ट सैंपलिंग तकनीकों के अपने पायलट और रोल-आउट अध्ययन में विशेषज्ञ सलाह भी प्रदान करता

शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस)

4.36 शहरी फ्रेम सर्वेक्षण (यूएफएस) शहरी क्षेत्र में प्रथम चरण नमूना इकाइयों के चयन के लिए फ्रेम प्रदान करने के लिए शहरों में यूएफएस ब्लॉकों के गठन और अद्यतन के लिए 5 साल के चरण में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के फील्ड ऑपरेशन डिवीजन (एफओडी) द्वारा आयोजित किया जाता है। एनएसएसओ के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों में उपयोग के लिए वर्तमान में चरण 2022-27 (जुलाई 2022-जून 2027) का सर्वेक्षण कार्य एनआरएससी से सॉफ्टवेयर समर्थन का उपयोग करके डिजिटल मोड में चल रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वेबसाइट में अद्यतन करने के लिए यूएफएस फ्रेम के साथ नवीनतम यूएफएस मेटाडेटा डीपीडी द्वारा प्रदान किया गया है।

मूल्य आंकड़ा

कृषि श्रम और ग्रामीण श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई (एएल/आरएल),

4.37 एनएसएसओ कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों (एएल/आरएल) के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन के लिए मासिक ग्रामीण मूल्य आंकड़ा संग्रहीत करता है। लगभग 260 मदों के लिए मूल्य आंकड़ा के साथ-साथ, 12 कृषि प्रमुख तथा 13 गैर-कृषि प्रमुख व्यवसायों की दैनिक मजदूरी दरें भी अनुसूची 3.01 (आर) में एकत्रित की जा रही हैं। महत्वपूर्ण कृषि प्रचालनों की दैनिक मजदूरी दरों के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार पर रिपोर्ट किए जाते है। श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के सीपीआई (एएल/आर एल) सूचकांक आंकड़ों को संकलित करता है और प्रकाशित करता है। जिसे प्रत्येक राज्य तथा अखिल भारत स्तर पर प्रत्येक माह (20 तारीख अथवा अगले महीने के पूर्ववर्ती कार्य दिवस को) जारी किया जाता है। सीपीआई (एएल/आरएल) के लिए वर्तमान आधार वर्ष 1986-87=100 है आरपीसी के लिए आंकड़ा 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 603 गांवों से किया जाता है और श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ को प्रेषित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आधार संशोधन के लिए नई श्रृंखला के तहत 782 ग्रामीण प्रतिदर्शों से भी मूल्य संग्रहण क्षेत्र अधिकारियों द्वारा मासिक आधार पर किया जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी)

4.38 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) परिवारों द्वारा उपभोग के उद्देश्य से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू) का मूल्य संग्रहण मई 2008 से मूल्य सांख्यिकी प्रभाग, (पीएसडी), की ओर से एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा आरम्भ किया गया। सीपीआई (यू) का वर्तमान आधार वर्ष 2012=100 है। मूल्य आंकड़ा संग्रहण प्रतिमाह पूरे देश में 310 कस्बों से 1078 कोटेशन के लिए किया जाता है। सीपीआई (यू) के शहरी मूल्य पोर्टल में मासिक खुदरा मूल्य का संग्रहण/पारेषण एफओडी, एनएसएसओ द्वारा नियमित रूप से किया जा रहा है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण)

4.39 एफओडी, एनएसएसओ को, डाक विभाग (डीओपी) से कार्य हस्तांतरित करने के बाद, सितंबर 2018 से सीपीआई (ग्रामीण) का काम सौंपा गया है।

4.40 सीपीआई (ग्रामीण) का आधार वर्ष सीपीआई (शहरी) के समान है, अर्थात, 2012=100 देश भर के 1181 गांवों में स्थित बाजारों से मूल्य डेटा संग्रह किया जा रहा है। एफओडीके क्षेत्र कार्यालयों द्वारा सीपीआई (आर) के ग्रामीण मूल्य पोर्टल में मासिक खुदरा मूल्यों का संग्रहण/प्रेषण नियमित रूप से किया जा रहा है।

(सीपीआई) आर के लिए मूल्य डेटा संग्रहण का क्षेत्रीय निरीक्षण

बाजार सर्वेक्षण और सीपीआई (यू/आर) का आधार संशोधन

4.41 सीपीआई (यू/आर) के आधार संशोधन के लिए एक पूर्ण बाजार सर्वेक्षण 1 जनवरी 2024 से शुरू हो गया है, जिसमें नए चयनित गाँव और कस्बे शामिल हैं। देश भर में प्रति माह 1399 शहरी और 1465 ग्रामीण कोटेशन के लिए मूल्य डेटा संग्रह किया जाता है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई)

4.42 आर्थिक सलाहकार का कार्यालय मासिक थोक मूल्य सूचकांक डेटा संकलित करने और जारी करने के लिए जिम्मेदार है। संगठित क्षेत्र की 5905 विनिर्माण इकाइयों/कारखानों को कवर करने वाले मासिक आधार पर 6765 कोटेशन के लिए डेटा संग्रह/संचरण गतिविधियों को थोक मूल्य सूचकांक के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) में आर्थिक सलाहकार के कार्यालय की ओर से एफओडी, एनएसएसओ द्वारा सुगम बनाया जा रहा है।

थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष संशोधन

4.43 थोक मूल्य सूचकांक के आधार संशोधन के लिए वर्तमान थोक मूल्य सूचकांक श्रृंखला के अलावा अप्रैल 2017 से प्रति माह 5884 कोटेशन के लिए बैकलॉग मूल्य संग्रह एकत्र किया जा रहा है।

योजना

4.44 एनएसएसओ पर मंत्रालय की योजना स्कीम 'क्षमता विकास' के उपघटकों में से एक नामतः 'एनएसएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' को कार्यान्वित करने का दायित्व है। इस घटक एससीडी के अंतर्गत, एनएसएसओ पाँच पूर्वोत्तर राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और सिक्किम को एनएसएसओ के सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के लिए राज्य प्रतिदर्शों के साथ केन्द्रीय प्रतिदर्शों हेतु अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित क्षेत्र कार्य के बदले में सहायता अनुदान के रूप में निधियाँ जारी की है।

4.45 'एनएसएसओ की आंकड़ा विधायन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत, अवसंरचना तैयार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के अलावा, 10 वीं योजना के दौरान दो योजना केंद्रों नामतः समंक विधायन केंद्र, बंगलौर तथा समंक विधायन केंद्र अहमदाबाद में संस्थापित किए गए। इन दोनों समंक विधायन केंद्रों ने परिणामों को जारी करने और आंकड़ा विधायन की समयबद्धता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

सर्वेक्षण

4.46 सर्वेक्षण जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय की एक अर्धवार्षिक तकनीकी पत्रिका है। यह एनएसएसओ के भाग के रूप में संचालित सर्वेक्षणों पर विशेष रूप से आधारित विभिन्न सामाजिक आर्थिक पक्षों के संबंध में शैक्षिक समुदाय, अन्वेषकों और सरकारी अधिकारियों के बीच अनुसंधान और विश्लेषण को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण मंच रहा है। एनएसएसओ पत्रिका 'सर्वेक्षण' का 114 वां अंक अप्रैल 2023 में प्रकाशित किया गया है। इस पत्रिका में सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न पक्षों से संबंधित शोध पत्र लेख है।

4.47 प्रकाशन के लिए दस्तावेजों को जमा करवाने हेतु संपादकीय सलाहकार बोर्ड (ईएबी) द्वारा दस्तावेजों की समीक्षा की कड़ी प्रक्रिया के पश्चात् ही ई ए बी द्वारा उसे अनुमोदन दिया जाता है। मंत्रालय की वेबसाइट पर 'सर्वेक्षण' के विभिन्न अंक उपलब्ध करवाए गए हैं।

राष्ट्रीय सेमीनार

4.48 एससीडी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) दौरों के दौरान संग्रहित आंकड़ों पर आधारित सर्वेक्षण रिपोर्टों को जारी किये जाने के बाद नियमित अंतरालों पर सेमीनार आयोजित करता है, जहां विभिन्न क्षेत्रों से विशेषज्ञ/लेखक जैसे अकादमी अन्वेषक/केन्द्रीय और राज्य सरकार के अधिकारी और अन्य संस्थान/विश्वविद्यालय को अनुसंधान लेख प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। संपूर्ण देश की विख्यात संस्थाओं/विश्वविद्यालों में वर्ष 2022-23 तक सतरह (17) सेमीनार आयोजित किए जा चुके हैं। 17वां राष्ट्रीय सेमीनार जिसमें एनएसएस के 76 वें दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2018) और 77वां दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2019) के दौरान प्राप्त हुए एनएसएस सर्वेक्षण के परिणामों को शामिल किया गया है, 1 एवम् 2 सितंबर, 2022 के दौरान कोच्चि विज्ञान और प्रद्यौगिकी विश्व-विद्यालय (सीयूएसएटी), कोचिन में आयोजित किया गया था।

कुसाट, कोची में आयोजित 17 वें राष्ट्रीय सेमिनार की कुछ झांकियाँ

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग/नई पहलें

4.49 एनएसएस के 77वें दौर से सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण का डिजीटाइजेशन दिनांक 01 जनवरी, 2019 से आरंभ किया गया। क्षेत्र में आंकड़ें टेबलेट का उपयोग करते हुए आई सक्षम प्लेटफार्म पर कैप्चर किये जा रहें हैं। इन-बिल्ट नियंत्रणों के माध्यम से फील्ड डाटा की गुणवत्ता में सुधार करते हुए यह डाटा संचरण में लगने वाले समय को भी कम करता है।

4.50 वर्तमान में चल रहे यूएफएस चरणों (2022-2027) का क्षेत्रीय कार्य नेशनल राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा तैयार मोबाइल/वेब एप्लीकेशनों के माध्यम से डिजिटल मोड में किया जा रहा है। ब्लॉक/वार्ड/अन्वेषक इकाईयां/कस्बों की सीमाएं क्वांटम भौगोलिक सूचना प्रणाली सॉफ्टवेयर (क्यूजीआईएस) का प्रयोग करते हुए 'भुवन' पोर्टल से प्राप्त सेटेलाइट चित्रण पर खींची जायेगी। संरचनाओं के विभिन्न गुणों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कैप्चर किया जाता है और सेटेलाइट चित्रण पर लगाया जाता है। डिजिटल मोड में यूएफएसमैप को सेव करने पर जोर देता है और साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए सेम्पलिंग फ्रेम के रूप में इसका प्रयोग करने के लिए भुवन पोर्टल की संबंधित विशेषताओं पर विचार करता है। एनएसएसओ (एफओडी) ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के तहत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं, ताकि भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अत्याधुनिक जियो आईसीटी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके डिजिटल मोड में यूएफएस की सुविधा प्रदान की जा सके।

4.51 फसल कटाई प्रयोगों पर नमूना जांच पर डेटा के प्रसारण के लिए एफओडी ने कागज आधारित अनुसूची की प्रणाली से ई-शेड्यूल में बदलाव किया है (अनुसूची एएस 2.0) एएस 2.0 के लिए एनएसएसओ में उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता के साथ एक इन-हाउस डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर विकसित किया गया था और 2018-19 के दौरान सभी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों/राज्य सरकारों को उपलब्ध कराया गया था।

सर्वेक्षण उपकरणों का डिजिटलीकरण और राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षणों में समय अंतराल में कमी:

4.52 प्रणालीगत सुधार और आंकड़ों के समय पर प्रकाशन के संबंध में, बेहतर डेटा कैप्चरिंग और प्रसंस्करण के लिए आधुनिक आईटी उपकरण अपनाए जा रहे है। इसके एक भाग के रूप में, सभी चल रहे एनएसएस सर्वेक्षण अब सीएपीआई (कम्प्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू) में आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें डेटा कैप्चरिंग के विभिन्न चरणों में डेटा सत्यापन के लिए इन-बिल्ट कंप्यूटर स्क्रूटनी पॉइंट्स (सीएसपी) लोड किए गए हैं, जो एक क्लाउड आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एक साथ डेटा प्रोसेसिंग सुनिश्चित करता है। यह सर्वेक्षण परिणाम प्रकाशित करने में शामिल समय चक्र के साथ-साथ तेजी से सत्यापन और बेहतर डेटा गुणवत्ता को सक्षम बनाता है। इस तकनीकी सुधार के कारण पीएलएफएस के त्रैमासिक बुलेटिन (क्यूबी) के रिलीज होने में लगने वाला समय, क्षेत्रीय कार्य पूरा होने के बाद लगने वाले नौ महीने से घटकर दो महीने रह गया। सर्वेक्षण अवधि के अंत से पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के जारी होने में लगने वाले समय अंतराल को भी पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के जारी होने के 8 महीने से घटाकर लगभग 3 महीने कर दिया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालयों में अवसंरचना का उन्नयन/संवर्धन

4.53 क्षेत्र संकार्य प्रभाग के फील्ड कार्यालयों में बुनियादी सुविधाओं का नियमित रूप से विकास और सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। इस संबंध में, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरानः

(i) एनएसएसओ (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) छात्रावास, गुवाहाटी की मरम्मत और उन्नयन कार्य शुरू हुआ।
(ii) क्षेत्रीय कार्यालय बेंगलुरु के कार्यालय भवन का नवीनीकरण किया गया है।
(iii) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कार्यालय भवन का नवीनीकरण शुरू हुआ।
(iv) क्षेत्रीय कार्यालय शिवपुरी के कार्यालय भवन का नवीनीकरण किया गया है।
(v) क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के कार्यालय भवन का नवीनीकरण शुरू हुआ।
(vi) सभी आवश्यक फिटिंग के साथ शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के शौचालय का निर्माण, नववदज, अहमदाबाद में एनएसएसओ भवन के अंदर और बाहर शौचालय का नवीनीकरण और पेंटिंग का काम पूरा हो गया है।
(vi) पूर्वी क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का नवीनीकरण/उन्नयन पूरा हो गया है।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान निम्नलिखित कार्य किए गए हैं:

(I) क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी में एनएसओ (क्षेत्र संकार्य प्रभाग) छात्रावास की मरम्मत और उन्नयन कार्य पूरा हो गया है।
(ii) क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के कार्यालय भवन का नवीनीकरण पूरा हो गया है।
(iii) क्षेत्रीय कार्यालय, फरीदाबाद के कार्यालय भवन का नवीनीकरण पूरा हो गया है।
(iv) एसआरओ राजकोट के लिए खरीदे गए भूखंड के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(v) आरओ हुबली में लिफ्ट की स्थापना पूरी हो गई है।
(vi) एसआरओ उधमपुर के भूखंड के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(vii) एसआरओ काकीनाडा के भूखंड के चारों ओर चारदीवारी का निर्माण पूरा हो गया है।
(viii) जोनल/क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी के लिए अतिरिक्त स्थान खरीदने के लिए तीसरी किस्त का भुगतान किया गया है।

4.54 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, उपर्युक्त कार्य सहित भवन एवं संरचना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के लिए सीपीडब्ल्यूडी को 7-54 करोड़ रुपये की राशि के एलओएएस जारी किए गए।

प्रशिक्षण सुविधा को सुदृढ़ करना

दिनांक 29 अगस्त 2023 को महानिदेशक एनएसएस द्वारा आंचलिक कार्यालय (ईजेड) कोलकाता में प्रशिक्षण हॉल का उद्घाटन

4.55 प्रशिक्षण सुविधाओं को सुदृढ़ करना क्षेत्र संकार्य प्रभाग की तकनीकी जनशक्ति का क्षमता विकास और सूचना अद्यतन एक सतत प्रक्रिया है। क्षेत्र संकार्य प्रभाग सभी छह आंचलिक कार्यालयों और कृषि सांख्यिकी विंग, फरीदाबाद में अपने आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए नियमित इन-सर्विस प्रशिक्षण मॉड्यूल आयोजित करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, अधिकारियों/कर्मचारियों को विभिन्न तकनीकी योजनाओं जैसे सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई/एएसआई वेब पोर्टल, कृषि सांख्यिकी, यूएफएस, पीएलएफएस, आदि और सामान्य प्रशासनिक मामलों और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 पर प्रशिक्षित किया गयाथा। इसके अलावा, क्षेत्र संकार्य प्रभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किसी भी सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय कार्य शुरू करने से पहले क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए सर्वेक्षण-विशिष्ट प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं।

4.56 वर्ष 2023-24 के दौरान, एफओडी ने अक्टूबर 2023 में एएसयूएसई 2023-24 के प्रारंभ/लॉन्च के लिए एसडीआरडी और डीपीडी के प्रशिक्षकों द्वारा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण का आयोजन किया, जिसके बाद आरओ स्तर पर सभी क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

अध्याय - 5

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

5.1 एमपीलैडस योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की घोषणा 23 दिसंबर 1993 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा संसद में की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सांसद को लोगों की स्थानीय रूप से महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के निर्माण पर जोर देने के साथ विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाना है। प्रारंभ में एमपीलैड्स का प्रशासन ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास था। हालांकि, अक्टूबर 1994 से, योजना का प्रशासन सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पास निहित है। यह योजना दिशानिर्देशों के एक समूह द्वारा शासित होती है, जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है। वर्तमान दिशा-निर्देश 22 फरवरी 2023 को जारी किए गए थे, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू हुए।

5.2 एमपीलैडस योजना की मुख्य विशेषताएः-

(क) एमपीलैड्स भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है जिसके अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में कुछ शर्तों के अधीन वार्षिक प्राधिकरण सीमा आवंटित की जाती है।

(ख) स्कीम के अंतर्गत कार्यों की सिफारिश और स्वीकृति करते समय संसद सदस्य, नोडल जिला प्राधिकारियों, कार्यान्वयन जिला प्राधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मूल सिद्धांत यह है कि इससे व्यापक स्तर पर समाज के जनहित के लिए टिकाऊ सार्वजनिक परिसंपत्तियों का सृजन होता है और समाज के किसी वर्ग तक इसकी पहुंच और उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) एमपीलैड्स निधियों का उपयोग सरकारी स्वामित्व वाली भूमि पर अचल सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन और चल सार्वजनिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए केवल सरकारी स्वामित्व वाली और सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थानों अर्थात् केन्द्र, राज्य/संघ शासित प्रदेश और सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों सहित स्थानीय सरकारों के लिए किया जा सकता है।

(घ) एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 में उन कार्यों की सांकेतिक सूची प्रदान की गई है जिन्हें योजना के तहत लिया जा सकता है। तथापि, यह सूची विस्तृत नहीं है और संसद सदस्य की सिफारिशों पर सूची में नए कार्य जोड़े जा सकते हैं, यदि वे स्कीम के समग्र सिद्धांतों और उद्देश्यों के अनुरूप हों।

(ङ) संसद के किसी विशेष सदस्य के वार्षिक आबंटन में से खर्च न की गई शेष राशि को आगे बढ़ाया जाएगा और बाद के वित्तीय वर्ष के लिए संसद सदस्य के लिए वार्षिक आबंटन में जोड़ा जाएगा और नोडल जिला प्राधिकरण के साथ उसके खाते की आहरण सीमा तदनुसार निर्धारित की जाएगी।

(च) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्यों की भूमिका कार्यों की सिफारिश करने तक सीमित है। तत्पश्चात, यह जिला प्राधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृति, निष्पादित और पूरा करे।

(छ) निर्वाचित लोक सभा सदस्य अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उस राज्य में कहीं भी काम की सिफारिश कर सकते हैं जहां से वे चुने गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी काम की सिफारिश कर सकते हैं।

(ज) एक संसद सदस्य सभी सोसाइटियों/न्यासों को कुल मिलाकर प्रति वर्ष केवल 50 लाख रुपये तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा संसद सदस्य अपनी संपूर्ण अवधि के दौरान किसी विशेष सोसायटी/न्यास के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य की सिफारिश न कर सके। 1 करोड़ रुपये की सीमा उनके पुनः चुनाव/नामांकन के बाद संसद सदस्य के रूप में संबंधित व्यक्ति का नया कार्यकाल शुरू होने पर पुनः लागू होगी।

(झ) देश में कहीं से भी कोई भी संसद सदस्य एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन देश के किसी भी भाग में भारत सरकार द्वारा घोषित प्राकृतिक प्रकृति की आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये तक की अपनी एमपीलैड्स निधियों की सहमति दे सकता है।

(ञ) जब किसी राज्य सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से गंभीर प्रकृति की आपदा घोषित की जाती है न कि भारत सरकार द्वारा, तो उस राज्य के किसी निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा संसद सदस्य और उस राज्य का कोई भी राज्य सभा संसद सदस्य राज्य के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक सहमति दे सकता है।

(ट) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा बसे क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर उचित ध्यान देने के लिए, संसद सदस्यों को अनुसूचित जाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए कुल एमपीलैडस पात्रता का कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले क्षेत्रों के लिए वर्ष के लिए कुल एमपीलैडस पात्रता का कम से कम 7-5 प्रतिशत लागत वाले कार्यों की सिफारिश करनी है।

(ठ) एक निर्वाचित संसद सदस्य भी सामान्य क्षेत्र से बाहर देश में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकता है जिसमें वह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 311 में उल्लिखित कार्य की सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि आपदा के मामले को छोड़कर, ऐसी सभी सिफारिशों के लिए प्रति संसद सदस्य एक वित्तीय वर्ष में 25 लाख रुपये की सीमा हो।

(ड) दिशा-निर्देशों में अलग-अलग विकलांग व्यक्तियों को प्रोस्थेटिक्स, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल (मैनुअल या मोटरीज्ड), इलेक्ट्रिक स्कूटी, श्रवण यंत्र और ऐसे अन्य उपकरण प्रदान करके सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

(ढ) न्यास, समितियों और सहकारी समितियों के लिए निष्पादित किए जाने वाले कार्यों सहित एमपीलैड्स निधियों को अन्य केन्द्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ-साथ स्थानीय निकायों की व्यक्तिगत/एकल परियोजनाओं के साथ पूल किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसे कार्य एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हों।

(ण) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एमपीलैड्स प्रभाग (पीएमयू-एमपीलैड्स) के अंतर्गत परियोजना प्रबंधन इकाई को योजना के कार्यान्वयन के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वास्तविक निधि केवल केन्द्रीय नोडल खाते में होगी और जब कभी इलैक्ट्रानिक रूप से मांगें उठाई जाएंगी तो निधि सीधे विक्रेता के खाते में जमा की जाएगी।

(त) एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन के लिए एमपीलैड्स दिशानिर्देश, 2023 में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और कार्यान्वयन एजेंसियों की भूमिका स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। एमपीलैड्स दिशानिर्देश मंत्रालय की बेवसाइट mplads-gov- पद पर उपलब्ध हैं ।

योजना निष्पादन

वास्तविक निष्पादन

5.3 प्रारंभ से ही इस स्कीम ने पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर-पारंपरिक ऊर्जा, सामुदायिक केन्द्रों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, बस स्टैंडों/स्टॉपों, सड़कों, रास्तों एवं पुलों, खेलकूद आदि जैसी विभिन्न विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करके स्थानीय समुदाय को लाभान्वित किया है। इन कार्यों को एमपीलैड्स दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, निष्पादित और मॉनीटर किया जाता है।

योजना की शुरुआत से लेकर 31 मार्च 2024 तक

- सांसदों द्वारा 25,97,604 कार्यों की सिफारिश की गई है।
- इनमें से 22,93,251 कार्यों को मंजूरी दे दी गई है और कार्यान्वयन के लिए शुरू कर दिया गया है।
- 20,81,325 कार्य पूरे किए जा चुके हैं और स्थानीय समुदायों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए परिसंपत्तियां उपलब्ध करा दी गई हैं।

1 अप्रैल 2023 से ई-साक्षी पोर्टल के कार्यान्वयन के बाद, 2023-24 के दौरान,

- सांसदों द्वारा 1,15,530 कार्यों की सिफारिश की गई है
- 72,054 कार्य स्वीकृत किए गए हैं तथा
- 3,256 कार्य पूरे किए जा चुके हैं।

5.4 योजना की शुरुआत के बाद से, संसद सदस्यों को 5950573 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है (निधियों की वर्ष-वार रिलीज के लिए ग्राफ देखें)।

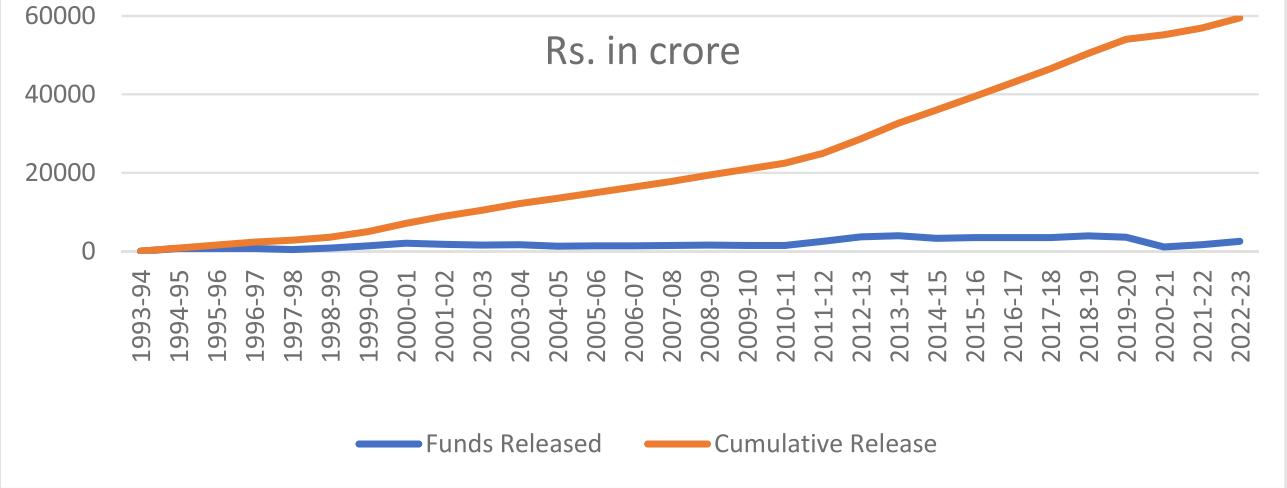

5.5 योजना की शुरुआत के बाद से, मंत्रालय द्वारा 31 मार्च 2023 तक 59,505-74 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है और 59,250-75 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है। जारी की गई राशि का 99.57 प्रतिशत इस योजना के तहत खर्च किया जा चुका है।

संशोधित एमपीलैड्स दिशानिर्देश और नई निधि प्रवाह प्रक्रिया

5.6 योजना को अधिक लचीला, कुशल और प्रभावी बनाने और इसे समुदाय की बदलती विकास आवश्यकताओं के अनुरूप लाने के उद्देश्य से, दिशानिर्देशों का एक संशोधित सेट 22 फरवरी 2023 को जारी किया गया है, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हुआ है। वित्त मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप 1 अप्रैल, 2023 से एमपीलैड्स के तहत संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया को लागू करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से मंत्रालय द्वारा ई-साक्षी पोर्टल विकसित किया गया है।

5.7 संशोधित निधि प्रवाह प्रक्रिया के अंतर्गत, संसद सदस्यों को नई परियोजनाओं की सिफारिश करने से पहले मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली वास्तविक निधि की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उन्हें कतिपय शर्तों के अध्यधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में वार्षिक आहरण सीमाएं आबंटित की जाएंगी। निधि प्रवाह की पूरी प्रक्रिया एक आईटी प्लेटफॉर्म अर्थात ई-साक्षी पर संचालित होगी, जो संसद सदस्यों, केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों, जिला प्राधिकरणों आदि सहित सभी हितधारकों को धन की स्थिति की निगरानी करने और वास्तविक समय के आधार पर कार्यों की निगरानी करने की अनुमति देता है, जो एमपीलैड्स के तहत परियोजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान करेगा और प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी लाएगा।

5.8 1 अप्रैल 2023 से नई निधि प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत ई-साक्षी पोर्टल के कार्यान्वयन के पश्चात, 2023-24 के दौरान,

- ₹ 6817-47 करोड़ की प्राधिकरण राशि जारी की गई है।
- ₹ 1089-94 करोड़ का व्यय हुआ है।
- ₹ अधिकृत राशि का 15.98 प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

5.9 जिलों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक योजना के अंतर्गत ₹60,610,69 करोड़ रू. का व्यय किया गया है, जिसमें से 2023-24 के दौरान ई-साक्षी पोर्टल के माध्यम से ₹1089,94 करोड़ रू. खर्च किए गए हैं।

ई-साक्षी मोबाइल ऐप का शुभारंभ

5.10 मंत्रालय ने 16 जनवरी 2024 को ई-साक्षी मोबाइल एप्लिकेशन लॉन्च किया, जो माननीय सांसदों को वास्तविक समय में परियोजनाओं को प्रस्तावित करने, ट्रैक करने और उनकी देखरेख करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने, उभरती जरूरतों या मुद्दों पर तेजी से प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए पहुंच और सुविधा प्रदान करता है। मोबाइल ऐप माननीय सांसदों को उनकी प्रस्तावित परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति पर तत्काल अपडेट प्रदान करेगा और सांसदों और संबंधित अधिकारियों के बीच संचार को भी सुव्यवस्थित करेगा, जिससे सूचना के अधिक कुशल आदान-प्रदान की सुविधा होगी।

5.11 यह पारदर्शिता न केवल जवाबदेही को बढ़ावा देती है बल्कि एमपीलैड्स निधियों के आवंटन और उपयोग में जनता का विश्वास भी जगाती है। मोबाइल एप्लिकेशन में बजट प्रबंधन की सुविधाएँ भी हैं जो सांसदों द्वारा व्यय की निगरानी की सुविधा प्रदान करती हैं। एमपीलैड योजना के कार्यान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय विभिन्न हितधारकों के सहयोग और वर्षों से प्राप्त परिचालन अनुभव, सक्रिय भागीदारी और निगरानी द्वारा प्राप्त तालमेल को दिया जाता है। संशोधित दिशा-निर्देशों के तहत सिफारिश की पूरी प्रक्रिया वेब पोर्टल के साथ-साथ मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से संचालित होगी। इस अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान का उद्देश्य एमपीलैड योजना के निष्पादन में पारदर्शिता, सुलभता और दक्षता को बढ़ाना है।

निगरानी और प्रशिक्षण

5.12 2023-24 के दौरान, विभिन्न हितधारकों अर्थात राज्य और जिला प्राधिकरणों तक नई प्रणाली और संबंधित दिशा-निर्देशों का प्रसार करने और उन्हें ई-साक्षी पोर्टल में प्रदान की गई कार्यक्षमता को समझाने के लिए, एमपीलैड्स प्रभाग ने पूरे वर्ष कार्यशालाओं और संगोष्ठियों की एक श्रृंखला आयोजित की। राज्य और जिला प्राधिकरणों के अधिकारियों का मार्गदर्शन करने और ई-साक्षी पोर्टल के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए वर्ष के दौरान सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में बारह वेबिनार और 38 कार्यशालाएँ आयोजित की गईं।

5.13 इसके अतिरिक्त, ई-साक्षी पोर्टल से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक समर्पित 24x7 हेल्पडेस्क (1800113702) स्थापित किया गया है। 2023 के मानसून सत्र के बाद से सभी संसद सत्रों के दौरान कियोस्क/बूथ स्थापित किए गए और माननीय सांसदों/उनके प्रतिनिधियों द्वारा पोर्टल अवलोकन, फंड रिलीज, लॉगिन मुद्दों और आईडीए से संबंधित मुद्दों आदि से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया गया।

अध्याय - 6

अवसंरचना तथा परियोजना निगरानी

6.1 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का अवसंरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) 150 करोड़ रुपये या इससे अधिक की परियोजनाओं की निगरानी करता है। भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन (पीआई) स्कंध के इस प्रभाग को निम्नलिखित को पूरा करने का अधिदेश प्राप्त है:

- परियोजना निगरानी - 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक की परियोजनाओं की निगरानी
- प्रदर्शन की निगरानी - बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी

परियोजना निगरानी

6.2 आईपीएमडी सां.कार्य.कार्या.मंत्रा. की ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस) के माध्यम से प्राप्त मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के परियोजना संबंधी आंकड़ों के माध्यम से 150 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति का निष्पादन करता है। परियोजनाओं की प्रगति, वित्तीय पैरामीटर (लागत और व्यय से संबंधित), नियोजित अनुसूची और मूल लागत के संबंध में परियोजनाओं में चूक के कारणों/मुद्दों के संबंध में ओसीएमएस के माध्यम से कई पैरामीटर प्राप्त किए जाते हैं। उपर्युक्त परियोजना आंकड़ों के आधार पर, सां.कार्य.कार्या.मंत्रा. परियोजनाओं के समय और लागत वृद्धि का विश्लेषण करता है और एक मासिक फ्लैश रिपोर्ट (एफआर) और एक तिमाही परियोजना कार्यान्वयन स्थिति रिपोर्ट (क्यूपीआईएसआर) जारी करता है।

6.3 ओसीएमएस पोर्टल पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजनाओं की परियोजना रिपोर्टिंग के मामले में संबंधित मंत्रालयों के साथ निरंतर अनुनय के माध्यम से, पोर्टल पर केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की रिपोर्टिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की गई है। वर्तमान में, रिपोर्ट प्रतिशत 90 प्रतिशत से अधिक है।

6.4 आईपीएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान परियोजना कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए समय-समय पर प्रणालीगत सुधारों को लागू करना रहा है। आईपीएमडी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ नियमित परियोजना समीक्षा बैठकों के दौरान निर्धारित समय से पीछे चलने वाली अथवा लागत वृद्धि का सामना कर रही परियोजनाओं की पहचान करने में एक महत्वपूर्ण सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह प्रक्रिया परियोजना बाधाओं को इंगित करने और बाधाओं को प्रभावी ढंग से दूर करने के लिए सुधारात्मक उपायों को लागू करने में प्रशासनिक मंत्रालयों की सहायता करती है।

6.5 1 अप्रैल 2024 तक, लगभग 26.88 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली 1873 परियोजनाएँ MoSPI की निगरानी में हैं। जबकि 779 परियोजनाएँ देरी का सामना कर रही हैं, परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों ने 449 परियोजनाओं में कुल 5.01 लाख करोड़ रुपये की लागत में वृद्धि की सूचना दी है। मार्च 2024 तक 1873 चालू परियोजनाओं के लिए संचयी व्यय 17-12 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से 4.22 लाख करोड़ रुपये चालू वर्ष 2023-24 के दौरान खर्च किए गए। दिसंबर 2022-मार्च 2024 की अवधि के दौरान, 3.74 लाख करोड़ रुपये की लागत से कुल 439 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई है।

6.6 इसके अतिरिक्त, ओसीएमएस पोर्टल के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग कई उच्च-स्तरीय बैठकों के लिए इनपुट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जिसमें (PRAGATI) प्रगति मासिक समीक्षा, सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत संसदीय प्रश्नों और अनुरोधों को संबोधित करने के लिए प्रधानमंत्री की राज्य यात्राएं शामिल हैं।

परियोजनाओं में समय की अधिकता

6.7 ग्राफ 2014 से 2024 तक समय की अधिकता का अनुभव करने वाली परियोजनाओं के प्रतिशत में प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह मार्च 2014 में 29.44% से बढ़कर मार्च 2024 में 41.59% हो गया। ओसीएमएस में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बताए गए समय से अधिक समय लगने के कुछ कारणों में भूमि अधिग्रहण में देरी, वन/पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने में देरी, बुनियादी ढांचे के समर्थन और संपर्कों की कमी, परियोजना के वित्तपोषण में देरी, विस्तृत इंजीनियरिंग को अंतिम रूप देने में देरी, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन, निविदा प्रक्रिया में देरी, संविदा संबंधी मुद्दे, मानव शक्ति सहित अपर्याप्त संसाधन आदि शामिल हैं।

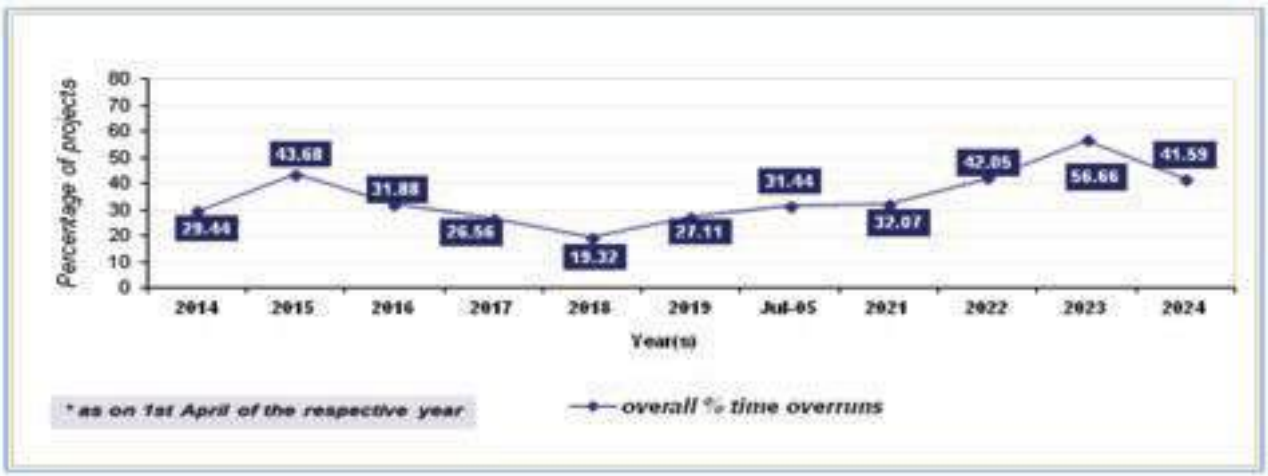

परियोजनाओं में लागत वृद्धि

6.8 नीचे दिया गया ग्राफ 2014 से 2024 तक सभी अपूर्ण कार्यान्वयन परियोजनाओं के लिए लागत वृद्धि के प्रतिशत की प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह मार्च 2014 में 19.4% से मार्च 2024 में 18.65% तक की गिरावट दर्शाता है। ओसीएमएस पर कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा बताए गए लागत वृद्धि के कुछ कारणों में परियोजनाओं के दायरे में परिवर्तन, मूल लागत का कम अनुमान, विदेशी मुद्रा और वैधानिक शुल्कों की दरों में परिवर्तन, पर्यावरण सुरक्षा और पुनर्वास उपायों की उच्च लागत, भूमि अधिग्रहण लागत में वृद्धि, उपकरण सेवाओं के विक्रेताओं द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण, सामान्य मूल्य वृद्धि / मुद्रास्फीति और समय की अधिकता शामिल हैं।

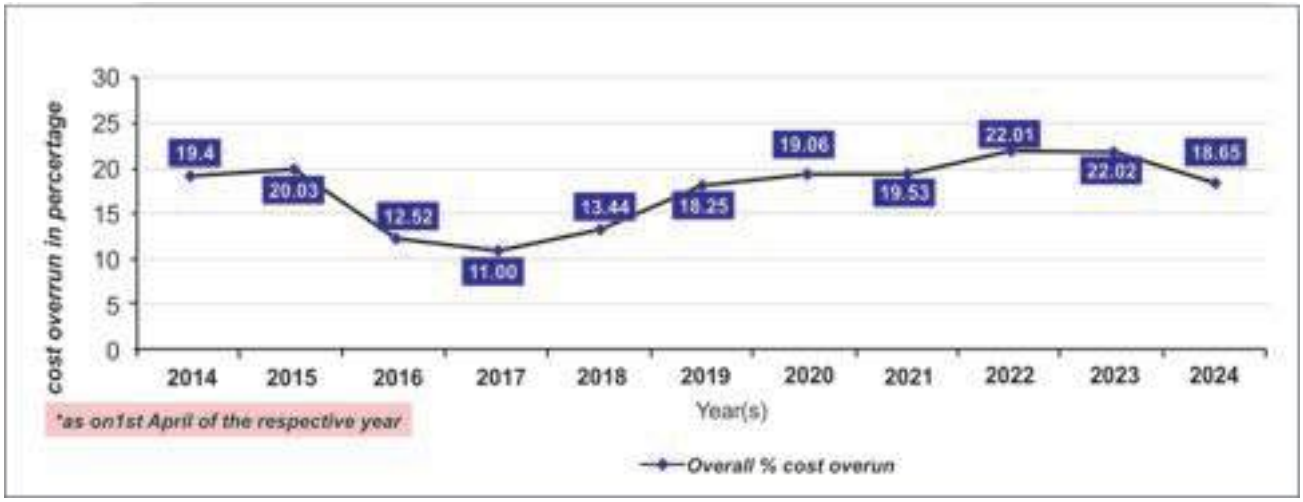

6.9 मार्च 2014 से मार्च 2024 तक निर्धारित समय पर, विलंबित, कमीशन की तिथि के बिना, और निर्धारित समय से पहले वर्गीकृत परियोजनाओं की संख्या का वितरण नीचे दिए गए ग्राफ से देखा जा सकता है:

6.10 मासिक फ्लैश रिपोर्ट और तिमाही समीक्षा रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें मॉनीटर की गई परियोजनाओं के संबंध में समय और लागत वृद्धि का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। ये रिपोर्टें सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।

6.11 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के OCM पोर्टल को नया रूप दिया जा रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक सामान्य अपलोड फॉर्म को आईआईजी और पीएमजी के पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा रहा है, जिससे विभिन्न संबंधित मंत्रालयों/विभागों को अपनी परियोजनाओं के संबंध में डेटा को एक ही एकीकृत पोर्टल पर अपडेट करना होगा और इससे परियोजना निगरानी प्रक्रिया सरल हो जाएगी।

प्रदर्शन निगरानी - बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन की निगरानी

6.12 आईपीएमडी बिजली, सीमेंट, कोयला, इस्पात, रेलवे, शिपिंग और बंदरगाह, उर्वरक, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, सड़क और दूरसंचार सहित 11 प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों के प्रदर्शन की समीक्षा करता है, जो अवधि के लिए उनके पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों और उनके सापेक्ष उपलब्धियों के संदर्भ में है। इन मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण मासिक बुनियादी ढांचा प्रदर्शन समीक्षा रिपोर्ट तैयार करने के लिए इंट्रानेट-आधारित एप्लिकेशन में डाला जाता है। तैयार की गई रिपोर्टें सां.कार्य.कार्या.मंत्रा वेबसाइट पर प्रकाशित की जाती हैं।

6.13 वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों में लक्ष्य मूल्यों के सापेक्ष उपलब्धि का प्रतिशत नीचे दर्शाया गया है।

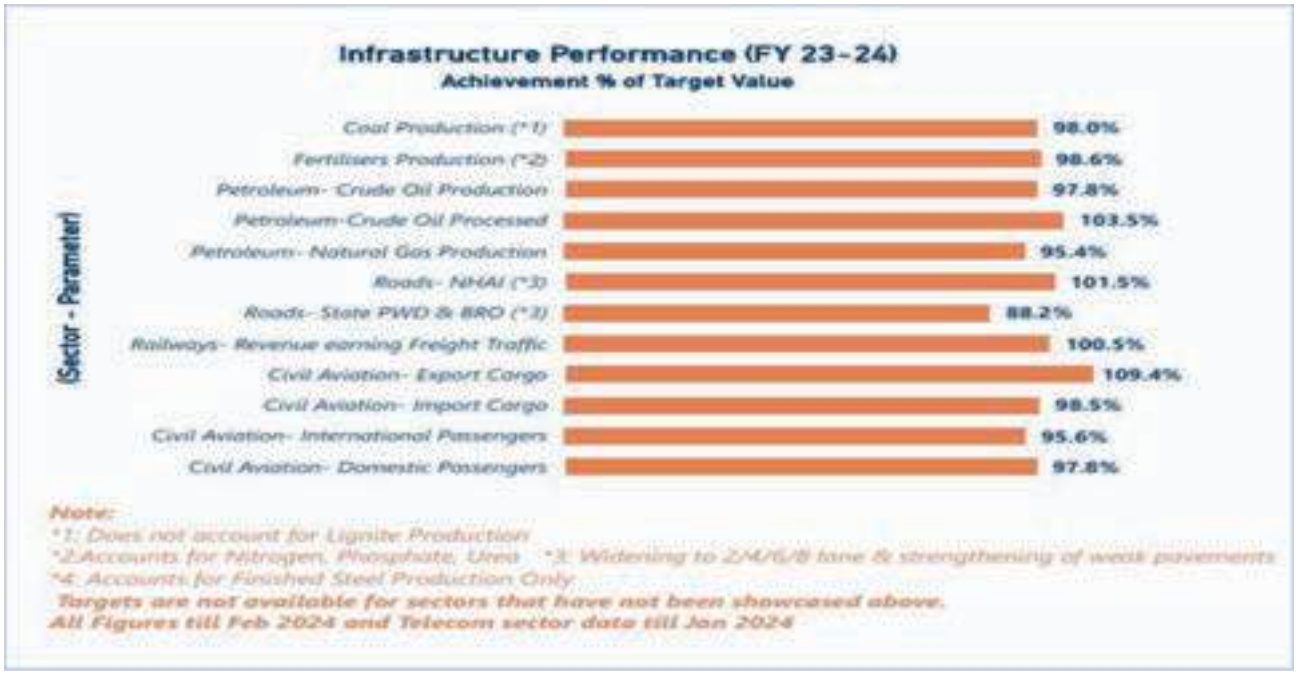

परियोजनाओं का मूल्यांकन एवं अनुमोदन (ए एंड ए)

6.14 आईपीएमडी सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी), प्रत्यायोजित निवेश बोर्ड (डीआईबी), मूल्यांकन और अनुमोदन (ए एंड ए), रेलवे के लिए विस्तारित बोर्ड (ईबीआर), और ईएफसी और एसएफसी मूल्यांकन के लिए बुनियादी ढांचे पर कैबिनेट समिति द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए इनपुट भी प्रदान करता है।

परियोजना निगरानी में प्रशिक्षण

6.15 आईपीएमडी प्रतिष्ठित संस्थानों के सहयोग से विभिन्न हितधारकों (लाइन मंत्रालयों/परियोजनाओं की कार्यान्वयन एजेंसियों) के लिए 'परियोजना नियोजन और प्रबंधन' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है। प्रबंधन विकास संस्थान (एमडीआई), गुड़गांव के सहयोग से 26 फरवरी 2024 से 1 मार्च 2024 तक एक मध्य-स्तरीय पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में व्यवहार में परियोजना प्रबंधन, नियोजन, समय-निर्धारण, संसाधन आवंटन और लागत निर्धारण, निगरानी और नियंत्रण, जोखिम प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन सिमुलेशन, परियोजना लेखा परीक्षा, परियोजना संचार, रिपोर्टिंग आदि से संबंधित विषयों को शामिल किया गया और विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के 30 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

अध्याय - 7

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

7.1 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) की औपचारिक स्थापना दिनांक 17 दिसंबर, 1931 को संस्थान के प्रथम अध्यक्ष सर आर.एन. मुखर्जी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में की गई एवं प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस को मानद सचिव नियुक्त किया गया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का रजिस्ट्रीकरण पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन एक अलाभकारी विद्या प्रसारक सोसाइटी के रूप में दिनांक 28 अप्रैल 1932 को किया गया। संस्थान वर्तमान में पश्चिम बंगाल सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXVI, 1961 के तहत पंजीकृत है, जिसे 1964 में संशोधित किया गया। संस्थान को भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 के माध्यम से "राष्ट्रीय महत्व" का दर्जा प्रदान किया गया।

7.2 जब संस्थान ने अपने अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यकलापों का विस्तार किया तो इसे राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिलने लगी। सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्य में संस्थान के उत्कृष्ट योगदान के कारण उसे संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (1959 का 57) द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई जिससे संस्थान को सांख्यिकी की परीक्षा आयोजित करने और डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार मिला और एसक्यूसी एवं ओआर तथा कम्प्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जून 1960 से आरंभ किए गए। संस्थान को इसी वर्ष से पीएचडी/डीएससी प्रदान करने का अधिकार भी मिला। इसके परिणामस्वरूप कंप्यूटर विज्ञान तथा गुणवत्ता विश्वसनीयता तथा मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (एम. टैक) पाठ्यक्रम शुरू किए गए ।

7.3 1995 में, आईएसआई संशोधन अधिनियम द्वारा संस्थान को आगे और गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर साइस तथा सांख्यिकी से संबंधित ऐसे अन्य विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने की शक्ति प्राप्त हुई। इससे न केवल सांख्किकी/गणित में अनुसंधान कार्यकलापों बल्कि कम्युटर तथा कम्युनिकेशन, नेचुरल एवं सोशल साइंस, भौतिकी तथा अर्थ विज्ञान, जैविक साइंस, सांख्यिकी गुणवत्ता तथा नियंत्रण एवं अनुसंधान प्रचालन, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में वृहत रूप से विभिन्न विधाओं में बढ़ावा मिला। वर्षों से, संस्थान, नेचुरल तथा सोशल साईट विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान तथा प्रायोगिक अनुप्रयोग का उन्नयन करके सांख्यिकी सिद्धांत तथा पद्धति के विकास में प्रमुख भुमिका निभा रहा है ।

संस्थान का समृद्धशाली इतिहास

7.4 संस्थान द्वारा वर्ष 1933 से प्रकाशित की जानेवाली "सांख्यिकी की भारतीय पत्रिका-सांख्य" की गणना अभी भी संसार की एक अग्रणी सांख्यिकीय पत्रिका के रूप में की जाती है। सांख्यिकीय सिद्धान्त के कई क्षेत्रों, विशेषकर बहुविध विश्लेषण, नमूना सर्वेक्षण एवं प्रयोग के डिजाइन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुरोगामी अनुसंधान कार्य किए गए। उन्नीस सौ चालीस के दशक में संस्थान में कार्यग्रहण करनेवाले प्रोफेसर सी आर राव एवं अन्य द्वारा ऐसे कार्यकलापों को और मजबूती प्रदान की गई तथा नई दिशाओं की खोज की गई और वह परंपरा अभी भी जारी है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान को उस समय काफी बढ़ावा मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में प्रोफेसर महालनवीस और संस्थान को देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा। प्रोफेसर महालनवीस के नेतृत्व में संस्थान द्वारा सौंपे गए योजना मॉडल सहित "प्रारूप" को अभी भी भारत की आर्थिक आयोजना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

7.5 भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) आंदोलन का आरंभ करने में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने नवंबर 1947 में एसक्यूसी के जनक प्रोफेसर डब्ल्यू.ए. श्योहार्ट और बाद में डब्ल्यू.ई. डेमिंग, डॉ. एलिस आर. ओट, डॉ. एच.सी. टिप्पेट और डॉ. जेनिशी तागुशी जैसे अन्य विशेषज्ञों के भारत दौरे का आयोजन कर अग्रणी भूमिका निभाई। फिर संस्थान के एसक्यूसी को बढ़ावा देने का कार्य धीरे-धीरे भारत के सभी औद्योगिक केन्द्रों तक शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाओं जैसे व्यापक कार्यक्रम के अधीन फैल गया। संस्थान भारत की "गुणवत्ता परिषद" का सदस्य भी बन गया।

[3]भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959, 1959 का क्रमांक 057

7.6 शुरुआती दिनों से, संस्थान दुनिया भर से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कई महीनों या उससे भी अधिक दिनों तक संस्थान में कार्य किया है। आधुनिक सांख्यिकी के एक पथप्रदर्शक सर रोनाल्ड फिशर एक नियमित अतिथि थे जिन्होंने संस्थान को काफी सहारा दिया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आनुवंशिकीविद् प्रोफेसर जे.बी.एस. हाल्डेन सन् 1957 से कई वर्षों तक संकाय सदस्य रहे। प्रख्यात गणितज्ञ नोर्बर्ट वीनर ने दो बार, 1954 और फिर 1955-56 में संस्थान का दौरा किया। अन्य शैक्षणिक व्यक्तित्व जिन्होंने संस्थान के विकास को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं

Professor and Mrs. Neils Bohr were shown round the electronic division of ISI, January, 1960

हेरोल्ड होटलिंग, फ्रैंक येट्स, हर्मन वॉल्ड, एडविन हार्पर (जूनियर) और एच क्रेमर, पीटर जे. बिकेल, डेविड कॉक्स जैसे सांख्यिकीविदय ए.एन. कोल्मोगोरोव, यू.वी. लिनिक, जे.एल. दूब और फिर वॉन एफ.आर.जोन्स, लोत्फी ए. जादेह जैसे गणितज्ञय वाल्टर श्योहार्ट और जी तागुची जैसे सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञय साइमन कुज्नेट, पॉल ए बारां, जॉन रॉबिन्सन, जेन टिंबर्जेन, निकोलस काल्डोर, आर.एम. गुडविन, रूथ ग्लास एवं जे.के. गालब्रेथ तथा हाल के अमर्त्य के. सेन, रॉबर्ट औमान, जोसेफ ई. स्टिग्लिज, जेम्स ए मिर्लीस, एरिक स्टार्क मस्किन, ईआई-इची नेगिशी, अदा योनाथ, डेविड जोनाथन ग्रोस्स, जोअकिम फ्रैंक जैसे अर्थशास्त्रीय पामेला रॉबिन्सन जैसे भूविज्ञानीय एन. डब्ल्यू पिरी जैसे जीव रसायनज्ञानी और डी. कॉस्टिक जैसे भाषाविद्। हमेशा से संस्थान ने रोनाल्ड फिशर की इस उक्ति पर चलने का प्रयास किया है कि सांख्यिकी सभी वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति अपनी अंतरंग प्रासंगिकता की दृष्टि से एक "प्रमुख प्रौद्योगिकी" है जिसमें प्रयोग, माप और नमूना से पूर्णयोग का निष्कर्ष शामिल है।

7.7 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान की समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष 1953 में संस्थान में एक छोटे एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया गया और उसका निर्माण किया गया। वर्ष 1956 में संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम से एक एचईसी-2 एम मशीन अर्जित किया जो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। साठ के दशक के प्रारम्भ में संस्थान ने जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएसआईजेयू-1 नामक एक पूर्णतः ट्रांजिस्टरीकृत डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन बनाने, उसे विकसित करने एवं उसके निर्माण का कार्य हाथ में लिया जिसे वर्ष 1966 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा चालू किया गया। पिछले छह दशकों

देश के विभिन्न कोनों में स्थित अईएसआई मुख्यालय समेत बहिर्वर्ती केंद्रों, शाखओं, यूनिटों के प्रवेश द्वारा

से संस्थान के अंतरराष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च कोटि के अनुसंधान, प्रकाशन एवं विकास का कार्य किया और उनके अथक प्रयासों ने संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पटल पर अग्रभाग में ला खड़ा किया है।

दिनांक 29 जून, 2023 को प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की 130वीं जन्म जयंती एवं सांख्यिकी दिवस का आयोजन

शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रभाग

7.8 शैक्षणिक सत्र 2023-2024 के दौरान, कुल 18,060 उम्मीदवारों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया और संस्थान द्वारा प्रस्तावित चौदह (14) कार्यक्रमों के लिए लिखित चयन परीक्षा के लिए बुलाया गया। 2003 में, कुल 11996 उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा के लिए 72 विभिन्न केंद्रों पर भाग लिया, 1191 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया, 507 उम्मीदवारों को प्रवेश दिया गया और 485 उम्मीदवारों ने शैक्षणिक सत्र के दौरान विभिन्न शोध और गैर-शोध पाठ्यक्रमों में प्रवेश लिया। इसके अलावा, सरकारी क्षेत्र से पांच प्रायोजित उम्मीदवारों ने भी प्रवेश लिया।

दिनांक 19 दिसंबर, 2023 को आयोजित संस्थान का 58वां दीक्षांत समारोह

7.9 अनुप्रयुक्त सांख्यिकी कार्यक्रम में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएएस) आईएसआई द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक वर्षीय ऑन-लाइन डिप्लोमा कार्यक्रम है। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में नियमित चैनल के लिए 92 और ट्यूशन माफ चैनल के माध्यम से 24 उम्मीदवारों का पंजीकरण किया गया था।

7.10 बिजनेस एनालिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा (पीजीडीबीए) की 65 सीटों के लिए, जो कि आईएसआई, आईआईटी खड़गपुर और आईआईएम कलकत्ता द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया जाने वाला दो वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा कार्यक्रम है, 1974 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, 1497 उम्मीदवार लिखित परीक्षा में शामिल हुए, 329 उम्मीदवारों और 61 छात्रों ने कार्यक्रम में नामांकन कराया।

7.11 दिनांक 31 मार्च 2024 तक, विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों के 73 प्रशिक्षुओं को संस्थान के विभिन्न संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में संस्थान की विभिन्न इकाइयों में एक से छह महीने का प्रोजेक्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी)

7.12 अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी) की स्थापना सन् 1950 में प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की पहल पर अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के बीच एक समझौते के माध्यम से कोलकाता में खोला गया, वर्तमान में यह केंद्र भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चलाया जाता है। यह केंद्र एक निदेशक मण्डल के अधीन कार्य करता है जिसके वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर एस. पी. मुखर्जी हैं। इस केंद्र का उद्देश्य मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एवं अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों से चयनित प्रतिभागियों के लिए विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है।

29 अगस्त 2023 को आयोजित 74वां सत्र आईएसईसी दीक्षांत समारोह

सांख्यिकी स्नातक (प्रतिष्ठा)य गणित स्नातक (प्रतिष्ठा)य सांख्यिकी निष्णातय गणित निष्णातय मात्रात्मक अर्थशास्त्र में विज्ञान निष्णातय गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान में विज्ञान निष्णातय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में विज्ञान निष्णातय कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी निष्णातयक्रिप्टोलोजी एवं सिक्यूरिटी में विज्ञान निष्णातय गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान में प्रौद्योगिकी निष्णातय सांख्यिकीय विधि एवं वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमाय अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा (ऑनलाइन पाठ्यक्रम) सांख्यिकीय विधियों और विश्लेषिकी के साथ कृषि और ग्रामीण प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञानय गुणवत्ता,विश्वसनीयता एवं क्रियात्मक अनुसंधान, भौतिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित, जैविक विज्ञान (मानव आनुवंशिकी) जैविक विज्ञान (कृषि एवं पारिस्थितिक अनुसंधान) और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान और समाजशास्त्र में अनुसंधान शिक्षावृत्ति।

प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकी (शीर्षक सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं अनुप्रयोग) में 10 महीने का एक नियमित पाठ्यक्रम है जिसके परिणामस्वरूप सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। जिसे आंशिक रूप से भारत सरकार के विदेश मंत्रालय (एमईए) के भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (आईटीईसी) कार्यक्रम द्वारा वित्त पोषित किया जाता है एवं आईएसआई द्वारा प्रदान किए गए सहयोग से संचालित किया जाता है। इसके अलावा, अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग अवधि के विशेष पाठ्यक्रम किसी उक्त देश के अनुरोध पर भी आयोजित किए जाते हैं।

7.13 वर्तमान शैक्षणिक वर्ष (2023-24) में सांख्यिकीय सिद्धांत और अनुप्रयोगों पर नियमित 10-माह के पाठ्यक्रम का 75 वां सत्र संचालित किया जा रहा है। यह 01 सितंबर, 2023 से शुरू हुआ और 30 जून, 2024 को समाप्त होगा। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केंद्र (आईएसईसी) ने 30 अक्टूबर-10 नवंबर, 2023 के दौरान घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करने हेतु नमूनाकरण पद्धतियाँ नामक एक पाठ्यक्रम का आयोजन किया। 7 विभिन्न देशों 13 प्रतिभागियों अर्थात् घाना, जमैका, मालदीव, दक्षिण सूडान, थाईलैंड, तंजानिया और वियतनाम ने पाठ्यक्रम में भाग लिया।

अनुसंधान कार्य

7.14 संस्थान के अनुसंधान, विकास और परामर्श गतिविधियों को सात शैक्षणिक प्रभागों में वर्गीकृत किया गया अर्थात सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणितय अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कंप्यूटर और संचार विज्ञानय भौतिकी और पृथ्वी विज्ञानय जैविक विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान प्रभाग तथा कंप्यूटर एवं सांख्यिकीय सेवा केंद्र, संस्थान को सेवाएँ प्रदान करते हैं।

7.15 इसके अलावा अन्य दो केंद्र हैं यथा-सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान : एक राष्ट्रीय सुविधा तथा आर.सी. बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलोजी एंड सिक्यूरिटी। "सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्रः एक राष्ट्रीय दक्षता" संस्थान में सॉफ्ट कंप्यूटिंग और मशीन इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट योगदान और उपलब्धियों के साथ कार्य कर रहा है। केंद्र का उद्देश्य सॉफ्ट कंप्यूटिंग के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय मानक के सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों तरह के अनुसंधान करना है। आर.सी. बोस क्रिप्टोलॉजी एवं सुरक्षा केंद्र क्रिप्टोलॉजी और साइबर सुरक्षा में शिक्षण, अनुसंधान के साथ-साथ प्रशिक्षण और विकास को आगे बढ़ाने के लिए गणित, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी में अंतःविषय अनुसंधान को बढ़ावा देता है। यह अध्ययन के सभी प्रासंगिक क्षेत्रों में क्रिप्टोग्राफिक आवश्यकताओं, अत्याधुनिक अनुसंधान गतिविधियों और स्वदेशी क्षमता निर्माण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में कार्य करता है।

7.16 उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में तीन अन्य अनुसंधान केंद्र भी हैं तथा वे दिल्ली केंद्र स्थित जलवायू, खाद्य, ऊर्जा एवं पर्यावरण के अर्थशास्त्र पर अनुसंधान (सीईसीएफईई) केंद्र तथा मुख्यालय, कोलकाता स्थित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग हेतु (सीएआईएमएल) केंद्र साथ ही मुख्यालय कोलकाता स्थित एक प्रौद्योगिकी नवाचार हब (टीआईएच) सहित केंद्र हैं. सीईसीएफईई आर्थिक कार्य विभाग में जलवायू परिवर्तन वित्त यूनिट, एमओएफ के साथ संलग्न है, जी20 की अध्यक्षता के दौरान सीईसीएफईई ने कार्बन मूल्य निर्धारण तथा जलवायू वित्त रिपोर्ट के प्रति अवदान किया है. इस केंद्र के अनुसंधानकर्तागण स्वास्थ्य, लिंग, खाद्य, कृषि, उत्सर्जन एवं नीति डिजाईन सदृश विविध विषय-क्षेत्र की खोज करते हैं, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं मशीन लर्निंग हेतु केंद्र (सीएआईएमएल) भारत में एआई का हब बनने की दिशा में प्रयासरत है। यह एआई के लाभों को अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से एआई के सिद्धांतों और कार्यप्रणाली के विकास पर काम करेगा। यह केंद्र हमारे देश के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र (यूएन) को उनके कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स एंड साइंस फाउंडेशन प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुवाद, एचआरडी, टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर (टीबीआई) साथ ही डेटा साइंस, बिग डेटा एनालिटिक्स और डेटा क्यूरेशन के क्षेत्र में स्टार्ट-अप डेवलपमेंट एवं अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता अनुसंधान में ध्यान केंद्रित करने के लिए अंतर्शास्त्रीय साइबर-फिजिकल सिस्टम्स (एनएम-आईसीपीएस) पर राष्ट्रीय मिशन के तत्वावधान में आईएसआई कोलकाता में स्थापित टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब (आईडीईएएस-टीआईएच) है। आईडीईएएस-टीआईएच मार्च 2021 में आईएसआई में अस्तित्व में आया। कई अनुवादात्मक अनुसंधान परियोजनाएं पहले से ही चल रही हैं, उनमें से कुछ अन्य भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ सहभागिता में कार्यरत हैं।

उन्नत कम्प्यूटिंग एवं माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट, कृषि एवं पारिस्थितिक अनुसंधान यूनिट,कंप्युटर विजन एवं प्रतिमान पहचान यूनिट, इलेक्ट्रानिक्स एवं संचार विज्ञान यूनिट, भूविज्ञान अध्ययन यूनिट, अंतर्विषयक सांख्यिकीय अनुसंधान यूनिट, यंत्र आसूचना यूनिट, भौतिकी एव अनुप्रयुक्त गणित यूनिट, प्रतिचयन एवं साधिकारिक सांख्यिकी यूनिट और सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान यूनिट।

संस्थान के विनियमन संख्या 14 के अनुसार आईएसआई का एक सहयोगी संस्थान है।

7.17 मुख्यालय में स्थित स्थापित कंप्यूटर और सांख्यिकी सेवा केंद्र (सीएसएससी) अपने संपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे और इसके साथ सम्बद्ध विभिन्न पाठ्यक्रम के छात्रों, संकाय, वैज्ञानिकों और प्रशासनिक कर्मचारियों सहित अपने उपयोगकर्ताओं के संबंधित मुद्दों के प्रबंधन, रखरखाव और समर्थन के लिए जिम्मेदार है।

संख्या – भारतीय सांख्यिकीय जर्नल

7.18 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक आधिकारिक प्रकाशन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिका सांख्य की नींव प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस ने 1932 में डाली और उनके संपादकत्व में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। यह संभाव्यता, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मूल शोध लेख के लिए समर्पित है। उपरोक्त क्षेत्रों में समीक्षा और वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्य में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत लेख की स्वीकृति के लिए एक कठोर समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया है। संभाव्यता, सैद्धांतिक सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर कई मौलिक लेख सांख्य में प्रकाशित किए गए हैं।

7.19 यह पत्रिका दो अलग सिरीज में प्रकाशित होती है - सिरीज 'ए' और सिरीज 'बी'। प्रतिवर्ष फरवरी और अगस्त में प्रकाशित होने वाले सिरीज 'ए' में संभाव्यता और सैद्धांतिक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष मई और नवंबर में प्रकाशित होनेवाले सिरीज 'बी' में अनुप्रयुक्त और अंतःविषयक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है। 2010 के प्रारंभ से, संस्थान स्प्रिंगर के साथ संख्या के अंतरराष्ट्रीय संस्करण को प्रिंट करने और विपणन करने के लिए दोनों प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में सहयोग कर रहा है। संपादकीय प्रणाली अब इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। सांख्य सीरीज ए और बी के प्रत्येक संस्करण के लेखों तक पहुंच निम्नलिखित वेबसाइटों के माध्यम से उपलब्ध है:

- सीरीज एः https://www.springer.com.journal.13171
- सीरीज बीः https://www.springer.com.journal.13571

7.20 सांख्यिकीय वित्त में हालिया प्रगति पर सीरीज बी (खंड 85, अनुपूरक अंक 1) का एक विशेष अंक मई 2023 में प्रकाशित किया गया था। इस विशेष अंक का संपादन रितुपर्णा सेन, सौरीश दास और सुजीत के घोष द्वारा किया गया था। इसके अतिरिक्त, श्रृंखला बी के दो नियमित अंक (खंड 85, अंक 1 और 2) क्रमशः मई 2023 और नवंबर 2023 में प्रकाशित किए गए थे। सीरीज ए के दो नियमित अंक (खंड 85, अंक 1 और 2) क्रमशः फरवरी 2023 और अगस्त 2023 में प्रकाशित हुए थे। सीरीज ए और सीरीज बी के अगले अंक सामान्य रूप से फरवरी 2024 और मई 2024 में प्रकाशित किए जाएंगे।

वैज्ञानिक लेख और प्रकाशन

7.21 वर्ष के दौरान लगभग छः सौ एकहत्तर वैज्ञानिक लेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

विदेश में वैज्ञानिक कार्य

7.22 संस्थान के ईकसठ वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए निमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत अनेक देशों में कई अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों का दौरा किया। उनमें से अधिकांश ने वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किए और उन सेमिनारों और सम्मेलनों में व्याख्यान दिए।

(i) कंप्यूटर लैब, (ii) वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क आर्किटेक्चर दोनों पर आधारित नेटवर्किंग सुविधा, (iii) कई उच्च कार्य प्रदर्शन उपकरणों द्वारा समर्थित कम्प्यूटेशनल सर्वर, (iv) सर्वरों का वर्चुअलाइजेशन, (v) मशीन लर्निंग आधारित अनुसंधान अध्ययन को सुविधासम्पन्न करने के लिए जीपीयू पर आधारित सुपर उच्च कार्य-प्रदर्शन कम्प्यूटेशन हेतु समर्थन (अप) इंटरनेट सुविधा और फायरवॉल के माध्यम से इसकी सुरक्षा, (vii) ईमेल सर्वर और स्पैम फिल्टर, (viii) वेबसाइट का डिजाइन, अपडेट और नियमित रखरखाव, (i)) माइक्रोसहफ्ट विंडोज, लिनक्स सहित विभिन्न ऑपरेटिंग सिस्टम, (ii) सीश्शी, जावा, आर, पायथन, फोर्ट्रान आदि सहित विभिन्न कंप्यूटर भाषाओं के कंपाइलर, (स्रप) विभिन्न सॉफ्टवेयर पैकेज जिनमें आर, मैटलैब और इसके विभिन्न टूल बॉक्स शामिल हैं, मैथमेटिका, एसपीएसएस आदि, (ii) विभिन्न डेटाबेस पैकेज जैसे एमवाईएसक्यूएल, पोस्ट्रे एसक्यूएल, (iii) आईडीआरआईएसआई (भूवैज्ञानिक सूचना प्रणाली), (स्रपअ) जूम ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल के माध्यम से ऑनलाइन मीटिंग समर्थन, (v) सायमेक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर (एचपीसी) प्रणाली आदि समर्थन शामिल हैं।

अभ्यागत वैज्ञानिकगण

7.23 अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, मलेशिया, नॉर्वे, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, यूके, यूएसए और भारत के भीतर भी दो सौ छियालीस वैज्ञानिकों ने संस्थान द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों, सेमिनारों आदि में भाग लिया। उनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने संस्थान के सहयोगात्मक अनुसंधान, शिक्षण और अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों में भी सहभागिता दर्ज की ।

आईएसआई वैज्ञानिकों का सम्मान

7.24 संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए गए अनुसंधान और वैज्ञानिक उत्कृष्टता के उच्च मानक की सराहना और मान्यता में, कई संकाय सदस्यों को कई विश्वविद्यालयों संस्थानों आदि से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के संगठनों से पुरस्कार, फेलोशिप के रूप में प्रशंसा मिली जैसे कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, वारविक विश्वविद्यालयय ब्रिटिश अकादमीय भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, भारत (एनएएसआई) विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), डीएसटी, भारत सरकारय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) भारतीय राष्ट्रीय इंजीनियरिंग अकादमी (आईएनएई); राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड (एनबीएचएम) आदि। इसके अलावा, कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों/निकायों द्वारा अपनी कई समितियों/संपादकीय बोर्डों आदि में अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य संपादक, संपादक, समीक्षक के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उनमें से, संकाय सदस्यों द्वारा अर्जित की गई कुछ सबसे उल्लेखनीय मान्यताएँ नीचे दर्शाया गया है:-

- प्रोफेसर मधुरा स्वामीनाथन को अध्यक्ष, अनुसंधान सलाहकार समिति, आईसीएआर-केंद्रीय कृषि महिला संस्थान, 2022-25 के लिए चुना गया।
- प्रो. नीना गुप्ता को द्वितीय गणित रत्न पुरस्कार, 2023 से सम्मानित किया गया एवं उन्हें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) का फेलो चुना गया।
- प्रोफेसर अरूप बोस को सांख्यिकी में जीवनपर्यंत उपलब्धियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 2023 से सम्मानित किया गया।
- प्रोफेसर बी.एस. दया सागर को विज्ञान, 2024-जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) का फेलो चुना गया।
- प्रोफेसर जयदेब सरकार को फेलो एन ए एस ई, (NASI), 2023 चुना गया।
- प्रो. रघुनाथ चटर्जी को अनुसंधान हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार, एसईआरबी, डीएसटी, भारत सरकार, से सम्मानित किया गया।
- प्रोफेसर उत्पल गराइन को फेलो ऑफ इंडियन नेशनल एकेडमी अहफ इंजीनियरिंग (आईएनएई), 2023 से सम्मानित किया गया है।
- प्रोफेसर उमापद पाल को कंप्यूटर विजन और इमेज प्रोसेसिंग में उनके शोध योगदान के लिए सीवीआईपी-2023 लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया।
- प्रोफेसर शंकर कुमार पाल, एमेरिटस प्रोफेसर को 30वीं पश्चिम बंगाल राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कांग्रेस, 2023 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के 30वें प्रशांत चंद्र महालनोबिस मेमोरियल लेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित पूर्व छात्र पुरस्कार 2023, रामकृष्ण मिशन विवेकानन्द सेंटेनरी कॉलेज, कलकत्ता (यह पुरस्कार 1963 में अपनी स्थापना के बाद से कॉलेज के 60 वर्षों के इतिहास में पहली बार किसी पूर्व छात्र को दिया गया था) और संस्थापक फेलो, वेब इंटेलिजेंस अकादमी (डब्ल्यूआईए), 2023 चयनित किया गया ।

ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेशय बेल्जियम, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, डेनमार्क, फ्रांस, ग्रीस, जर्मनी, हांगकांग, इंडोनेशिया, इजराइल, ईरान, इटली, जापान, कोरिया, मलेशिया, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, कतर, स्कॉटलैंड, स्पेन, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, ताइवान, यूके और यूएसए

- प्रो. सोमनाथ दासगुप्ता को पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए भारतीय भूभौतिकीय संघ द्वारा हरिनारायण लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया।
- प्रोफेसर शांता लैशराम को राष्ट्रीय उच्च गणित बोर्ड (एनबीएचएम) की ओलंपियाड गतिविधि समिति का सदस्य चुना गया।
- प्रोफेसर किरणमय दास को लैंसेट हेल्दी लॉन्गविटी, इम्पैक्ट फैक्टर=13-1 (जुलाई 2023 से) पत्रिका के लिए सांख्यिकीय सलाहकार चुना गया एवं लैंसेट समूह के संपादकीय बोर्ड द्वारा बायोस्टैटिस्टिक्स विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया।
- प्रोफेसर अभिरूप मुखोपाध्याय को अनुसंधान कार्य के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी, वारविक विश्वविद्यालय, यूनाइटेड किंगडम का फेलोय पूर्ण अध्यक्ष, आईआईटी, कानपुर और मुख्य वक्ता, हेरिटेज कॉलेज (कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध) के अर्थशास्त्र और वाणिज्यः 24 फरवरी 2024 और बिट्स पिलानी-हैदराबाद, 09 फरवरी 2024 चुना गया है।
- प्रोफेसर नीलाद्री शेखर दाश को भाषा विशेषज्ञ, शिक्षार्थी शब्दावली (I-V) को अंतिम रूप देने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी शर्तों के आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए चुना गया है, अप्रैल 2023; शब्द सिंधु के लिए वैचारिक समकक्षों का विकास, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, जुलाई-अक्टूबर 2023 और गणित की मौलिक शब्दावली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, मई 2023 य लेक्सिकोग्राफिक सलाहकार, बंगाली डिक्शनरी प्रोजेक्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, ऑक्सफोर्ड, यूके, जून-अगस्त 2023 के दौरानय भाषाविज्ञान विशेषज्ञ, भाषाविज्ञान की मौलिक शब्दावली, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, अगस्त 2023; पैनल सदस्य, परीक्षण विकास और पेपर सेटिंगः भाषाविज्ञान (31), यूजीसी-नेट 2023, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, भारत सरकार, सितंबर 2023 य ब्रिटिश अकादमी, यूके (संयुक्त रूप से) 2022-2024 द्वारा ब्रिटिश अकादमी/लेवरहुल्मे लघु अनुसंधान अनुदान प्राप्त किया।
- प्रबंधन और प्रौद्योगिकी में समसामयिक मुद्दों और चुनौतियों पर सम्मेलन आयोजित करने के लिए प्रो. तरुण कबीराज को नरूला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कोलकाता की सलाहकार समिति का सदस्य चुना गया है।
- प्रोफेसर अरुणाभ सेन को गेम थ्योरी सोसाइटी का फेलो चुना गया है, यह सोसाइटी गेम थ्योरी के प्रति उनकी सेवा और उनके योगदान के लिए सम्मानित लोगों का एक समूह है, और संचालन समिति के लिए सलाह का एक स्रोत है।
- डॉ. सांतनु के. माइति को अनुसंधान गतिविधियों के लिए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में विश्व भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों में सूचीबद्ध किया गया।
- प्रोफेसर आशीष घोष को आईआईआईटी भुवनेश्वर का निदेशक चुना गया।
- डॉ. मुतुशी चटर्जी को प्रतिष्ठित (i) एनल्स ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च, (ii) जर्नल ऑफ स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन एंड सिमुलेशन, (iii) जर्नल ऑफ क्वालिटी टेक्नोलॉजी, और (iv) साइंटिफिक रिपोर्ट के लिए कार्यवाहक समीक्षक चुना गया।
- डॉ. जगदीश को 27 जुलाई 2023 को मैकेनिकल इंजीनियरों के लिए डेटा एनालिटिक्स पर एमवीजे कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, बैंगलोर, कर्नाटक के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग में अतिथि वक्ता चुना गया।
- डॉ. मलय भट्टाचार्य को वैज्ञानिक प्रबंधन में योगदान के लिए एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी (एसीएम) प्रकाशन बोर्ड की मूल्यांकन और खोज समिति का सदस्य चुना गया।
- डॉ. अनीसुर रहमान, मोल्ला, जनरल चेयर, वितरित कंप्यूटिंग और इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी (आईसीडीसीआईटी) पर 20वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, 2024 में वितरित कंप्यूटिंग में विशेषज्ञ के रूप में और उन्हें आईसीडीसीआईटी, 2024 की कार्यवाही, आईसीडीसीआईटी-2024 और सम्मेलन के स्वीकृत पत्रों का संपादन के लिए स्प्रिंगर हेतु सह-संपादक चुना गया है ।
- डॉ. योगेश्वरन डी. को संपादकीय बोर्ड, इनफिनिट डाइमेन्शनल एनालिसिस एंड क्वांटम प्रोबीबिलिटी, सीएनआरएस 'पोस्टेस रूज' (विजिटिंग पोजीशन) का सदस्य चुना गया।

- प्रोफेसर फरजाना अफरीदी को बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन फॉर डिजिटल प्लेटफॉर्म और डब्ल्यू .ई.ईः व्हाट मैटर्स एंड व्हाट वर्क्स से रिसर्च अनुदान (2022-25) प्राप्त हुआ।
- डॉ. कनिष्का कक्कर को बेस्ट डिस्कशन पेपर पुरस्कार, पर्यावरण विकास पहल, 2023 पीटर बर्क बेस्ट डिस्कशन पेपर पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
- प्रो. संदीप मित्रा को मूल्यांकन हेतु तकनीकी सलाहकार समिति, नीति आयोग का सदस्य चुना गया ।
- प्रो. नचिकेता चट्टोपाध्याय को वैकल्पिक एएसपी सुझाव प्रदाता समिति, खनिज मंत्रालय का सदस्य चुना गया।

बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

7.25 सैद्धांतिक और प्रायोगिक योजना अनुसंधान के अलावा, संस्थान द्वारा सीएसआईआरओ, ऑस्ट्रेलिया जैसे विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी संगठनों से लगभग दो सौ बाह्य वित्त पोषित परियोजनाएं भी आरम्भ की गई है।[4]

कार्यशालाएँ , संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, परिगोष्ठियाँ

7.26 वर्ष के दौरान संस्थान ने भारत और विदेशों से प्रमुख शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ कई संगोष्ठी, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, परिगोष्ठियों का आयोजन किया। उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :-

- दिनांक 08 अप्रैल, 2023 को "ईबीएससीओ (पूर्ण पाठ के साथ इकोनलिट)" पर ऑनसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम, पुस्तकालय, प्रलेखन एवं सूचना विज्ञान प्रभाग, कोलकाता, आभासी रूप से।
- दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को "हार्नेकिन समानताएं, कोन्फोर्मल वॉक डाइमेन्शन एंड जिओमेट्रिक स्टेबल प्रोसैस" पर सेमिनार, सैद्धांतिक सांख्यिकी एवं गणित यूनिट, बैंगलोर।
- दिनांक 14-16 और 28-30 अप्रैल, 2023 के दौरान "सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन", पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, एसक्यूसी और ओआर यूनिट, मुंबई।
- दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को "मजदूरों का एक प्रभागः भारत में पहचान और दक्षता" पर सेमिनार, अर्थशास्त्र एवं आयोजना यूनिट, दिल्ली, आभासी रूप से।
- दिनांक 26 अप्रैल, 2023 को "पृथ्वी अवलोकन डेटा विश्लेषण" पर एक दिवसीय सेमिनार, टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब।
- दिनांक 16 मई, 2023 को "क्रोनिक हृदय रोगों के लिए आईओटी (IoT) और एआई (AI) संचालित स्क्रीनिंग" पर सेमिनार, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता, आभासी रूप से।
- दिनांक 22 मई, 2023 को "सेवरल वेरिएबल में कम्प्यूटेंट लिफ्टिंग, इंटरपोलेशन और टोप्लिट्ज ऑपरेटर्स" पर सेमिनार, सैद्धांतिक सांख्यिकी एवं गणित यूनिट, बैंगलोर।

---

[1]सीएसआईआरओ ऑस्ट्रेलिया बेबीसेंसर, नॉर्वेय उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इंडो-फ्रेंच सेंटर (आईएफसीपीएआर) मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, यूक; एसआरसी, यूएसए; यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग, यूके; पी.जे. सफारिक विश्वविद्याल;, स्लोवाकियाय इंडो-यूएस वर्चुअल नेटवर्क सेंटर; गूगल; विकास पहल के लिए पर्यावरण (ईएफडी), स्वीडन; आईबीएम, यूएसएय ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय, मोनाश विश्वविद्यालय, ऑस्ट्रेलिया; एशियाई विकास बैंक; विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी), डीएसटी, भारत सरकार; नीति आयोग; एमईआईटीवाई, भारत सरकार; इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम (आईसीपीएस), डीएसटी, भारत सरकार; जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी); इसरो; डीआरडीओ; एनएआई, काशीपुरय केनरा बैंक; राष्ट्रीय भू-स्थानिक कार्यक्रम, डीएसटी, भारत सरकारय संज्ञानात्मक विज्ञान अनुसंधान पहल, डीएसटी, भारत सरकार; राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (आरसीएफएल), भारत सरकार; आईबीसीडी, डीएसटी, भारत सरकार; आईटीईसी, विदेश मंत्रालय, भारत सरकारय भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर), नई दिल्ली, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार; डीएसटी-आईटीपीएआर-प्टः भारत सरकार; इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स एंड साइंस फाउंडेशन (आईडीईएएस); एनसीपीओआर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार; एनएसएसटीए, एम.ओ.एस. एवं पी.आई., भारत सरकार; भारतीय रिजर्व बैंकय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई); सेमीकंडक्टर रिसर्च कॉर्पोरेशन (एसआरसी) भारतय भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), नई दिल्लीय 5वां राज्य वित्त आयोग (एसएफसी), पश्चिम बंगाल सरकार; डेस, त्रिपुरा सरकार; टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज; टाटा इस्पात; बिड़ला जूट मिल्स; आईटीसी लिमिटेड, पेपर बोर्ड एवं स्पेशलिटी पेपर्स डिवीजन, यूनिटः कोवई; सीरम संस्थानय गुणवत्ता आश्वासन रक्षा संस्थान; दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेडय वाल्वोइल द्रव शक्तिय कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर); आईटीसी लिमिटेड; बीईएमएल; प्रोबो इंडिया लिमिटेड; एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड; एमओएल सूचना प्रौद्योगिकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड; जमशेदपुर प्रबंधन संगठन; यूपीएल लिमिटेडय बीएनपी पारिबास सिक्योरिटीज; जीआईए, मुंबईय शोट पूनावाला, गुजरात; बालासोर एल्वाइज, बालासोर; रिलायंस, वडोदरा; हुंडई मोटर्स; जीई हेल्थकेयर; एचएएल प्रबंधन अकादमी; स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेडय डेमलर, चेन्नई; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; जमशेदपुर प्रबंधन अकादमी; किर्लोस्कर; टोयोटा

- दिनांक 27 मई, 2023 को "सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान पद्धतियां एक सांख्यिकीय दृष्टिकोण," पर कार्यशाला, अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 08-12 मई 2023 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग के लिए "गणित की मौलिक शब्दावली (अंग्रेजी-हिंदी-बंगाली) की तैयारी" के लिए पांच दिवसीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति की बैठक सह कार्यशाला, भाषावैज्ञानिक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार।
- दिनांक 18 मई, 2023 को "साउथ एशियन रिसर्च नेटवर्क फॉर चाइल्डहुड एंड यूथ स्टडीज (एस ए आर एन सी वाई एन): एक संक्षिप्त अवलोकन" पर सेमिनार, अर्थशास्त्र अनुसंधान यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 31 मई - 14 जुलाई 2023 के दौरान "कंप्यूटर विजन, इमेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग" पर आठवां समर स्कूल, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विज्ञान यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 01 जून, 2023 को "मतदान में ओप्टीमिलिटी एवं रणनीति प्रमाणता" पर साप्ताहिक सेमिनार, कंप्यूटर साइंस यूनिट, चेन्नई।
- दिनांक 02-04 जून 2022 के दौरान "आईईईई वीनतेचकों 2022" पर कार्यशाला, इलेक्टॉनिक्स एवं संचार विज्ञान यूनिट, कोलकाता, आभासी रूप से।
- दिनांक 11 जून, 2023 को "नेविगेटिंग द वॉल स्ट्रीट जर्नल", लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन और सूचना विज्ञान प्रभाग, कोलकाता पर वेबिनार, आभासी रूप से।
- दिनांक 12-17 जून और 03-08 जुलाई, 2023 के दौरान "मास्टर ब्लैक बेल्ट प्रोग्राम", एसक्यूसी और ओआर यूनिट, मुंबई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- दिनांक 26 जून - 21 जुलाई, 2023 के दौरान प्रो. अरूप बोस की जेसी बोस फेलोशिप के सहयोग और समर्थन में सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणित यूनिट, कोलकाता की सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणित यूनिट, "स्टोकेस्टिक प्रक्रियाओं पर बुनियादी निर्देशात्मक स्कूल" पर कार्यशाला।
- जुलाई-सितंबर 2023 के दौरान "मशीन लर्निंग", एसक्यूसी और ओआर यूनिट, हैदराबाद पर ऑनलाइन कार्यक्रम, आभासी रूप से।
- दिनांक 10-14 जुलाई, 2023 के दौरान प्रौद्योगिकी नवाचार हब, "बाढ़ और सूखे पर ध्यान केंद्रित करते हुए आपदा प्रबंधन के लिए पृथ्वी अवलोकन (ईओ) डेटा एनालिटिक्स" पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- "इमेज फिल्टरिंग एवं ब्रेन डेटा विश्लेषण के लिए कम्प्यूटेशनल तरीके", इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार विज्ञान यूनिट, कोलकाता, 14 जुलाई, 2023 पर सेमिनार।
- दिनांक 17 जुलाई 2023 को आरबीआई के सहयोग से "वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट", प्रतिचयन एवं साधिकारिक सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता पर आउटरीच कार्यक्रम ।
- दिनांक 22 जुलाई - 06 अगस्त 2023 के दौरान "पायथन (बीएफ-07) का उपयोग करके बिजनेस फोरकास्टिंग" पर फाउंडेशन कोर्सः एसक्यूसी और ओआर यूनिट, बैंगलोर ।
- दिनांक 31 जुलाई - 05 अगस्त 2023 के दौरान "सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण", एसक्यूसी और ओआर यूनिट, कोलकाता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम।

(एसएफसी), पश्चिम बंगाल सरकार; डेस, त्रिपुरा सरकार; टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज; टाटा इस्पात; बिड़ला जूट मिल्स; आईटीसी लिमिटेड, पेपर बोर्ड एवं स्पेशलिटी पेपर्स डिवीजन, यूनिटः कोवई; सीरम संस्थान; गुणवत्ता आश्वासन रक्षा संस्थान; दीपक फर्टिलाइजर लिमिटेड; वाल्वोइल द्रव शक्ति; कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर); आईटीसी लिमिटेड; बीईएमएलयप्रोबो इंडिया लिमिटेड; एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेडय एमओएल सूचना प्रौद्योगिकी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड; कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड; जमशेदपुर प्रबंधन संगठन; यूपीएल लिमिटेड; बीएनपी पारिबास सिक्योरिटीज; जीआईए, मुंबई; शोट पूनावाला, गुजरात; बालासोर एल्वाइज, बालासोर; रिलायंस, वडोदरा; हुंडई मोटर्स; जीई हेल्थकेयर; एचएएल प्रबंधन अकादमी; स्ट्राइड्स फार्मा साइंस लिमिटेड; डेमलर, चेन्नई; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; जमशेदपुर प्रबंधन अकादमी; किर्लोस्कर; टोयोटा ।

- दिनांक 24 अगस्त, 2023 को "सामान्य क्वांटम राज्यों के लिए सख्त और मजबूत क्वांटम गति सीमाएं" पर संगोष्ठी, भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित यूनिट।
- दिनांक 26 - 27 अगस्त और 09 - 10 सितंबर 2023 के दौरान "प्रयोगों के डिजाइन का उपयोग करके समस्या समाधान (DoE-08)", एस क्यू सी एवं ओ आर यूनिट पर कार्यक्रम।
- दिनांक 27-28 अक्टूबर, 2023 के दौरान "सातवीं सीईसीएफईई वार्षिक अनुसंधान और नीति" पर कार्यशाला, अर्थशास्त्र एवं आयोजना यूनिट, दिल्ली द्वारा तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित की गई।
- दिनांक 03 नवंबर, 2023 को प्रोफेसर फिलिप मैनियन द्वारा "दक्षिण अमेरिका में अक्षांशीय जैव विविधता प्रवणता का विकास और उद्भव" पर सेमिनार, और प्रोफेसर पॉल अपचर्च, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन,यूके द्वारा "सैरोपॉड डायनासोर के उदय और प्रारंभिक विकास पर अजैविक और जैविक नियंत्रण" पर सेमिनार, भूवैज्ञानिक अध्ययन यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 06 नवंबर, 2023 को "एस्ट्रोसाइट्स के साथ स्पाइकिंग न्यूरल नेटवर्क का गणितीय मॉडलिंग" पर सेमिनार, भौतिकी एवं अनुप्रयुक्त गणित यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 06-07 नवंबर, 2023 के दौरान समाजशास्त्रीय अनुसंधान यूनिट, कोलकाता और गिरिडीह में "कोविड-19 महामारी के दौरान और उसके बाद आजीविका की चुनौतियां और अवसर" विषय पर कार्यशाला।
- दिनांक 08-10 नवंबर, 2023 के दौरान "पायथन का उपयोग करके डेटा विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता", सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त विज्ञान यूनिट (टीएएसयू), उत्तर-पूर्व केंद्र, तेजपुर पर तीन दिवसीय कार्यशाला।
- दिनांक 08-10 नवंबर, 2023 के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग केंद्र, "क्रिप्टोलॉजी के लिए मशीन लर्निंग" पर एक अंतःविषय कार्यशाला।
- दिनांक 20-25 नवंबर, 2023 के दौरान नॉर्थ-ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, तुरा कैंपस, मेघालय में "सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए सांख्यिकीय तरीके और खोजपूर्ण डेटा विश्लेषणः एक व्यावहारिक आर कार्यशाला", कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता और गिरिडीह पर कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित किया गया।
- दिनांक 20 नवंबर - 01 दिसंबर 2023 के दौरान "सांख्यिकीय शिक्षण और आर के साथ बायेसियन विश्लेषण", अंतर्विषयक सांख्यिकीय अनुसंधान यूनिट, कोलकाता पर कार्यशाला।
- दिनांक 24 नवंबर, 2023 को "चिकित्सकों के स्थानों में दृढ़ताः विकेंद्रीकृत ऋण पुनर्भुगतान कार्यक्रमों से दीर्घकालिक साक्ष्य", पर सेमिनार, अर्थशास्त्र और योजना यूनिट, दिल्ली।
- 24 नवंबर, 2023 को "रैंडम ओब्जेक्ट्स हेतु ज्यामितीय खोजपूर्ण डेटा विश्लेषण", पर सेमिनार, सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणित यूनिट, कोलकाता।
- नवंबर, 2023 के दौरान "डीस्पेस" पर कार्यशाला, दस्तावेजन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, बैंगलोर, आभासी रूप से।
- दिनांक 10-13 दिसंबर, 2023 के दौरान "इंडिया आईईईई जियोसाइंस एंड रिमोट सेंसिंग (इन जी ए आर एस एस) - 2023", आर्थिक विश्लेषण यूनिट, बैंगलोर पर संगोष्ठी अंतरराष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, बैंगलोर (आई आई आइ टीबी) में आयोजित की गई।
- दिनांक 12-15 दिसंबर, 2023 "पैटर्न रिकॉग्निशन एंड मशीन इंटेलिजेंस (PReMI) पर 10वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, मशीन इंटेलिजेंस यूनिट, कोलकाता।
- दिनांक 18-22 दिसंबर 2023 के दौरान "अनुसंधान पद्धति के लिए सांख्यिकीय तकनीक", पर कार्यशाला एसक्यूसी और ओआर यूनिट, मुंबई।
- दिनांक 19-23 दिसंबर, 2023 के दौरान सीएमआई, चेन्नई में आयोजित "वित्त में सांख्यिकीय तरीकों", अनुप्रयुक्त सांख्यिकी यूनिट, बैंगलोर पर 8वीं अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन आयोजित किया गया।

- दिनांक 21-22 दिसंबर, 2023 के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से भाषावैज्ञानिक अनुसंधान यूनिट, कोलकाता "सामाजिक विज्ञान में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द" पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी, आयोजित किया गया।
- दिनांक 01 और 03 मार्च, 2024 के दौरान "ऑप्टिमाइजेशन और गेम थ्योरी" पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, एसक्यूसी और ओआर यूनिट, चेन्नई, आईआईटी, मद्रास में आयोजित किया गया।
- दिनांक 05 फरवरी 2024 के दौरान "क्वांटम सांख्यिकीय अनुमान" पर आयोजित सेमिनार में मुख्य भाषण समृद्ध लाहिड़ी, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टेट-मैथ यूनिट, कोलकाता द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- दिनांक 21 फरवरी 2024 को "डिरिचलेट एल फंक्शन का गैर-लुप्त होना- II" पर आयोजित सेमिनार में मुख्य भाषण सम्पूर्ण पाल, स्टेट-मैथ यूनिट, कोलकाता द्वारा प्रस्तुत किया गया।
- दिनांक 28 फरवरी, 2024 को "भूमि या समुद्र?" पर व्याख्यान भूगोल ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद के उद्भव को कैसे आकार दिया "विषय पर जलवायु, खाद्य, ऊर्जा और पर्यावरण अर्थशास्त्र अनुसंधान केंद्र, दिल्ली, अर्थशास्त्र और योजना इकाई, दिल्ली के सहयोग से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर तीर्थंकर रॉय द्वारा व्याख्यान दिया गया।
- 04-22 मार्च 2024 के दौरान "डेटा एनालिटिक्स फॉर डिसीजन मेकिंग" पर आईटीईसी प्रायोजित पाठ्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र, इस कार्यक्रम के लिए 10 देशों से 15 प्रतिभागी उपस्थित थे।
- 04 मार्च, 2024 से 26 अप्रैल 2024 के दौरान "सर्वेक्षण पद्धति एवं डेटा एनालिटिक्स-आईएसएस प्रोबेशनर्स (45वें बैच) के लिए" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रतिचयन एवं आधिकारिक सांख्यिकी यूनिट, कोलकाता, आईएसएस परिवीक्षार्थी (45वां बैच)
- दिनांक 22 मार्च, 2024 के दौरान "बाढ़ के जोखिम के अनुकूल होनाः शहरों के एक वैश्विक पैनल से साक्ष्य" पर सेमिनार, अर्थशास्त्र और योजना इकाई, दिल्ली।
- 04-10 मार्च 2024 के दौरान "पर्यावरण अनुसंधान में सांख्यिकी और मशीन लर्निंग के अनुप्रयोग" पर डीएसटी एसईआरबी उच्च अंत कार्यशाला, सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान इकाई, उत्तर-पूर्व केंद्र, तेजपुर।
- दिनांक 28 मार्च-30 मार्च, 2024 के दौरान आईएसएस प्रोबेशनर्स (45वें बैच) के लिए आईएसआई-गिरिडीह और आईएसआई-कोलकाता द्वारा आयोजित "फार्म प्रबंधन पर आधिकारिक सांख्यिकी" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम, समन्वयकः हरिचरण बेहरा, गिरिडीह केंद्र।

आईएसएस परिवीक्षार्थी (45वां बैच)

अध्याय - 8

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

8.1 उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) 13 फरवरी, 2009 को अस्तित्व में आई। यह राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर सरकारी सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से पोषित करने वाला प्राथमिक संस्थान है। अकादमी राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, विशेष रूप से विकासशील तथा सार्क देशों में, सरकारी सांख्यिकी तथा संबंधित विषयों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्य में सक्रियतापूर्वक संलग्न है। अकादमी सामाजिक- आर्थिक पर्यावरण, तकनीकी विकास और पद्धतिगत विकास के संबंध में सांख्यिकीय श्रमबल को अवगत कराने और उन्हें अद्यतित रखने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस चुनौती को पूरा करने के लिए, वे अद्यतित पाठ्यक्रम सामग्री, संशोधित पाठ्यक्रम पाठ्यचर्चा तैयार करने और प्रभावी वितरण तंत्र लागू करने के लिए निरंतर प्रयास करता रहा है। वे शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं, और उनके पास केंद्रीय तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों में नए भर्ती तथा सेवारत सांख्यिकीय कार्मिकों दोनों के लिए एक केंद्रित प्रशिक्षण रणनीति है।

मुख्य अभिप्राय और उद्देश्य

8.2 इस अकादमी के मुख्य अभिप्राय और उद्देश्य इस प्रकार हैं:

क) देश के लिए नीतियां और योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंकड़ा संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और प्रसार की वर्तमान तथा उभरती दोनों प्रकार की चुनौतियों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल सृजित करना।

ख) विशिष्ट लघु/मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तरीय कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी और गैर-सांख्यिकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करना तथा

ग) विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं तथा यूएन/द्विपक्षी एजेंसियों से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा व्यवसायविदों के परामर्श और सहयोग से पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों के पूल का सृजन करना तथा प्रशिक्षण संबंधी सामग्री तैयार करना।

8.3 अपनाई गई प्रशिक्षण कार्यनीति नस्टा में प्रवेश और पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रमों, दोनों को आयोजित करना तथा अनेक अन्य अभिज्ञात प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ संस्थाओं को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण दिलवाना अपरिहार्य है। ये कार्यालय केंद्र सरकार में कार्यरत सांख्यिकीय कार्मिकों नामतः भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) अधिकारियों, भारतीय आर्थिक सेवा (आईईएस), केंद्र सरकार की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) पदाधिकारियों आरबीआई एवं आरजीआई के पदाधिकारियों, अभिज्ञात विषय क्षेत्रों में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सांख्यिकीय अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है। नस्टा मित्रवत और पड़ोसी एशियाई तथा अफ्रीकी देशों के सांख्यिकीय कर्मियों के क्षमता विकास के मामले में भी नियमित रूप से तकनीकी सहायता प्रदान करता है और उनके लिए अनुरोध आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

8.4 नस्टा अपने परिसर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, दोनों में आधिकारिक सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित मानव संसाधनों के प्रति संचेतना पैदा करने का प्रयास भी करता है। इन कार्यक्रमों में नस्टा में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तथा अकादमी और एनएसओ के अधिकारियों द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। नस्टा प्रत्येक वर्ष इस क्रियाकलाप को निरंतर आयोजित करता है, क्योंकि इसे शासकीय सांख्यिकी के प्रयोक्ता समुदाय हेतु अत्यंत उपयोगी पाया गया है।

अकादमी में सुविधाएं:

8.5 नस्टा प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके आवास और भोजन संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अकादमी के परिसर में तीन सुव्यवस्थित ब्लॉक नामतः शिक्षण एवं प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, तथा आवासीय ब्लॉक हैं, जो सुव्यवस्थित परिदृश्यों से घिरा हुआ है। शैक्षणिक एवं प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत एक सम्मेलन कक्ष भी है जिसमें लगभग 60 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। एक केन्द्रीकृत वातानुकूलित ऑडिटोरियम जिसका नाम महालनोबिस ऑडिटोरियम है; में लगभग 160 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है। नवीनतम कम्प्यूटरीकृत शिक्षण सहायक सामग्री से सुसज्जित चार व्याख्यान कक्ष, है। एक पुस्तकालय है जिसका नाम 'सुखात्मे पुस्तकालय' है; आईटी शिक्षण कंप्यूटर प्रयोगशाला है जो किसी भी समय प्रायोगिक प्रशिक्षण के संबंध में लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण संचालन संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त है और 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने की सुविधाएं हैं; परिसर में उपलब्ध मनोरंजक सुविधाओं में बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बैडमिंटन और बास्केटबॉल सहित इनडोर और आउटडोर खेल शामिल हैं।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी)

8.6 एनएसएसटीए को अपनी विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों के आयोजन में मार्गदर्शन के उद्देश्य से, भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित संस्थानों के कुछ विषय विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय 'प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति' (टीपीएसी) का गठन किया गया है। समिति वार्षिक आधार पर आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है, साथ ही सभी मॉड्यूल के लिए पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण पद्धति की समीक्षा करती है। इनमें से कुछ पाठ्यक्रम एनएसएसटीए में संचालित किए जाते हैं और कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों में संचालित किए जाते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली, सैद्धांतिक; अनुप्रयुक्त सांख्यिकी, बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली (एसएनए), डेटा प्रबंधन तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सूक्ष्म और स्थूल अर्थशास्त्र, अर्थमिति, उभरती प्रौद्योगिकियों के विषय आदि के क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं।

नस्टा में आयोजित प्रशिक्षण अनुसूची

8.7 एनएसएसटीए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

क. भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के अधिकारियों के लिए दो वर्षीय परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम

ख. केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों और अन्य संबंधित विभागों के सेवारात आईएसएस अधिकारियों और केंद्रीय वरिष्ठ अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मध्य-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एमसीपीटी) और डोमेन विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम (डीएसटीपी),/सेमिनार/ कार्यशालाएं।

ग. अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) के नवनियुक्त कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए तीन सप्ताह का प्रेरण प्रशिक्षण कार्यक्रम

घ. सेवारत एसएसएस अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

ड़. अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों (डीईएस)/योजना प्रभागों/मंत्रालयों/विभागों आदि के अधिकारियों के लिए मांग-आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम और राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

च. भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता और अन्य केंद्रों के एम. स्टेट. छात्रों के लिए सरकारी सांखयिकीय पद्धति पर प्रदर्शन कार्यक्रम के लिए समर्थन; और विश्वविद्यालयों के छात्रों और संकाय सदस्यों के लिए सरकारी सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रम।

8.8 विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य से, नस्टा विभिन्न प्रतिष्ठित/विशिष्ट संस्थानों जैसे आईआईएमय आईआईटीय आईआईआरएस, देहरादून एएससीआई, हैदराबाद श्रम ब्यूरो, चंडीगढ़ आईआईपीए, दिल्ली आईआईपीएस, मुंबई आईएसटीएम, दिल्ली आईजीआईडीआर, मुंबई आईएएसआरआई, दिल्ली आईएसईसी, बेंगलुरु आदि के साथ सहयोग करता है ।

8.9 राज्य सांख्यिकी कार्मिकों का प्रशिक्षणः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समय-समय पर उनकी रुचि के कुछ निर्दिष्ट विषयों और क्षेत्रों में नियमित और साथ ही मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इनके अलावा, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशिष्ट अनुरोधों के आधार पर, नस्टा में विशेष रूप से तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.10 नस्टा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), कोलकाता के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र (आईएसईसी), कोलकाता के सहयोग से सांख्यिकी सिद्धांत और अनुप्रयोग में नियमित डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

8.11 विदेश मंत्रालय, वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई), नोएडा, उत्तर प्रदेश; आईआईपीए, नई दिल्ली; आदि से प्राप्त अनुरोध के अनुसार विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय कर्मियों/प्रतिभागियों के लिए अल्पकालिक यानी एक-दो सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन दौरे भी आयोजित किए जाते हैं।

विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों/बैठका/कार्यशालाओं/सेमिनारों/सम्मेलनों में भागीदारी

8.12 भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव (एस एंड पीआई) की अध्यक्षता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की स्क्रीनिंग समिति का गठन अंतर्राष्ट्रीय बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और प्रशिक्षणों में भागीदारी के लिए नामांकन पर विचार करने के लिए किया गया है।

8.13 दिनांक 1 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2024 के दौरान, इस मंत्रालय के 87 अधिकारियों ने भौतिक मोड में 55 अंतर्राष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/सेमिनारों में भाग लिया है और 39 अधिकारियों ने वर्चुअल मोड में 17 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

स्नातकोत्तर/शोध छात्रों के लिए इंटर्नशिप की योजना

8.14 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों/संस्थानों के स्नातकोत्तर छात्रों/शोध विद्वानों के लिए इंटर्नशिप की योजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य छात्रों में भारत की सांख्यिकी प्रणाली के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस योजना के तहत मई से जुलाई के दौरान दो महीने की इंटर्नशिप की पेशकश की जाती है और इंटर्नशिप पूरी होने के बाद छात्रों को ₹10,000, का वजीफा दिया जाता है। वर्ष 2023-24 की इंटर्नशिप योजनाओं के लिए कुल 193 प्रशिक्षुओं को इंटर्नशिप के लिए चुना गया। वर्ष 2024-25 के दौरान इंटर्नशिप योजना को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कुल 282 स्लॉट की पेशकश की गई है।

शोध अध्ययनों को बढ़ावा देने तथा संगोष्ठियों/सम्मेलन/कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए संस्थाओं को अनुदान सहायता।

8.15 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वित्तीय सहायता प्रदान करके आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में शोध अध्ययनों और संगोष्ठियों को बढ़ावा देने के लिए अनुदान सहायता योजना को लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस योजना के तहत, पात्र संस्थाओं/संगठनों को आधिकारिक सांख्यिकी से संबंधित विषयों पर शोध अध्ययन/संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाओं आदि के आयोजन के लिए धनराशि प्रदान की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं में शोध-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस उद्देश्य के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार आधिकारिक सांख्यिकी में सर्वेक्षण/अध्ययन करने के लिए शोध संस्थाओं/संगठनों/गैर सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2023-24 (मार्च 2024 तक) के दौरान 10 लाख रुपये की राशि के दो प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।.

सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीयधराष्ट्रीय पुरस्कार

8.16 मंत्रालय ने प्रख्यात भारतीय सांख्यिकीविद् प्रो. पी. सी. महालनोबिस की स्मृति में सांख्यिकी में प्रो. पी. सी. महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्थापित किया है। वर्तमान में इस पुरस्कार में 10,000 अमेरिकी डॉलर का नकद पुरस्कार, एक प्रशस्ति पत्र, एक स्मृति चिन्ह और सम्मान समारोह में भाग लेने के लिए संयुक्त राष्ट्र दरों के अनुसार राउंड ट्रिप इकोनॉमी क्लॉस हवाई किराया और प्रतिदिन भत्ता दिया जाता है। यह पुरस्कार द्विवार्षिक आधार पर दिया जाता है। यह पुरस्कार सांख्यिकी में आजीवन योगदान के लिए विकासशील देश के चयनित सांख्यिकीविद् को दिया जाता है। 11वां प्रो. पी. सी. महालनोबिस अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार-2023 प्रो. अरूप बोस, भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) कोलकाता को प्रदान किया गया और यह 16-20 जुलाई, 2023 को कनाडा के ओटावा के मध्य में शॉ कॉन्फ्रेंस सेंटर में 64वें विश्व सांख्यिकी कांग्रेस के दौरान दिया गया।

ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता

8.17 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, 17 वर्ष 2005 से, प्रतिवर्ष, प्रख्यात सांख्यिकीविद् प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालया/महाविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत सांख्यिकी के स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सांख्यिकी/सरकारी सांख्यिकी से संबंधित विषयों पर अखिल भारतीय तत्काल निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन करता है। प्रतियोगिता आम तौर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों जैसे कि एनएसएसओ (एफओडी) के उप-क्षेत्रीय/क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों आदि में आयोजित की जाती है। प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रतिवर्ष 29 जून को आयोजित सांख्यिकी दिवस समारोह में सम्मानित किया जाता है। प्रतियोगिता के अंतर्गत 15,000/- रुपये का एक प्रथम पुरस्कार, 12,000/- रुपये के दो द्वितीय पुरस्कार, 10,000/- रुपये के तीन तृतीय पुरस्कार तथा 5,000/- रुपये के पांच सांत्वना पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2023 की आधिकारिक घोषणा 27 जनवरी, 2023 को की गई थी, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च, 2023 निर्धारित की गई थी। प्रतियोगिता 19 मार्च, 2023 को 30 केंद्रों पर हुई, जिसमें कुल 82 उम्मीदवारों ने भाग लिया। प्रतियोगिता के परिणाम 8 जून, 2023 को घोषित किए गए, जिसमें कुल 11 आवेदकों को ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2023 का विजेता घोषित किया गया। ऑन द स्पॉट निबंध लेखन प्रतियोगिता 2024 की आधिकारिक घोषणा दिनांक 2 फरवरी, 2024 को की गई, जिसमें आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 मार्च, 2024 निर्धारित की गई। कुल 248 आवेदन प्राप्त हुए और कुल 222 उम्मीदवार उक्त प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए पात्र पाए गए, जिसका आयोजन 7 अप्रैल, 2024 को देशभर में एनएसओ (एफओडी) के 45 क्षेत्रीय कार्यालयों/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में किया जाएगा। एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

अध्याय - 9

संगणक केंद्र

9.1 संगणक केंद्र 1967 में स्थापित किया गया था और इसका नेतृत्व अतिरिक्त महानिदेशक करते हैं। संगणक केंद्र द्वारा निष्पादित कार्य/गतिविधियां इस प्रकार हैं:

(i) मंत्रालय की वेबसाइट, डेटा कैटलॉग और सीपीआई वेब पोर्टल का डिजाइन, विकास और रखरखाव.

(ii) अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) ढांचे और एसडीएमएक्स (सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा एक्सचेंज) दिशानिर्देशों सहित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुसार मंत्रालय द्वारा तैयार की गई रिपोर्टों और सांख्यिकी का प्रसार, जैसा लागू हो और

(iii) मंत्रालय के एप्लिकेशन पोर्टल की होस्टिंग और रखरखाव के लिए एनआईसी क्लाउड सेवाओं की सुविधा प्रदान करना।

मंत्रालय की वेब साइट

9.2 एमओएसपीआई की वेबसाइट (https://www.mospi.gov.in) अपने उपयोगकर्ताओं को एक एकीकृत डिजिटल अनुभव प्रदान करती है। मंत्रालय की भूमिका, गतिविधियों, संगठनात्मक संरचना, संपर्क जानकारी आदि के बारे में जानकारी प्रदान करने के अलावा, वेबसाइट सभी सांख्यिकीय प्रकाशनों/रिपोर्टों, डेटा और एमओएसपीआई के विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड के लिए एक मंच है।

9.3 सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों की आवश्यकता को शामिल करने की दिशा में एक कदम के रूप में, एमओएसपीआई वेबसाइट में कुछ सबंधन किए गए हैं अर्थात्:

क. एनआईसी कोड खोजक का समावेश किसी भी उद्योग समूह के राष्ट्रीय उद्योग वर्गीकरण के अनुसार उपयुक्त कोड को आसानी से खोज करने की सुविधा के लिए कुछ प्रमुख शब्दों की मदद से और इसके विपरीत।

ख. एक एफओडी कार्यालय लोकेटर भी विकसित किया गया है और भारत में एमओएसपीआई क्षेत्रीय कार्यालयों के विस्तार को प्रदर्शित करने के लिए के पी आई पर रखा गया है

ग. इसके होमपेज पर प्रमुख के पी आई (मुख्य प्रदर्शन संकेतक) का प्रदर्शन

घ. एमओएसपीआई के सबसे व्यापक रूप से रिपोर्ट किए गए डेटा उत्पादों से संबंधित डेटा विजुअलाइजेशन अनुभाग को शामिल करनाय विजुअलाइजेशन अनुभाग में 1400 से अधिक डेटा विजुअलाइजेशन शामिल हैं।

डेटा प्रसार में प्रबंधन और समर्थन

9.4 संगणक केंद्र में निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान करता है:

क. विभिन्न हितधारकों को प्रसार के लिए एमओएसपीआई सर्वेक्षण इकाई स्तर के डेटा को अंतरराष्ट्रीय मानक प्रारूप यानी आईएचएसएन (अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क) में परिवर्तित करना।

ख. राष्ट्रीय डेटा संग्रह पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के माइक्रोडेटा और मेटा डेटा का ऑनलाइन डाउनलोड करना।

9.5 मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष में जारी किए गए यूनिट स्तर के अज्ञात डेटा सेटों को उपयोगकर्ताओं और शोधकर्ताओं के लिए ऑनलाइन प्रसार के लिए वेबसाइट पर डाला गया है:

- आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) का इकाई स्तर डेटा, जनवरी, 2023 दिसंबर, 2023.
- अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईआईएचएसएन) में 78 वें दौर के यूनिट स्तर के डेटा का रूपांतरण।
- अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) में एएसआई 2020-21और एएसआई 2021-22 के यूनिट स्तर के डेटा का रूपांतरण।
- अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सर्वेक्षण नेटवर्क (आईआईआईएसएन) में बहु-संकेतक सर्वेक्षण (एमआईएस) के इकाई स्तर के डेटा का रूपांतरण।

क्लाउड कम्प्यूटिंग

9.6 एनआईसी क्लाउड सेवाओं के लाभों का इस्तेमाल किया जा रहा है. और सीपीआई ग्रामीण. सीपीआई शहरी, एमपीएलएडीएस, गतिविधि डैशबोर्ड-गतिविधि प्रबंधन प्रणाली, ई संख्यिकी पोर्टल और माइक्रो डेटा पोर्टल आदि सहित मंत्रालय के विभिन्न वेब अनुप्रयोगों को एनआईसी क्लाउड पर होस्ट किया गया है। यह बुनियादी ढांचे और जनशक्ति की लागत को कम करता है और बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पोर्टल

9.7 संगणक केंद्र द्वारा विकसित सीपीआई अभिलेखीय वेब पोर्टल सहफ्टवेयर एप्लिकेशन, सीपीआई डेटा की आसान पुनर्प्रासि के लिए परिचालित है। मासिक प्रेस विज्ञप्ति के बाद, विवरण सीपीआई वेब पोर्टल पर अपलोड किए जाते हैं और उपयोगकर्ता निम्नलिखित तक पहुंच सकते हैं:

- राज्य/अखिल भारतीय समूह-उप समूह सूचकांक
- अखिल भारतीय आइटम इंडेक्स
- वार्षिक मुद्रास्फीति दर
- अखिल भारतीय मद मुद्रास्फीति दरें
- प्रकाशनार्थ विज्ञप्ति
- क्रॉस सारणीकरण रिपोर्ट
- विजुअलाइजेशन

बदलती प्रौद्योगिकी की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल को हाल ही में पूर्णतः प्रचालनात्मक डाटाबेस में अंतरित किया गया है।

सांख्यिकीय डेटा और मेटाडेटा विनिमय ैक्डग)

9.8 सांख्यिकीय आंकड़े और मेटाडाटा एक्सचेंज (एसडीएमएक्स) वर्ष 2011 (पहली तिमाही) से सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान एसडीएमएक्स फार्मेट में जारी किए जा रहे हैं। संगणक केंद्र ने डोमेन सीपीआई और एनएडी के लिए भी पहल की है वार्षिक जीडीपी अनुमानः

क. एनएडी डेटा का एसडीएमएक्स Q3 FY 2023-& 24 के लिए जीडीपी के तिमाही अनुमानों की नवीनतम विज्ञप्ति के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड किया गया है

ख. सीपीआई डेटा का एसडीएमएक्स जनवरी 2024 तक वेबसाइट पर उपलब्ध है

केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी (सीडीआर)

9.9 प्रमुख संकेतकों के प्रबंधन और प्रसार के लिए केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी (सीडीआर) का एक प्रोटोटाइप संगणक केंद्र में विकसित किया जा रहा है, जो कि एमओएसपीआई के डेटा उत्पादों का प्रबंधन और प्रसार करता है।

एक लघु डाटा सेंटर का संचालन और एमओएसपीआई की आईटी परिसंपत्तियों का रखरखाव

9.10 डाटा सेंटर के सर्वर 24x7x365 आधार पर काम कर रहे हैं। नई उभरती प्रौद्योगिकी के अनुसार मंत्रालय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आईटी उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है। संगणक केंद्र मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों की आईटी परिसंपत्तियों के रखरखाव की देखभाल करता है। संगणक केंद्र में सम्मेलन कक्ष के लिए एक नई श्रव्य दृश्य प्रणाली संस्थापित की गई है। साइबर सुरक्षा पर एमईआईटीवाई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है और वेबसाइटों और अनुप्रयोगों जैसे सुरक्षा प्रथाओं को एक वैध एसएसएल प्रमाणपत्र के साथ "https" सक्षम किया गया है, वेब अनुप्रयोगों की भेद्यता मूल्यांकन, एनआईसी द्वारा प्रदान किए गए ईडीआर सहफ्टवेयर एंटीवायरस की स्थापना, बाहरी यूएसबी स्टोरेज उपकरणों को डेटा सुरक्षा और मैक बाइंडिंग आदि को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मंत्रालय के ई-मेल खातों का अद्यतनीकरण सृजन नियमित आधार पर किया जाता है।

राष्ट्रीय स्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (एनएसडीआई)

9.11 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एनएसडीआई जून 2006 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया था। एनएसडीआई स्थानिक डेटा के अधिग्रहण, प्रसंस्करण, भंडारण, वितरण और उपयोग में सुधार के उद्देश्य से है। एनएसडीआई के भाग के रूप में सभी नोडल मंत्रालयों/संगठनों में पृथक नोड सृजित किया जाना है। एनएसडीआई नोड की स्थापना के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में संगणक केंद्र को नोडल संगठन के रूप में नामित किया गया है। अंतरिम आंकड़ा भागीदारी ढांचे (आईडीएसएफ) के संबंध में डीएसटी को आर्थिक गणना के आंकड़ों के प्रसार के बारे में मासिक रिपोर्ट उपलब्ध कराई गई है।

एमओएसपीआई की आईं टी पहलों के संचालन पर अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी)

9.12 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त इनपुट के आधार पर, एमओएसपीआई ने भारत में डेटासेट और रजिस्ट्रियों का संग्रह, 2023 का अगला संस्करण जारी किया है। प्रकाशन का एक बीटा संस्करण पहले 2022 में लाया गया था। संग्रह के नवीनतम संस्करण में 38 मंत्रालय/विभागों से प्राप्त 236 डेटासेट रजिस्ट्रियां (बीटा संस्करण में 70 डेटासेट रजिस्ट्रियों से वृद्धि) शामिल हैं।

9.13 इस सार-संग्रह में मंत्रालयों/विभागों सहित विभिन्न संगठनों के डेटासेट रजिस्ट्रियों से संबंधित अद्यतन नए जोडे गए मेटाडेटा विवरण शामिल हैं। इसमें विभिन्न डेटासेटों/संकेतकों/रजिस्ट्रियों के मेटाडेटा विवरण शामिल हैं, जैसे डेटा संग्रह और संकलन की पद्धतियां, संकलन रिलीज की आवधिकता, डेटा साझाकरण नीति, डेटा के संग्रह के लिए अधिनियम कानूनी प्रावधान, प्रसार के तरीके और प्रारूप, प्रसार में समय अंतराल, एकत्रीकरण के स्तर (राज्यवार/लिंग-वार/ग्रामीण-शहरी, आदि) के साथ-साथ वेब-लिंक जहां स्रोत मंत्रालय/विभाग द्वारा डाउनलोड प्रसार के लिए डेटा उपलब्ध है।

आई टी समर्थित गतिविधियाँ

9.14 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के लिए आईटी से संबंधित कार्यकलाप के लिए नोडल कार्यालय होने के नाते संगणक केंद्र ने मंत्रालय के अन्य कार्यालयों प्रभागों की आईटी से संबंधित परियोजनाओं के लिए परामर्श देने का कार्य शुरू किया है। संगणक केंद्र ने इस उद्देश्य के लिए एमओएसपीआई के एफओडी के डीपीडी, पीएसडी, कृषि सांख्यिकी विंग को प्रौद्योगिकी पर सक्रिय रूप से सलाह प्रदान की है। इसने मंत्रालय के आईटी परियोजना कार्यान्वयन में बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। संगणक केंद्र ने आईएसएस परिवीक्षाधीन के लिए आईटी पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए अच्छी तरह से योग्य और अनुभवी संकायों के साथ एनएसएसटीए का समर्थन किया। प्रभाग ने प्रशिक्षण प्रभाग, एमओएसपीआई द्वारा प्रायोजित ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप योजना के तहत सांख्यिकी और संबद्ध विषयों में स्नातकोत्तर अनुसंधान करने वाले छात्रों को इंटर्नशिप प्रदान की है।

केंद्रीय डेटा रिपोजिटरी (सीडीआर)

9.15 संगणक केंद्र के अधिकारियों ने क्षमता निर्माण आयोग, डीओपीटी के 'उभरती प्रौद्योगिकियों का परिचय' पर 'बिग डेटा और ई-लर्निंग सर्टिफिकेट कोर्स का परिचय' पर यूएन बिग डेटा ऑनलाइन कोर्स पूरा कर लिया है। डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई।

गतिविधि डैशबोर्ड

9.16 एमओएसपीआई के विभिन्न प्रभागों द्वारा उपयोग के लिए गतिविधि डैशबोर्ड भी विकसित किया गया है ताकि विभिन्न गतिविधियों की समय पर प्रगति को ट्रैक किया जा सके ।

ई संखियिकी पोर्टल

9.17 संगणक केंद्र ने आधिकारिक सांख्यिकीय डेटासेट के आसान प्रबंधन, पहुंच और प्रसार के लिए ई संखियिकी पोर्टल (https://esankhyiki.mospi.gov.in/) के विकास की शुरुआत की है। डेटा कैटलॉग अनुभाग, जो उपयुक्त मेटाडेटा, चार्ट के साथ-साथ डाउनलोड करने योग्य तालिकाओं के साथ मंत्रालय के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डेटासेट तक पहुंच प्रदान करता है. फरवरी, 2024 में लॉन्च किया गया है। एमओएसपीआई के प्रमुख डेटा उत्पादों के लिए 2053 से अधिक टेबल उपलब्ध कराए गए हैं और प्रत्येक टेबल के लिए विजुअलाइजेशन बनाए गए हैं

संगणक केंद्र द्वारा राजभाषा के प्रगतिशील उपयोग का कार्यान्वयन

9.18 संगणक केंद्र ने एमओएसपीआई में आधिकारिक भाषा के प्रगतिशील उपयोग को बढ़ाने के लिए उपाय किए हैं। सितंबर 2023 में कार्यालय में हिंदी पखवाड़ा मनाया गया और विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। हिंदी में मूल कार्य के लिए राजभाषा विभाग की प्रोत्साहन योजना जारी रखी गई। मंत्रालय की वेबसाइट को आंशिक रूप से द्विभाषी बनाया गया है।

अध्याय - 10

नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग (पीआईएमडी)

10.1 18 जनवरी 2021 से एनएसओ में पीआईएमडी की स्थापना की गई है, जिसका व्यापक अधिदेश इस प्रकार है

(i) एनएसओ मंत्रालयों के कार्यात्मक प्रभागों के माध्यम से आधिकारिक सांख्यिकी पर प्रस्तावित राष्ट्रीय नीति के विभिन्न घटकों के कार्यान्वयन को संचालित करना और उसकी देखरेख करना, जहाँ भी लागू हो।

(ii) एक शासन संरचना, यानी नीतियाँ, निर्देश, दिशा-निर्देश, अभ्यास और उपकरण स्थापित करना जो प्रशासनिक डेटा के अधिग्रहण, प्रबंधन और कुशल उपयोग का समर्थन करेंगे।

iii) अन्य विभागों/मंत्रालयों (सांख्यिकीय सलाहकारों के माध्यम से) के साथ समन्वय करना ताकि उन संगठनों द्वारा रखे गए प्रशासनिक रिकॉर्ड की सांख्यिकीय क्षमता की जाँच की जा सके ताकि प्रशासनिक प्रणाली में सांख्यिकीय आवश्यकताओं के निर्माण में मदद मिल सके फिर उनके प्रशासनिक रिकॉर्ड सिस्टम का निर्माण या पुनर्विकास किया जा सके।

(iv) सभी मंत्रालयों/विभागों के पास उपलब्ध प्रशासनिक डेटासेट के बारे में मेटा डेटा सहित सूचना के भंडार के निर्माण की सुविधा प्रदान करना।

10.2 पीआईएमडी ने तैयार और प्रकाशित किया है

- सरकारी सांख्यिकीय प्रणाली के एक भाग के रूप में प्रशासनिक डेटा का उपयोग करते हुए "प्रशासनिक डेटा: मुद्दे, चिंताएं और संभावनाएं" पर एक पेपर:
- डेटा प्रसार : सांख्यिकीय उत्पादों के लिए राष्ट्रीय मेटा डेटा संरचना (एनएमडीएस)पर एक दस्तावेज। यह डेटा उत्पादकों के लिए डेटा की गुणवत्ता स्थापित करने और बनाए रखने और डेटा साझा करने में आसानी बढ़ाने के लिए एक बुनियादी न्यूनतम गुणवत्ता मानक का पालन करने के लिए दिशानिर्देशों का एक सेट है। एनएमडीएस को अपनाने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच प्रसारित किया गया है।

10.3 पीआईएमडी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) में एक नोडल प्रभाग के रूप में कार्य करता है, जो आवश्यक इनपुट प्रदान करता है और राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (नीति आयोग) द्वारा डेटा गवर्नेंस गुणवत्ता सूचकांक (डीजीक्यूआई) के संकलन से संबंधित गतिविधियों का समन्वय करता है। मंत्रालय के लिए डीजीक्यूआई स्कोर वर्ष 2020-21 के दौरान 2.51 से बढ़कर वर्ष 2022-23 के दौरान 4.27 हो गया है।

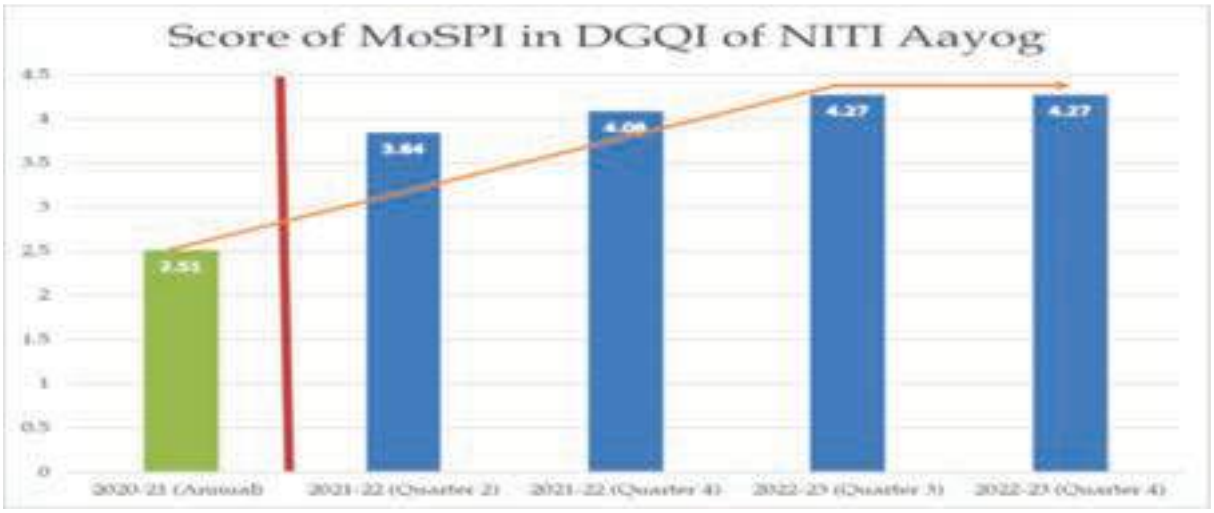

10.4 भारत सरकार ने नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के लिए विभिन्न अधिनियमों को अपराधमुक्त करने का कार्य अपने हाथ में लिया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय सांख्यिकी संग्रह (सीओएस) अधिनियम, 2008 का प्रशासन करता है और पीआईएमडी सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में नोडल प्रभाग है, जो डीपीआईआईटी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के साथ बातचीत करता है, जो इस विषय पर भारत सरकार का नोडल मंत्रालय है।

10.5 भारत सरकार ने 30 वैश्विक सूचकांकों की निगरानी शुरू कर दी है, जो विकास के विभिन्न पहलुओं पर विभिन्न देशों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें रैंक करते हैं। पीआईएमडी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में नोडल प्रभाग है, जो लगभग दस वैश्विक सूचकांकों के संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर लागू विभिन्न संकेतकों के लिए भारत सरकार के नोडल मंत्रालय/विभाग के साथ समन्वय करता है।

10.6 स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत, नागरिकों के बीच साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने और नागरिक-केंद्रित आधारी संरचना बनाने के लिए, पीआईएमडी ने 12 जुलाई, 2023 को एक जागरूकता कार्यक्रम और अभियान की सावधानीपूर्वक योजना बनाई और उसका आयोजन किया। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के मंदिर मार्ग स्थित दयानंद मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुआ। पीआईएमडी के अधिकारियों ने स्कूल परिसर में नए वृक्षारोपण किए और पीआईएमडी के अधिकारियों ने स्कूल में एक नवनिर्मित शौचालय का उद्घाटन किया।

अध्याय - 11

संयुक्त राष्ट्र में भारत

1.1 सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में भारत की विशेषज्ञता ने इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) में स्थान दिलाया है। वर्ष 1946 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग वैश्विक सांख्यिकीय प्रणाली का सर्वोच्च निकाय है जो दुनिया भर के सदस्य देशों के मुख्य सांख्यिकीविदों को एक साथ लाता है। यह अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है, जो सांख्यिकीय मानको को निर्धारित करने और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनके कार्यान्वयन सहित अवधारणाओं और विधियों के विकास के लिए जिम्मेदार है।

11.2 वर्ष 2024-2027 की अवधि के लिए यूएनएससी की सदस्यता हेतु भारत की उम्मीदवारी के समर्थन जुटाने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन (पीएमआई-यूएन) द्वारा संयुक्त प्रयास किए गए। पीएमआई-यूएन और सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के सम्मिलित प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत को 2024-2027 की अवधि के लिए यूएनएससी के सदस्य के रूप में चुना गया। भारत को लगभग 2 दशकों के बाद यूएनएससी के सदस्य के रूप में चुना गया है, जो भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के लिए एक उपलब्धि है।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का 55वां सत्र

11.3 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग का 55वां सत्र दिनांक 27 फरवरी 2024 से 01 मार्च 2024 तक न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के नेतृत्व में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधिमंडल ने सत्र में भाग लिया।

11.4 भारत ने आधिकारिक मौखिक वक्तव्य दिए जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों के परामर्श से विभिन्न एजेंडा मदों पर तैयार किए गए थे, जिनमें आधिकारिक सांख्यिकी के मौलिक सिद्धांत, राष्ट्रीय लेखे, जलवायु परिवर्तन के आंकड़े, सांख्यिकीय आयोग की कार्य पद्धतियां, पर्यावरण-आर्थिक लेखांकन और सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के लिए आंकड़े और संकेतक शामिल थे।

एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) सांख्यिकी समिति (सीएसटी) के ब्यूरो के उपाध्यक्ष

11.5 एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सबसे समावेशी अंतर-सरकारी मंच है। आयोग सतत विकास चुनौतियों के समाधान की खोज में अपने 53 सदस्य देशों और 9 सहयोगी सदस्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देता है। ईएससीएपी संयुक्त राष्ट्र के पाँच क्षेत्रीय आयोगों में से एक है।

11.6 सांख्यिकी पर ईएससीएपी समिति एशियाई और प्रशांत क्षेत्र में सांख्यिकी पर निर्णय लेने के लिए उच्चतम स्तर का अंतर-सरकारी मंच है। समिति में ईएससीएपी सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों के नेताओं, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है।

11.7 अगस्त 2022 में आयोजित सीएसटी के 8वें सत्र के दौरान भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी सांख्यिकी समिति (सीएसटी) के ब्यूरो के तीन उपाध्यक्षों में से एक के रूप में चुना गया।

एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकी संस्थान (एसआईएपी) की शासी परिषद् (जीसी) के सदस्य

11.8 एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी संस्थान (एसआईएपी) सरकारी अधिकारियों और आधिकारिक सांख्यिकी पर काम करने वाले अन्य लोगों के लिए एक पेशेवर सांख्यिकी प्रशिक्षण केंद्र है। एसआईएपी राष्ट्रीय सरकारों के कर्मचारियों के ज्ञान को मजबूत करने और उनके कौशल का निर्माण करने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक विशेष प्रशिक्षण प्रदान करता है, ताकि वे विश्वसनीय सांख्यिकी का उत्पादन, उपयोग और साझा कर सकें, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी और तथ्य-आधारित नीति का विकास शामिल है। एसआईएपी एशिया और प्रशांत के लिए आर्थिक और सामाजिक आयोग (ईएससीएपी) की एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण शाखा है।

11.9 इसकी संविधि के अनुसार, संस्थान की एक शासी परिषद् है जिसमें जापान सरकार द्वारा नामित एक प्रतिनिधि और अन्य सदस्यों द्वारा नामित आठ प्रतिनिधि तथा आयोग द्वारा चुने गए ईएससीएपी के सहयोगी सदस्य शामिल हैं.

11.10 मई 2022 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र ईएससीएपी के 78वें सत्र के दौरान भारत को 2022 से 2024 की अवधि के लिए एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकी संस्थान (एसआईएपी) की शासी परिषद् (जीसी) के लिए फिर से चुना गया था।

अध्याय - 12

सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

12.1 भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, एवं प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था।

12.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिससे वे वास्तविक, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें (क) नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सहित); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें।

12.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है। मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है। तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं।

12.4 इस सेवा की भर्ती संघ लोकसेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नति तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है। गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है। आरंभिक गठन और वर्तमान में विभिन्न ग्रेडों में पदों का आबंटन तालिका में दिया गया है:

ग्रेड	**संस्वीकृत पद**	**दिनांक 31-03-2024 के अनुसार संवर्ग संख्या बल**	
		तैनात	रिक्ति
उच्च प्रशासनिक ग्रेड प्लस (एचएजी+)	05	05	00
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	18	14	04
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	136	127	09
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) और एनएफएसजी	176#	143	35
वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	179	172	15
कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	300*	213	62
कुल	**814**	**674**	**125**

#इनमें से, 30: सीनियर ड्यूटी के पद एनएफएसजी में संचालित हैं।
*स्वीकृत पदों में 50 आरक्षित पद शामिल है।

12.1 भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, एवं प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था।

12.5 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी। दिनांक 31/03/2024 तक, सीधी भर्ती के 45 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है।

12.6 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है। इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है। अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा

12.7 सरकार द्वारा निर्णय लेने को सुसाध्य बनाने, नीतियां तैयार करने और आयोजना बनाने के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय डेटाबेस तैयार करने में सहायता करने के लिए सांख्यिकी के मुख्य विनियमों के साथ अर्हक कर्मिकों के संवर्ग के रूप में दिनांक 12 फरवरी, 2002 को अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन किया गया था।

12.8 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों का समूह-ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकीय सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है। इसमें वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (एसएसओ) समूह-ख राजपत्रित तथा कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी (जेएसओ) (ग्रुप ख अराजपत्रित) शामिल हैं। 7 वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी का वेतनमान क्रमशः पे मैट्रिक्स के लेवल-7 और कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी का लेवल-6 है। एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं।

12.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है। मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है। तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देख-रेख की जाती है।

12.10 एसएसएस नियम, 2021 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों पे मेट्रिक्स नेवल-4 और लेवल-5 के सांख्यिकीय कार्यकारी पद से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। सेवा में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी पद हेतु पदोन्नतियां विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर चयन होने के आधार पर की जाती है। अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के भर्ती नियमावली के अनुसार, सेवा में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी के स्तर पर कोई सीधी भर्ती नहीं है।

12.11 दिनांक 31-3-24 की स्थिति के अनुसार अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा अधिकारियों संख्या वर्तमान में नीचे दी गई है:

क्रम सं.	**पदनाम**	**वर्तमान संख्या**
1.	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1936
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1555
कुल सं.		**3491**

वर्ष 2023-24 के दौरान

- वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग की स्वीकृति से 300 नए पद एसएसओ के 100 पद और जेएसओ के 200 पद सृजित किए गए हैं, जिससे एसएसएस की कुल स्वीकृत संख्या 4385 एसएसओ 1983 और जेएसओएस 2402, हो गई है।

- विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की सिफारिशों को स्वीकार करने के परिणामस्वरूप, 312 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों (जेएसओ) को रिक्ति कैलेंडर वर्ष 2023 के प्रति वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों (एसएसओ) के पद पर पदोन्नत किया गया है।
- वर्ष 2023 के दौरान कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएलई 2020, 2021, 2022, 2023) के माध्यम से जेएसओ के रूप में भर्ती किए गए 598 उम्मीदवारों के संबंध में नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
- वर्ष के दौरान, एसएसएस के लगभग 113 अधिकारियों को उनकी पात्रता के अनुसार संबंधित स्तर 7, 8 और 9 में प्रथम, द्वितीय और तृतीय एमएसीपी प्रदान किया गया है।
- परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, 76 जूनियर सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवाओं की पुष्टि की गई है।
- एसएसएस संवर्ग के नवनियुक्त 423 जेएसओ के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम (आईटीपी) राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए), ग्रेटर नोएडा के माध्यम से आयोजित किया गया है।
- एसएसएस प्रभाग ने वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों सहित लगभग 225 एसएसएस अधिकारियों की बड़ी भागीदारी के साथ आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली द्वारा सामना किए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने के लिए एसएसएस अधिकारियों के लिए दो दिवसीय चिंतन शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन किया।
- स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो (एसपीएआरओ) पर एसएसएस अधिकारियों के लिए एपीएआर की ऑनलाइन रिपोर्टिंग की प्रक्रिया लागू की गई है और यह पूरी तरह से कार्यात्मक है।

अध्याय - 13

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण उप-योजना के लिए समर्थन

13.1 सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) एक चालू केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय आधिकारिक आंकड़ों के संग्रह, संकलन और प्रसार के लिए राज्य सांख्यिकी प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना है। यह उप-योजना राज्य निदेशालयों/अर्थशास्त्र और सांख्यिकी ब्यूरो (डीईएस) के माध्यम से भारत सरकार और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हस्ताक्षरित राज्य के विशिष्ट समझौता ज्ञापनों में विस्तृत अनुमोदित गतिविधियों/लक्ष्यों/उत्पादनों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है।

13.2 एसएसएस उप-योजना को मार्च 2010 में आर्थिक मामलों की मंत्रि मंडलीय समिति (सीसीईए) द्वारा "भारत सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण परियोजना" के रूप में अनुमोदित किया गया था, जो उस समय राज्य सांख्यिकी प्रणाली की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना थी। बाद में इस परियोजना का नाम बदलकर "सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण के लिए समर्थन" (एसएसएस) कर दिया गया। 2014-15 के बजट के बाद, एसएसएस योजना को मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना 'क्षमता विकास' के अंतर्गत केंद्र से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र उप-योजना बना दिया गया।

योजना कार्यान्वयन

13.3 दिनांक 31 मार्च 2024 तक, 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उप-योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है, जिनमें से 11 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वयन पूरा हो चुका है। एसएसएस उप-योजना ने कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालयों/ब्यूरो और उनके संबंधित विभागों की दक्षता बढ़ाने में निम्नलिखित क्षेत्रों में सुधार करने में योगदान दिया है:

- सूचना प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ बनाना तथा आंकड़ों/सूचनाओं के ऑनलाइन संग्रह और प्रसार के लिए वेब-आधारित सॉफ्टवेयर पोर्टल/एप्लीकेशन का विकास/निर्माण;
- राज्यों और उप-राज्यों के स्तर पर नीति नियोजन के लिए राज्य घरेलू उत्पाद (एसडीपी), जिला घरेलू उत्पाद (डीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपी), थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) आदि जैसे प्रमुख आर्थिक संकेतकों का संकलन और रिलीज;
- सांख्यिकीय विधियों/कंप्यूटर कौशल और सांख्यिकीय अनुप्रयोगों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्मिकों की क्षमता निर्माण।

डीईएसएम एंड ई मुख्यालय भवन, सिक्किम

राज्य सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (एसएएसए) भवन, केरल

- सांख्यिकी के महत्व और सांख्यिकी सर्वेक्षण अध्ययनों में भागीदारी के बारे में उत्तरदाताओं, उपयोगकर्ताओं, उत्पादकों आदि के बीच जागरूकता पैदा करना, वकालत गतिविधियाँ करना, उपयोगकर्ता उत्पादक संवाद आयोजित करना आदि।

- आंध्र प्रदेश (तिरुपति में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र), गुजरात (डीईएस मुख्यालय भवन, सहभागी शिक्षण केंद्र), झारखंड (डीईएस मुख्यालय भवन), कर्नाटक (बेंगलुरु, हसन, चिकमगलूर, रायचूर में जिला सांख्यिकी कार्यालय भवन), केरल (राज्य अकादमी) में डीईएस का मुख्यालय भवन, सिक्किम राज्य सांख्यिकी प्रशासन अकादमी (एसएएसए) भवन, केरल सांख्यिकी प्रशासन), मणिपुर (प्रशासनिक ब्लॉक, डीईएस का सभागार), मिजोरम (डीईएस मुख्यालय भवन), ओडिशा (314 ब्लॉक में ब्लॉक सांख्यिकी कार्यालय), राजस्थान (17 जिला सांख्यिकी कार्यालय, डीईएस में प्रशिक्षण हॉल), सिक्किम (डीईएस मुख्यालय भवन, 2 जिला सांख्यिकी कार्यालय भवन) मंगन और ग्यालशिंग में सांख्यिकी कार्यालय भवन), उत्तर प्रदेश (कानपुर और बस्ती में डिवीजन कार्यालय भवन), तमिलनाडु (डीईएस मुख्यालय भवन), तेलंगाना (तेलंगाना राज्य सांख्यिकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान) और पश्चिम बंगाल (11 जिलों में जिला सांख्यिकी कार्यालय) इत्यादि राज्यों में राज्य निदेशालयों/अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी ब्यूरो (डीईएस) के भवनों और प्रशिक्षण सुविधाओं जैसे भौतिक आधारी संरचना का सृजन।

13.4 वर्ष 2023-24 के दौरान योजना के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियाँ/महत्वपूर्ण विकास इस प्रकार हैं:

(क) केंद्रीय उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की दो बैठकें सीएसआई सह सचिव, एमओएसपीआई की अध्यक्षता में 03 अगस्त 2023 और 01 सितंबर 2023 को बुलाई गईं जिसमें तीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों नामतः दादरा नागर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा और लक्षद्वीप की गतिविधियों वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई थी ।

(ख) एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत प्रमुख उपलब्धियों पर एक पुस्तिका फरवरी 2023 में प्रकाशित की गई थी जिसमें दिसंबर 2022 तक की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया था।

(ग) 01 दिसंबर 2022 से 31 मार्च 2024 की अवधि के दौरान, एडीजी (आईआईआईसीयू और एसएसपीयू)/डीडीजी (एसएसपीयू) की अध्यक्षता में असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पुडुचेरी, त्रिपुरा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ इन राज्यों में एसएसएस उप-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने और डीईएस द्वारा सामना किए जाने वाले कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा और समाधान करने के लिए 12 संयुक्त समीक्षा बैठकों (जेआरएम) का आयोजन किया गया ।

असम और नागालैंड राज्यों के साथ संयुक्त समीझा बैठकें (जेआरएम)

13.5 दिनांक 15 मार्च, 2024 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के महानिदेशक (सीएंडए) की अध्यक्षता में गुवाहाटी, असम में एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के पांच राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा) में एसएसएस उप-योजना के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा की गई। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की टीम ने 16 मार्च, 2024 को एसएसएस उप-योजना के अंतर्गत असम और मेघालय राज्यों द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण संबंधी कार्यों की देखरेख के लिए क्षेत्र का दौरा भी किया।

गुवाहाटी, असम में 5 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संयुक्त समीक्षा बैठक

तीन नए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र कार्यक्रमों के अनुमोदन के लिए एसएसएस उप-योजना की उच-स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की बैठक आयोजित की गई

अध्याय - 14

राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

14.1 संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने प्रभागों/अनुभागों तथा सभी संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रुप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास कर रहा है। मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 में यथा निर्धारित सांविधिक उपबंधों एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए उत्तरदायी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में विभिन्न चेक पॉइंट विकसित किए गए हैं।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी)

14.2 संयुक्त सचिव (प्रशासन), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा करती है। मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही और वार्षिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को प्रेषित की जाती हैं। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गई थी ।

राजभाषा निरीक्षण

14.3 राजभाषा अनुभाग के अधिकारी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति के साथ-साथ राजभाषा नीति का जायजा लेने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करते हैं और उसी में सुधार लाने के लिए उपचारात्मक उपाय करने पर आवश्यक निर्देश देते हैं।मंत्रालय के एफओडी मुख्यालय एससीडी, एसएसएसटीए सहित सभी अनुभाग/प्रभागों का निरीक्षण इस वर्ष के दौरान किया गया। इसके अतिरिक्त मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण इस वर्ष के दौरान किया गया: जेडओ आगरा, जेडओ दिल्ली, डीपीडी दिल्ली, डीआईआईडी दिल्ली, एसआरओ भागलपुर, आरओ पटना, आरओ नागपुर, आरओ श्रीनगर, एसआरओ अंनतनाग, आरओ हैदराबाद, एसआरओ कटक, आरओ जम्मू, एसआरओ उधमपुर, आरओ पंजिम ।

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

14.4 कार्यालयी काम काज में हिन्दी प्रयोग करने हेतु मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 14-28 सितंबर, 2023 को "हिन्दी पखवाड़ा" के रूप में मनाया गया। माननीय गृह मंत्री और कैबिनेट सचिव के संदेश ई-ऑफिस पोर्टल पर प्रसारित और प्रदर्शित किए गए। इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव द्वारा एक अपील जारी की गई थी। मंत्रालय के विभिन्न भवनों में हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्यांशों को दर्शाने वाले बैनर भी प्रदर्शित किए गए थे। पखवाड़ा के दौरान, मंत्रालय के हिंदी अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और कई अधिकारियों और पदाधिकारियों ने इन प्रतियोगिताओं में सक्रिय रूप से भाग लिया। मंत्रालय के कुल 32 विजेता प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में सांख्यिकी और कार्य. कार्या. मंत्रालय के सचिव द्वारा दिनांक 1 नवंबर, 2023 को हिन्दी पखवाड़ा समारोह 2023 में नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

संसदीय राजभाषा समिति

14.5 इस वर्ष के दौरान संसदीय राजभाषा की तीसरी उप समिति द्वारा मंत्रालय के विभिन्न अधीनस्थ और संलग्न कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया। श्री तनवीर कमर मोहम्मद, संयुक्त सचिव (प्रशा.), श्री आशीष कुमार गुप्ता, निदेशक (विभागाध्यक्ष) ने श्री संजय सिंह, उप निदेशक (राजभाषा) और श्री राकेश, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी के साथ इस बैठक में हिस्सा लिया।

14.6 संसदीय राजभाषा की तीसरी उप-समिति द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग) के निम्नलिखित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया:

1.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोची	04.01.2023
2.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोटयम	06.01.2023
3.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, इंदौर	19.01.2023
4.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, जलंधर	18.04.2023
5.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला	20.04.2023
6.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, बिलासपुर	24.05.2023
7.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर	24.05.2023
8.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कानपुर	15.06.2023
9.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ	15.06.2023
10.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना	13.02.2023
11.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, रांची	13.07.2023
12.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, थाने	13.09.2023
13.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, उप क्षेत्रीय कार्यालय, कोटा	05.10.2023
14.	राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आंचलिक कार्यालय, जयपुर	05.10.2023
15.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राजकोट	09.01.2024
16.	डाटा प्रोसेसिंग केंद्र, अहमदाबाद	10.01.2024
17.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, गोवा	15.02.2024
18.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली	12.03.2024

'हिन्दी सलाहकार समिति' की बैठक का आयोजन

14.7 श्री राव इंद्रजीत सिंह, माननीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में मंत्रालय के 'हिंदी सलाहकार समिति' की दूसरी बैठक का आयोजन दिनांक 21 जुलाई, 2023 को सम्मेलन कक्ष संख्या 201, खुर्शीद लाल भवन, नई दिल्ली में किया गया। दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 के पुनर्गठन के बाद यह मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की दूसरी बैठक है। बैठक की शुरुआत माननीय मंत्री और 'हिंदी सलाहकार समिति' के अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्जवलन से हुई। माननीय मंत्री ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से सुझाव लिया ताकि सरकारी कार्यालय में हिंदी में आसानी से काम किया जा सके।

14.8 समिति के सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए माननीय मंत्री श्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि दिनांक 12 अक्टूबर, 2021 को पुनर्गठन के बाद मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की यह पहली बैठक है। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों से सुझाव मांगे, ताकि सरकारी कार्यालय में हिन्दी में कार्य आसानी से हो सके। सदस्य सचिव एवं संयुक्त सचिव ने यह जानकारी दी कि मंत्रालय में प्रयुक्त सभी नियमावली, कोड द्विभाषी हैं और मंत्रालय की वेबसाइट भी द्विभाषी रूप में उपलब्ध है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समिति की अपेक्षाओं के अनुसार, आगामी वर्षों में, केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति के सफल एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित लक्ष्यों को हिंदी भाषा के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे।

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी)

14.9 मंत्रालय ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के द्वारा दिनांक 18-10-2023 को सचिव की अध्यक्षता में आयोजित की गई केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सीओएलआईसी) की बैठक का प्रतिनिधित्व भी किया और संयुक्त सचिव (प्रशासन) ने उप-निदेशक (राजभाषा) के साथ बैठक में हिस्सा लिया। समिति द्वारा इंगित की गई सभी त्रुटियों के संबंध में ध्यान दिया गया ।

अध्याय - 15

अन्य कार्यकलाप

15.1 मंत्रालय का सतर्कता अनुभाग, संयुक्त सचिव/उप महानिदेशक और मुख्य सतर्कता अधिकारी प्रभागीय प्रमुख के रूप में निम्नलिखित कार्यों को संभालते हैं:

- ग्रुप 'क','ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामले जैसे, भ्रष्टाचार के मामले, कदाचार और ईमानदारी की कमी;
- विविध उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के संबंध में सतर्कता निकासी पर काम करना/जारी करना;
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1964 का कार्यान्वयन;
- प्रोबिटी पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को सतर्कता मामलों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

15.2 सतर्कता प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यकलापों का भी संचालन करता है:-

- प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे सुव्यवस्थित बनाना जिसमें भ्रष्टाचार या कदाचार से निपटने के प्रावधान शामिल हों और भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए अन्य उपाय खोजना एवं मंत्रालय तथा इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को दण्डित करना; संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति ।
- संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति।

15.3 व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों यथा सीबीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है। आरंभिक जांच-पड़ताल शिकायतों के गुण-दोष का पता लगाने के लिए की जाती है और यदि शिकायतों का कोई आधार पाया जाता है तो उन पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है।

15.4 वर्ष 2023-24 के दौरान, तार्किक निष्कर्ष के बाद 89 शिकायतें बंद कर दी गई थी (जिसमें पिछले वर्ष की शिकायतें शामिल हैं)।

15.5 कथित अवधि के दौरान कोई छोटी-बड़ी शास्ति नहीं लगाई गई है।

15.6 वर्ष 2023-24 के दौरान, 2500 से अधिक सतर्कता अनापत्ति संसाधित/जारी किए गए, जिसका अंततः आईएसएस अधिकारियों की सामयिक पदोन्नति/एनएफयू/स्थायीकरण/ प्रतिनियुक्ति/जेएस नामिकायन आदि में परिणाम निकला।

15.7 30 अक्टूबर से 5 नवंबर, 2023 की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया। यह शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ। इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय "भ्रष्टाचार को न कहे; राष्ट्र के लिए प्रतिबद्ध रहे" था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने से संबंधित बैनर मंत्रालय में प्रमुख जगहों पर लगाए गए। अतिथि संकाय के माध्यम से मंत्रालय के ग्रुप ए और बी अधिकारियों के लिए 05 जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था।

15.8 जून, 2023 में सीवीसी के अनुमोदन से अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी को आईएसआई, कोलकाता में नियुक्त किया गया है।

लोक शिकायत निवारण

15.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का जनसाधारण से संपर्क नगण्य है। तथापि, इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी (लोक शिकायत) के पर्यवेक्षण में एक शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है। शिकायतें मंत्रालय के जन शिकायत पोर्टल या विभिन्न नोडल एजेंसियों जैसे कि प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ), प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) आदि से प्राप्त होती हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के पीजी पोर्टल की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा नियमित तौर पर निगरानी की जाती है। 01 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार, 36 शिकायतें लंबित थीं। 1 दिसंबर, 2022 से लेकर 31 मार्च 2024 तक की अवधि के दौरान कुल 639 शिकायतें प्राप्त की गईं और 659 शिकायतों का निपटान किया गया। सभी लोक शिकायत मामलो की निगरानी की जा रही है और इन लोक शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए प्राथमिकता के आधार पर संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों प्रभागों को नियमित रुप से अनुस्मासक दिया जाता है।

सूचना का अधिकार संबंधी मामले

15.10 सूचना का अधिकार संबंधी आवेदन/पहली अपील सामान्यतः पीआईजीआर अनुभाग में प्राप्त किए जाते हैं और तब इन्हें निपटान हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों(सीपीआईओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को भेजा जाता है। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उपसचिव/निदेशक स्तर के 37 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक आरटीआई नोडल अधिकारी को नामित किया है। मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के लिए मंत्रालय ने 82 सीपीआईओ को भी नामित किया। इसके अतिरिक्त इस मंत्रालय के नियंत्राणाधीन भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई), एक स्वायत्त निकाय के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक सीपीआईओ को नामित किया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 1 दिसंबर, 2022 से 31 मार्च 2024 तक 16 माह की अवधि में प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की संख्या इस प्रकार हैः

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत 1 दिसम्बर 2022 से 31 मार्च 2024 तक 16 माह की अवधि के दौरान प्राप्त अनुरोध/अपील की संख्या

क्रम सं.	माह का नाम	अनुरोध/आवेदन				अपील			
		सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित
1	दिसम्बर-22	102	131	136	97	9	16	7	18
2	जनवरी-23	97	195	192	100	18	10	18	10
3	फरवरी-23	100	135	141	94	10	11	13	8
4	मार्च-23	94	183	165	112	8	10	7	11
5	अप्रैल-23	112	112	127	97	11	12	9	14
6	मई-23	97	158	161	94	14	8	13	9
7	जून-23	94	175	151	118	9	10	9	10
8	जुलाई-23	118	132	128	122	10	11	6	15
9	अगस्त-23	122	185	142	165	15	20	12	23
10	सितम्बर-23	165	156	178	143	23	9	18	14

क्रम सं.	माह का नाम	अनुरोध/आवेदन				अपील			
		सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित
11	अक्टूबर-23	143	129	172	100	14	15	12	17
12	नवम्बर-23	100	175	148	127	17	17	14	20
13	दिसम्बर-24	127	148	142	133	20	10	14	16
14	जनवरी-24	133	159	178	114	16	12	11	17
15	फरवरी-24	114	260	242	132	17	17	21	13
16	मार्च-24	132	303	268	167	13	19	16	16
	कुल	**102***	**2736**	**2671**	**167***	***9***	**207**	**200**	**16****

सीएफः पिछले माह के लंबित कार्यों को अग्रेषित करना (कैरी फारवार्ड)
प्राप्तः माह के दौरान प्राप्त
निपटानः माह के दौरान निपटाए गए
*: 01 दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार लंबित कार्यों को अग्रेषित करना।
**: 31 मार्च, 2024 को लंबित

सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण

15.11 सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के मुख्य केंद्रित क्षेत्र हैं जिसका उद्देश्य एक अधिक समतामूलक समाज का सृजन करना है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को मूल अधिकार, अवसर और संसाधन मिलने चाहिए । यह मंत्रालय अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों सहित सामाजिक और आर्थिक अधिकारहीन समुदायों का कल्याण, विकास और सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए, उप सचिव रैंक के एक अधिकारी को एससी, एसटी और पीडब्लूबीडी के लिए सम्पर्क अधिकारी के रूप में नियुक्त भी किया गया है, ताकि कोई पक्षपात न किया जा सके और स्वस्थ तथा समावेशी कार्य वातावरण बनाए रखा जा सके।

मंत्रालय में एक शिकायत निवारण प्रकोष्ठ भी है जो प्राथमिकता आधार पर एससी/एसटी और पीडब्लयूडी से संबंधित उच्च स्तरीय शिकायतों/आरोपों पर विचार करता है और तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए प्रतिबद्ध है। संपूर्ण रूप से, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण को एक अधिक समावेशी और समतामूलक समाज का सृजन करने के लिए कार्य कर रहे मंत्रालय की रेंज के साथ भारत के विकास सम्बन्धी एजेंडा के महत्त्वपूर्ण घटकों के रूप में देखा जाता है। एससी/एसटी और पीडब्लयूबीडी के प्रतिनिधित्व से संबंधित सूचना अनुबंध VIII(क) और VIII (ख) में दी गई है।

सामान्य अनुभाग :

15.12 ई-अधिप्रापणः निविदा की ई-अधिप्रापण और ई-प्रकाशन विधि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्ण रूप से प्रचलन में है। यदि जीईएम पर उपलब्ध नहीं है तो उत्पाद/सेवाओं के सभी प्राप्ति (लगभग 99%) जीईएम और सीपीपी पोर्टल के द्वारा की जा रही है ।

15.13 ई-ऑफिस परियोजनाः वर्तमान में, मंत्रालय ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म/परिवेश पर 100% कार्य कर रहा है और सभी चल रही फाईल ई-फाईल है। आगे, पुरानी फाइलों का डिजिटलीकरण पूरा हो गया है और सभी को इलेक्ट्रेनिक फाइलों में परिवर्तित कर दिया गया है। सरकारी प्रकिया और सेवा प्रदान करने के तंत्र की तत्परता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मॉड परियोजना में ई-ऑफिस परियोजना शामिल है ।

15.14 ऑनलाइन स्टेशनरी प्रबंधन प्रणालीः उपयोग, रिकॉर्ड और भावी आवयकताओं पर नजर रखने के लिए, सभी कर्मचारियों को स्टेशनरी ऑनलाइन स्टेशनरी प्रबंधन प्रणाली जरिए की जा रही है।

15.15 पीएफएमएसः सभी भुगतान सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रोनिक रूप में जारी किए जा रहे हैं और किसी भी विक्रेता या कर्मचारी को कोई नकद भुगतान नहीं किया जा रहा है।

15.16 ई-बिलिंग : भुगतान के लिए सभी ई-बिल लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली के ई-बिल मोड के माध्यम से संसाधित की जा रही है।

15.17 चिंतन शिविरः मंत्रालय सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार की तरफ लगातार काम कर रहा है। मंत्रालय के अंदर सुधार की आवश्यकताओं पर आंतरिक रूप से विचार-विमर्श करने और समयसीमा, कार्यान्वयन पद्धति तथा प्रदेय वस्तु के साथ कार्य बिन्दु के कार्यान्वयन के लिए रोडमैप की तैयारी हेतु चिंतन शिविर का संचालन किया गया था।

15.18 फिट इंडिया फ्रीडम रन 4.0 अभियानः फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन दो दिवसीय राष्ट्रीय महत्व, नामतः स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती को चिन्हित करने के लिए शुरु किया गया। इस संस्करण में बेहतर स्वास्थ्य और फिटनेस की तलाश में लोगों में चलने और दौड़ने की आदत को समझाने के लिए दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से 31 अक्टूबर, 2023 तक फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन, एक विशेष अभियान का संचालन किया गया। अभियान का उद्देश्य "फिट इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन के लिए था और अभियान का विषय "स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत" था। फिट इडिया स्वच्छता फ्रीडम रन के इस संस्करण में, फिटनेस के साथ स्वच्छता पर फोकस था।

15-19 स्वच्छ भारत/स्वच्छता अभियानः मंत्रालय स्वच्छ भारत मिशन पर निरंतर काम कर रहा है। हाल ही में मंत्रालय ने अपने कार्यालयों के अंदर स्वच्छता पर विशेष अभियान 3.0 का आयोजन किया। अभियान की शुरुआत 02 अक्तूबर, 2023 से हुई और 31 अक्तूबर, 2023 तक चली। स्थान प्रबंधन और कार्यालय में कार्यस्थल अनुभव में वृद्धि, स्वच्छता अभियान, रद्दी चीजों का निपटान तथा फाइलों को छांटने पर विशेष ध्यान दिया गया।

15.20 स्वच्छता पखवाड़ा, 2023: पेयजल और स्वच्छता विभाग के अनुसार इस मंत्रालय में स्वच्छता पखवाड़ा, 2023 दिनांक 1 जुलाई, 2023 से 15 जुलाई, 2023 तक मनाया गया। समन्वय अनुभाग ने देश भर में 177 क्षेत्रीय कार्यालय सहित सभी कार्यालयों की उत्साहपूर्ण भागीदारी के साथ सावधानीपूर्वक इस अभियान की योजना बनाई और उसका निष्पादन किया। 55,000 से अधिक लोगों ने कुल मिलाकर 738 गतिविधियों में व्यस्त होते हुए 153 शहरों में इस राष्ट्रव्यापी अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह एक शानदार सफलता थी।

15.21 स्वच्छता पखवाड़ा के दौरान, मंत्रालय के अंतर्गत सभी कर्यालयों ने गतिविधियों की रेंज में व्यस्त रहते हुए सराहनीय प्रतिबद्धता दर्शायी। विशेषतः एएस मुख्यालय, फरीदाबाद; एफओडी मुख्यालय, दिल्ली; डीआईआईडी; डीक्यूएडी/ एसडीआरडी; आईएसआई और अन्य ने पूरे पखवाड़े भर गतिविधियों का संचालन किया। शेष अधिकारियों ने भी स्वच्छ भारत अभियान की सफलता में महत्त्वपूर्ण योगदान देते हुए, बड़े जोश के साथ नियोजित/नामित गतिविधियाँ शुरू की। पूरे पखवाड़े की गतिविधियों में कार्यस्थल की सफाई, अस्पताल, पार्क, नदी, तालाब, समुद्र तट जैसे सार्वजनिक स्थानों की सफाई की गई, स्वच्छता रैली का आयोजन किया, वृक्षारोपन किया गया, पेंटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, प्रश्नोत्तरी का संचालन किया, दीवार को चित्रों से सजाया गया, आदि गतिविधियां पूरी की गई और कार्यालय क्षेत्र की सफाई का काम पूरा किया गया।

15.22 मंत्रालय ने अधिकतम आउटरीच और लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किया। ट्वीटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रभावी प्रयोग के माध्यम से इस अभियान ने सार्वजनिक रूप से व्यापक तौर पर ध्यान आकर्षित किया और सराहना प्राप्त किया।

सां और कार्य. कार्या. मंत्रा. का संगठनात्मक चार्ट

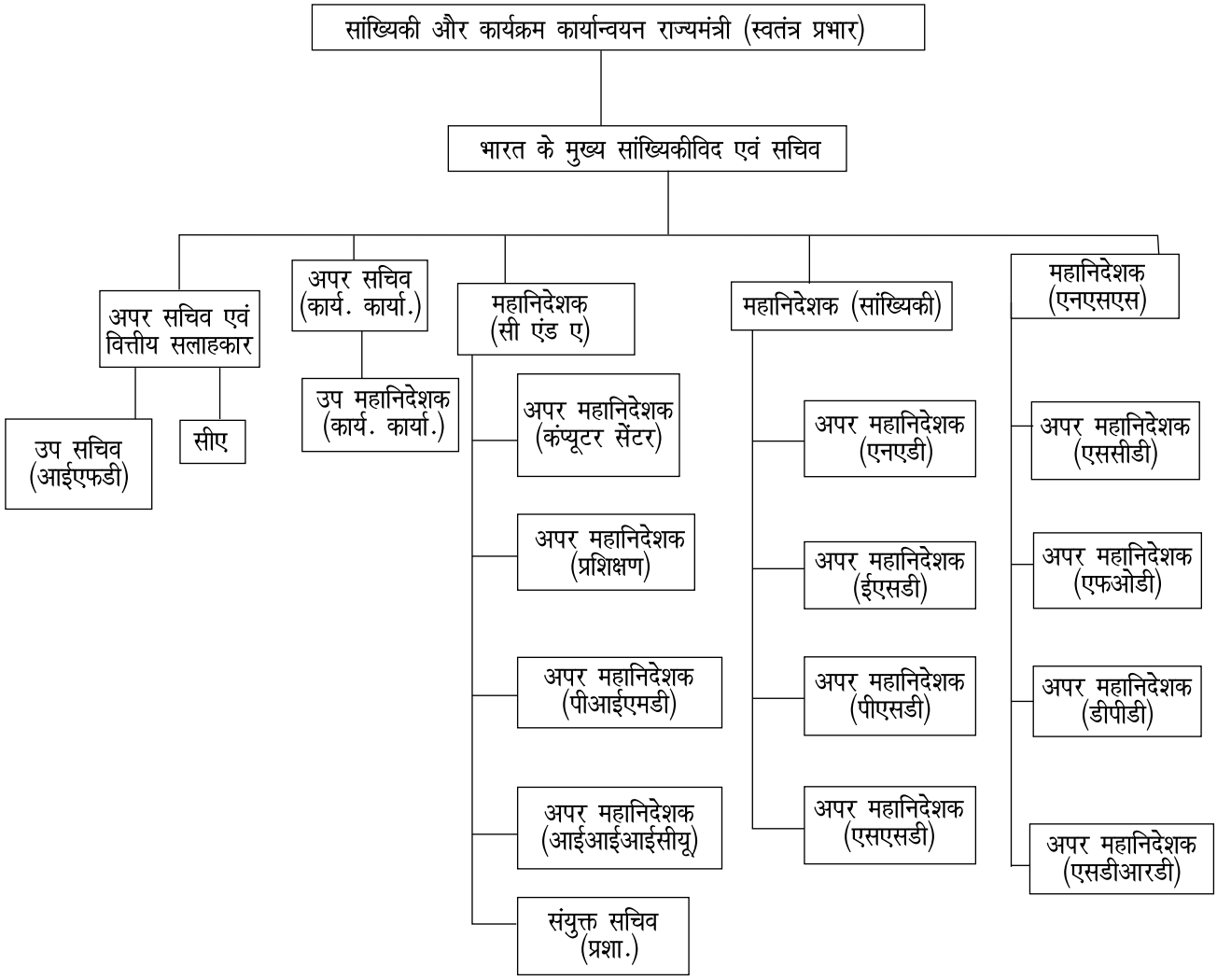

संगठनात्मक चार्ट

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

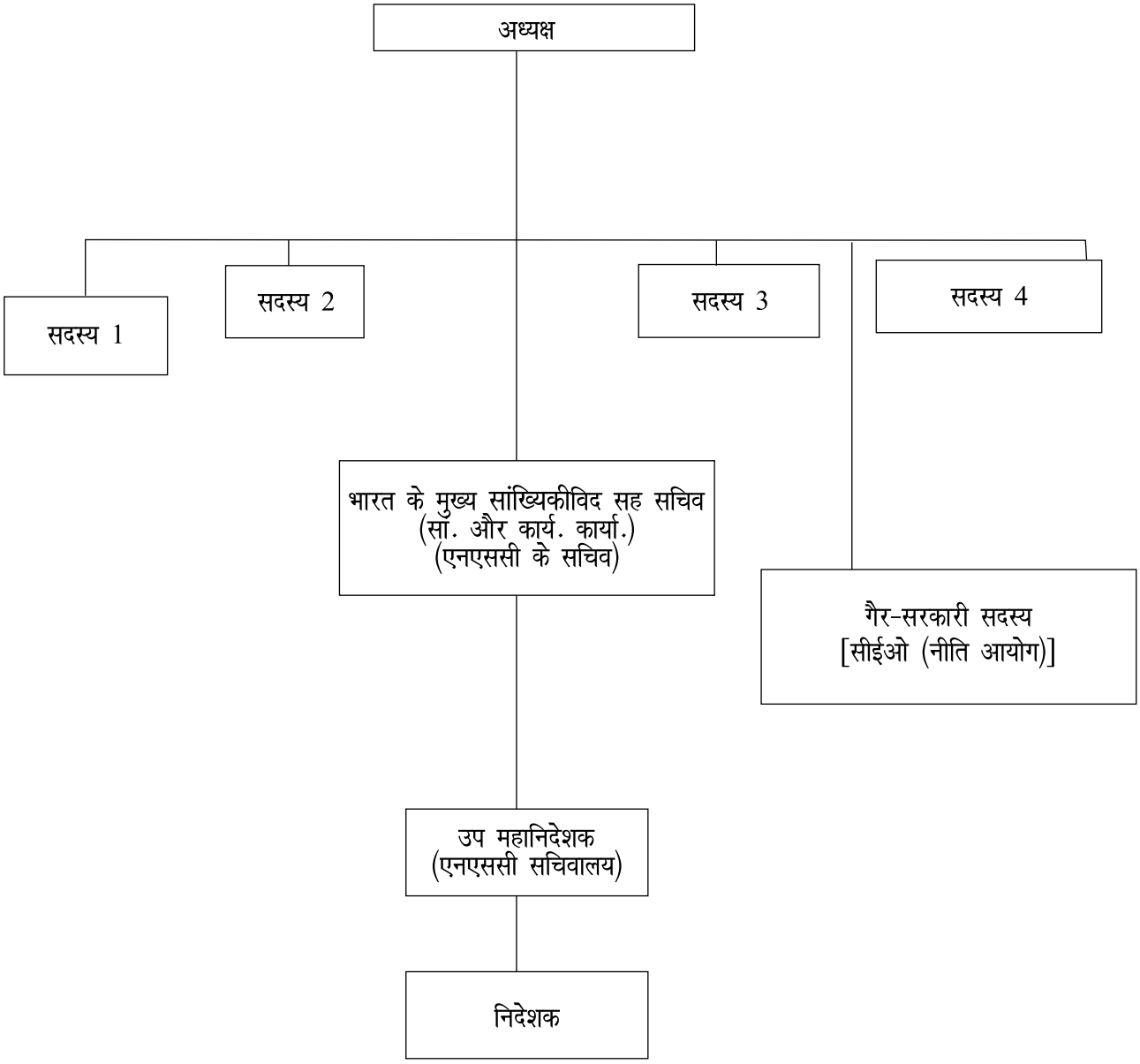

एनएससीः राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

प्रयुक्त संक्षिप्तियां

एएस व एफए	अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार
एएसआई	वार्षिक औद्योगिक सर्वेकक्षण
एएसटीटी. डीआईआर	सहायक निदेशक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीपीडी	समन्वय और प्रकाशन प्रभाग
सी एंड ए	समन्वय और प्रशासन
कॉर्ड.	समन्वय
म. नि. सीईओ	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
डीआईआर	निदेशक
डीडीजी	उप महानिदेशक
डीओ	डेस्क अधिकारी
डीपीडी	समंक विधायन प्रभाग
उ. स.	उप सचिव
उप. सचिव.	उप सचिव
उप. सलाह.	उप सलाहकार
उप. ले. नि.	उप लेखा नियंत्रक
उप. नि.	उप निदेशक
उप. वि. सलाह.	उप वित्तीय सलाहकार
ईएसडी	आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग
एफओडी	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
एचओडी	विभागाध्यक्ष
एचओओ	कार्यालयाध्यक्ष
सं. सलाह.	संयुक्त सलाहकार
सं. नि.	संयुक्त निदेशक
जेसीएम	संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी
सं. नि.	संयुक्त निदेशक

आईसीटी	अंतरराष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण
आईपीएमडी	अवसंरचना और परियोजना निगरानी प्रभाग
आईएसडी	औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग
आईएसआई	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
आईएसएस	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
आईएस विंग	औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध
आईडब्ल्यूएसयू	आंतरिक कार्य अध्ययन इकाई
एमडीजी	सहस्राब्दी विकास लक्ष्य
एमपीलैड्स	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
एनएडी	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीएमपी	राष्ट्रीय न्यूनतम कार्यक्रम आयोग
एनएससी	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
एनएसओ	राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
ओएल.	राजभाषा
ओ एंड एम	संगठन और पद्धति
पीएओ	भुगतान और लेखा कार्यालय
पीसीएल	मूल्य और जीवनयापन लागत
पीजी	लोक शिकायत
पीआईएमडी	नीति कार्यान्वयन और निगरानी प्रभाग
आरटीआई	सूचना का अधिकार
एससीडी	सर्वेक्षण समन्वय प्रभाग
एससी/एसटी	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति
एसडीआरडी	सर्वेक्षण अभिकल्प और अनुसंधान प्रभाग
एसएसडी	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
एसएसएस	अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा
एसडीजी	सतत विकास लक्ष्य
प्रशि.	प्रशिक्षण
उ.स.	अवर सचिव

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आवंटित कार्य

I सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास की योजना बनाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वयन करना ताकि आंकड़ा अन्तरालों तथा सांख्यिकीय कार्य में दोहरीकरण की पहचान की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाना।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदण्ड और मानक बनाना और उनका अनुरक्षण, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणाएं, परिभाषाएं और कार्य प्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रचार-प्रसार।

4. सांख्यिकीय कार्य प्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना।

5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अन्तिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा स्थिर पूंजी उपभोग, सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान तैयार करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिका तैयार करना, घरेलू उत्पाद एवं अधि-क्षेत्रीय क्षेत्रों के स्थाई पूंजी निर्माण के राज्य स्तरीय अनुमान तैयार करना।

6. त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन एवं उन्हें जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना ताकि संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) क्षेत्र के विकास, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन हो सके।

7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्य प्रणाली और अवधारणाओं का विकास तथा भारत का राष्ट्रीय संसाधन लेखा तैयार करना।

8. अखिल भारतीय आर्थिक गणना तथा अनुवर्ती प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आवधिक आयोजन व संचालन।

9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति, ऋण एवं निवेश, भूमि एवं पशुधन होल्डिंग, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माणकारी एवं सेवाओं आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन ताकि विकास, अनुसंधान, नीति-निर्माण एवं आर्थिक आयोजन हेतु अपेक्षित आंकड़ा आधार प्रदान किया जा सके।

10. तकनीकी संवीक्षा एवं प्रतिदर्श जांचों के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की गुणवत्ता जांच एवं लेखा परीक्षा का आयोजन तथा, यदि आवश्यक हो तो, शुद्धिकारक और वैकल्पिक अनुमान तैयार करना।

11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों और आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से संग्रहित सर्वेक्षण-आंकड़ों का संसाधन करना।

12. अनेक नियमित अथवा तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/अभिकरणों को सांख्यिकीय सूचना का प्रचार-प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, एशिया एवं प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अनुरोध पर आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना।

13. पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान देना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण करना।

14. प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर कार्य करना और संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।
15. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार भारतीय सांख्यिकी संस्थान का कार्यपालन सुनिश्चित करना।
16. शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और प्रकाशन करना।
17. लघुक्षेत्र-अनुमानों सहित बेहतर प्रतिचयन तकनीकें और आकलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए कार्य प्रणालीगत अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना।

II कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. देश के ग्यारह मुख्य अवसंरचना क्षेत्रों अर्थात विद्युत, कोयला, स्टील, रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरकों, सीमेंट, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, रोड और नागरिक उड्डयन के निष्पादन की निगरानी;
19. ₹150 करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत वाली सभी केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाओं की निगरानी करना; और
20. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

अनुलग्नक–III क

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 (बीई एवं आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	योजना	वार्षिक योजना 2023-24 (बीई)			पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित परिव्यय 2023-24 (बीई)
		जीबीएस	आईईबीआर	कुल	
1	2	3	4	5	6
(ए) केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं (सीएस)					
1	विकास क्षमता	600.00	0	600.00	18.19
	कुल (ए)	600.00	0	600.00	18.19
(बी) ब्लॉक अनुदान					
1	सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)	3958.50	0	3958.50	0
600.00	कुल (ए+बी)	4558.50	0	4558.50	18.19

अनुलग्नक–III ख

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2022-23 (बीई एवं आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ लाख में)

योजना का नाम	2022-23 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान			पूर्वोत्तर राज्य	राज्यवार वास्तविक व्यय	टिप्पणी
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय			
1	2	3	4	5	6	7
1- क्षमता विकास (कुल)	4307.00	2259.00	2199.88		2199.88	
(क) क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को अनुदान सहायता)	2200.00	2234.00	2199.88	अरुणाचल प्रदेश	371.25	
				असम	455.10	
				मणिपुर	230.73	
				मेघालय	248.21	
				मिजोरम	135.50	
				नगालैंड	238.84	
				सिक्किम	127.61	
				त्रिपुरा	392.64	
(ख) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	2107.00	25.00	0.00			
(ग) आर्थिक जनगणना						
2. एमपीलैड्स			1695.00	अरुणाचल प्रदेश	700.00	
				असम	9050.00	
				मणिपुर	1600.00	
				मेघालय	950.00	
				मिजोरम	750.00	
				नगालैंड	1000.00	
				सिक्किम	450.00	
				त्रिपुरा	2450.00	
कुल योग	4307.00	2259.00	19149.88			

पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए वर्ष 2023-24 (बीई एवं आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

(₹ रुपए लाख में)

योजना का नाम	2023-24 के दौरान पूर्वोत्तर के लिए प्रावधान			पूर्वोत्तर राज्य	राज्यवार वास्तविक व्यय	टिप्पणी
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय (31.03.2024 तक)			
1	2	3	4	5	6	7
1- क्षमता विकास (कुल)	1819.00	1819.00	1705.40			
(क) क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को अनुदान सहायता)	1534.00	1534.00	1533.96	अरुणाचल प्रदेश	401.26	
				मणिपुर	540.28	
				मिजोरम	194.27	
				सिक्किम	74.55	
				त्रिपुरा	323.60	
				नगालैंड	92.75	
				अरुणाचल प्रदेश	35.00	
				असम	43.69	
(ख) सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता	285.00	285.00	171.44			
(ग) आर्थिक जनगणना						
2. एमपीलैड्स			29455.3	अरुणाचल प्रदेश	2500.00	
				असम	16000.00	
				मणिपुर	2505.11	
				मेघालय	2250.00	
				मिजोरम	1250.00	
				नगालैंड	1000.19	
				सिक्किम	1750.00	
				त्रिपुरा	2200.00	
कुल योग	1819.00	1819.00	31160.70			

मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी प्रकाशन

क. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

1	अक्टूबर-दिसंबर, 2022 तिमाही हेतु पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन, फरवरी, 2023 में जारी
2	पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई, 2021-जून, 2022, फरवरी, 2023 में जारी
3	भारत में बहु-संकेतक सर्वेक्षण पर 78वें दौर की एनएसएस रिपोर्ट संख्या 589, मार्च, 2023 में जारी
4	जनवरी-मार्च 2023 तिमाही के लिए पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन, मई 2023 में जारी
5	पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट जुलाई, 2022-जून, 2023, अक्टूबर, 2023 में जारी
6	पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन के लिए तिमाही अप्रैल-जून, 2023 जारी किया में अक्टूबर, 2023 में जारी
7	जुलाई-सितंबर, 2023 तिमाही के लिए पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन, नवंबर, 2023 में जारी
8	पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट प्रतिवेदन 2022-23 की अतिरिक्त सारणियाँ, जनवरी, 2024 में जारी
9	अक्टूबर-दिसंबर, 2023 तिमाही के लिए पीएलएफएस त्रैमासिक बुलेटिन, फरवरी, 2024 में जारी
10	एचसीईएस 2022-23 का तथ्य-पत्रक, फरवरी, 2024 में जारी
11	जनवरी-दिसंबर, 2023 के लिए प्रमुख रोजगार बेरोजगारी संकेतक, मार्च, 2024 में जारी
12	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2020-21, फरवरी 2024 में जारी
13	वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) 2021-22 फरवरी 2024 में जारी

ख. सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा वर्ष 2023-24 के दौरान जारी प्रकाशन :

क्रम सं.	प्रकाशन का नाम	आवधिकता	प्रकाशन माह	सामग्री
1.	एन्वीस्टैट्स इंडिया 2023; खंड I : पर्यावरण सांख्यिकी	वार्षिक	मार्च 2023	पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सांख्यिकीय जानकारी एकत्र करने और जारी करने के अपने प्रयास को जारी रखते हुए, प्रभाग ने मार्च 2023 में "एनविस्टेट्स इंडिया 2023 खंड-I पर्यावरण सांख्यिकी" जारी किया। यह प्रकाशन पर्यावरण सांख्यिकी के संकलन के लिए यूएनएसडी द्वारा निर्धारित पर्यावरण सांख्यिकी के विकास पर फ्रेमवर्क (एफडीईएस 2013) पर आधारित है और छह मूलभूत घटकों अर्थात् (i) पर्यावरण की स्थिति और गुणवत्ताय (ii) पर्यावरण संसाधन और उनका उपयोग; (iii) अवशेष (iv) चरम घटनाएं और आपदाएंय (v) मानव बस्तियां और पर्यावरणीय स्वास्थ्य; और (vi) पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और जुड़ाव पर जानकारी प्रदान करता है। यह प्रकाशन श्रृंखला का छठा प्रकाशन है। नवीनतम प्रकाशन में एफडीईएस द्वारा निर्धारित संकेतकों का बेहतर कवरेज है, जिसमें फ्रेमवर्क के 177 संकेतकों पर जानकारी प्रदान की गई है
2.	एन्वीस्टैट्स इंडिया 2023; खंड II : पर्यावरण सांख्यिकी	वार्षिक	सिंतम्बर 2023	पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों की समझ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्रभाग ने पर्यावरण-आर्थिक लेखा ढांचे (एसईईए) की प्रणाली का पालन करते हुए सितंबर 2023 में पर्यावरण खातों पर वार्षिक प्रकाशन, "एनवीस्टेट्स इंडिया 2023 खंड-II पर्यावरण खाते" का लगातार छठा अंक जारी किया है। वर्तमान प्रकाशन में कई नए विषय शामिल हैं जैसे कि सामग्री प्रवाह खाते और वनों द्वारा मृदा क्षरण रोकथाम सेवाएँ और साथ ही पहले जारी किए गए ठोस अपशिष्ट खाते, मछली प्रावधान सेवाएँ आदि का अद्यतन डाटा।

3.	एन्वीस्टैट्स इंडिया एक्सप्लेनर सीरीज		मई 2023	एनएसओ, भारत ने मई, 2023 में फसल भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली मृदा अपरदन रोकथाम सेवाओं पर व्याख्यात्मक श्रृंखला जारी की। दस्तावेज में विशेष रूप से भौतिक मात्रा में फसल भूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं (नियामक) के बारे में विस्तार से बताया गया है।
4.	एन्वीस्टैट्स इंडियाः अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न		जनवरी 2024	एफएक्यू में पर्यावरण लेखांकन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, जिसका उद्देश्य एनविस्टेट्स इंडिया के उपयोगकर्ताओं को पर्यावरण लेखांकन की विभिन्न अवधारणाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना तथा इसके प्रति जागरूकता पैदा करना है।
5.	एन्वीस्टैट्स इंडियाः शब्दावली		मार्च 2024	शब्दावली में पर्यावरण लेखा में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों की परिभाषा दी गई है।
6.	सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट, 2023	वार्षिक	जून 2023	"सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क प्रगति रिपोर्ट 2023", एसडीजी-एनआईएफ (सभी 17 एसडीजी को कवर करते हुए) पर भारत की नवीनतम प्रगति रिपोर्ट समय श्रृंखला डेटा के साथ 29 जून, 2023 को जारी की गई थी। इस रिपोर्ट में चार भाग हैं - अवलोकन और कार्यकारी सारांश, डेटा स्नैपशॉट, मेटाडेटा और डेटा टेबल।
7.	सतत विकास लक्ष्य - राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा, 2023	वार्षिक	जून 2023	राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ), 2023 पर इस प्रकाशन में 17 एसडीजी, संबंधित 169 लक्ष्य और 284 राष्ट्रीय संकेतकों की सूची शामिल है।
8.	सतत विकास लक्ष्य राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा प्रगति रिपोर्ट 2023 पर डेटा स्नैपशॉट	वार्षिक	जून 2023	यह स्नैपशॉट राष्ट्रीय संकेतकों के राष्ट्रीय स्तर के मूल्यों पर आधारित है, जिसमें डेटा स्रोतों का समुचित उल्लेख किया गया है।
9.	भारत में महिलाएँ और पुरुष 2022	वार्षिक	मार्च 2023	स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेने, महिला सशक्तिकरण में बाधाएं आदि सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर लिंग आधारित आंकड़े।

ग. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग

क्र. सं.	प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण	प्रकाशन पद्धति
1	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी – 2023	ई-प्रकाशन
2	आपूर्ति और उपयोग तालिका (एसयूटी) 2019-20	ई-प्रकाशन
3	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2022-23 के अनंतिम अनुमान और 2022-23 की चौथी तिमाही (क्यू4) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	प्रेस नोट
4	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन से उत्पादन का राज्यवार और मदवार मूल्य (2011-12 से 2020-21)	ई-प्रकाशन
5	2023-24 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान	प्रेस नोट
6	2023-24 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान	प्रेस नोट
7	वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अग्रिम अनुमान (एफएई)	प्रेस नोट
8	राष्ट्रीय आय, 2023-24 के दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई); 2023-24 की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही (क्यू3) के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान इसके व्यय घटकों के साथ और राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2022-23 के पहले संशोधित अनुमान	प्रेस नोट
9	भारत में पे-रोल रिपोर्टिंगः एक रोजगार परिप्रेक्ष्य' (मासिक प्रेस नोट)	प्रेस नोट

*प्रत्येक माह की 25 तारीख को जारी, यदि 25 तारीख को अवकाश हो तो उस से पहले कार्यदिवस को जारी ।

वर्ष 2022-23 के लिए की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

क्र. सं	वर्ष	अनुच्छेदों/पीए रिपोर्टों की संख्या जिनपर लेखा पुनरीक्षण के पश्चात एटीएन जमा की गई हैं	उन अनुच्छेदा/पीए रिपोर्टों का विवरण जिनपर एटीएन लंबित हैं		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा भेजा ही नहीं गया है	उन एटीएन की संख्या जो भेजे गए लेकिन टिप्पणी के साथ लौटा दिए गए और मंत्रालय द्वारा लेखा को पुनः भेजे जाने हैं	उन एटीएन की संख्या जिनका पुनरीक्षण लेखा द्वारा कर लिया गया है लेकिन मंत्रालय द्वारा पीएसी को नहीं भेजे गए हैं
1	एमपीलैड्स के बारे में पीएसी रिपोर्ट सं. 31 (12 अनुच्छेदों में)	सभी 12 अनुच्छेदों की फाइनल एक्शन टेकन (एटीआर) एपीएमएस पोर्टल पर अपलोड कर दी गई हैं।	शून्य	शून्य	शून्य

1 जनवरी 2024 तक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व और पूर्ववर्ती कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों का प्रतिनिधित्व (01/01/2024 तक)						कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या														
							सीधी भर्ती द्वारा						पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा				
	कुल कर्मचारी	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	ईडब्ल्यूएस	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
ए	778	126	51	174	21	406	27	4	2	11	4	6	143	37	11	95	0	0	0	0	0
बी	3957	606	296	957	184	1914	498	86	47	81	35	249	158	24	14	120	0	0	0	0	0
सी (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	724	130	57	183	7	347	30	1	2	7	1	19	15	2	0	१३	0	0	0	0	0
सी (सफाई कर्मचारी)	1	1	0	0	0	0	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	5460	863	404	1314	212	2667	555	91	51	99	40	274	316	63	25	228	0	0	0	0	0

1 जनवरी 2024 तक सेवाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व को दर्शाने वाला वार्षिक विवरण

समूह	दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व (01/01/2024 तक)					कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या												
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा				प्रतिनियुक्ति द्वारा			
	कुल कर्मचारी	ए	बी	सी	डी तथा ई	कुल	ए	बी	सी	डी तथा ई	कुल	ए	बी	सी	कुल	ए	बी	सी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
ए	778	3	2	8	0	27	0	0	1	0	143	0	1	2	0	0	0	0
बी	3957	18	17	25	0	498	1	0	0	0	158	0	0	0	0	0	0	0
सी (सफाई कर्मचारी को छोड़कर)	724	3	0	1	0	30	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
सी (सफाई कर्मचारी)	1	0	0	0	0	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना	ना
कुल	5460	24	19	34	0	555	1	0	1	0	316	0	1	2	0	0	0	0

कैलेंडर वर्ष 2023 के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या में प्रयुक्त संक्षिप्ताक्षर
'ए (अंधापन और कम दृष्टि)'
'बी (बहरा और कम सुनने वाला)'

'सी (मस्तिष्क पक्षाघात, ठीक किया गया कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मांसपेशीय दुर्विकास सहित गतिजन्य विकलांगता)'
'डी एंड ई (डीः ऑटिज्म, बौद्धिक विकलांगता, विशिष्ट सीखने की विकलांगता और मानसिक बीमारी और ईः ए से डी तक कई विकलांगताएं जिनमें बहरापन-अंधापन भी शामिल है)'

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

www.mospi.gov.in @GoIStats